राष्ट्रीय संस्करण

युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को बर्बाद कर देगी उप्र सरकार >> 5

दैनिक जागरण

वर्ष 7 अंक 277
मूल्य ₹8.00 नई दिल्ली, शुक्रवार, 15 मार्च, 2024
www.jagran.com
पृष्ठ 14

जागरण विशेष — कर्मठ किसान

जहां थी पलायन की मार, वहां नवाचार से आई बहार

उत्तरकाशी: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन सभी को चिंतित करता है। ऐसे में जगमोहन राणा ने दिखाया कि अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती के साथ नवाचार भी करें तो रोजगार की राह निकल आती है। (पेज-7)

संपादकीय

और अधिक सक्षम होती अर्थव्यवस्था: जिस रफ्तार से भारत वृद्धि कर रहा है, उसे देखते हुए 2030 के आसपास तक देश सात ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। **धर्मकीर्ति जोशी** का दृष्टिकोण।

रेवड़ी संस्कृति को रोकने का समय: मुफ्त की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना ही छोड़ देते हैं। **आरके सिन्हा** की टिप्पणी। पेज 8

विमर्श

युवा दुनिया पर भारी पड़ता नींद का संकट: इंटरनेट मीडिया, कामकाज की शैलियों में बदलाव और बदलती जीवनशैली के कारण खासकर युवाओं में नींद का गंभीर संकट पैदा हो गया है। इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। **डा. संजय वर्मा** का आकलन।

शक्ति संतुलन का दिव्यास्त्र: चीन से मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर एमआइआरवी तकनीक से लैस अग्नि-5 जैसी मिसाइल की कमी को हमारा रक्षातंत्र लंबे समय से महसूस कर रहा था। **अभिषेक कुमार सिंह** का विश्लेषण। पेज-9

दैनिक जागरण सप्तरंग — मनोरंजन की दुनिया का

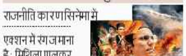

राजनीति कारण सिनेमा में

एक्शन में रंग जमाना है : मिथिला पालकर पेज-13

देशविरोधी एजेंडे को बढ़ावा इंडी गठबंधन की विचारधारा : मोदी

- प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि के लाभार्थियों को किया संबोधित
- कहा, रेहड़ी-पटरी वालों की दुकान छोटी, पर सपने बड़े होते हैं

नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएम स्वनिधि लाभार्थियों को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। ध्रुव कुमार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष के हमलों का करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा, मोदी गरीब और मध्य वर्गीय परिवार के जीवन को बेहतर करने में जुटा है। वहीं, इंडी गठबंधन मोदी को गालियां देने के घोषणापत्र के साथ दिल्ली में एक हो गया है। उसकी विचारधारा कुशासन की, करप्शन की और देशविरोधी एजेंडे को हवा देने की है। मोदी की विचारधारा है जन कल्याण से राष्ट्र कल्याण की, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को जड़ से मिटाने की और भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की। ये (गठबंधन के नेता) कहते हैं कि मोदी का परिवार नहीं है। मोदी के लिए तो देश का हर परिवार अपना परिवार है, इसलिए पूरा देश कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार।

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम ने मेट्रो के चौथे चरण के अंतर्गत लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कारिडोर का शिलान्यास किया। उन्होंने मंच पर पांच लोगों को स्वनिधि योजना के चेक देकर दिल्ली के पांच हजार लाभार्थियों के साथ ही देश में एक लाख रेहड़ी-पटरी वालों को ऋण वितरण की शुरुआत की। लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने गरीबों के साथ ही मध्य वर्ग के हित में किए गए कार्यों को गिनाया। मोदी ने कहा, रेहड़ी-पटरी वालों की दुकान छोटी होती है, लेकिन सपने छोटे नहीं होते। इनके सपने भी बड़े होते हैं, परंतु उसे पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते। पहले कारोबार बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता होने पर अधिक ब्याज पर ऋण लेना पड़ता था और लौटाने में कुछ घंटों का विलंब होने पर अपमान के साथ अधिक पैसे लौटाने पड़ते थे। बैंक खाता न होने और कारोबार के रिकार्ड के अभाव में बैंक ऋण नहीं मिलता था। पूर्व की सरकारों ने इनकी समस्या दूर करने की कोशिश नहीं की। आपका यह सेवक गरीबी से बाहर आया है, इसलिए जिनको किसी ने नहीं पूछा मोदी ने उनकी चिंता करने के साथ पूजा भी की। जिनके पास जमानत के तौर पर गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था, उन्हें मोदी की गारंटी का आश्वासन दिया गया। अब उन्हें सस्ता बैंक ऋण मिल रहा है। अब तक 62 लाख से अधिक लाभार्थियों को 11 हजार करोड़ रुपये की मदद मिल चुकी है। लाभार्थियों में आधे से अधिक महिलाएं हैं।

एक अध्ययन के अनुसार, इस योजना के कारण स्ट्रीट वेंडरों की आय कई गुना बढ़ गई है। यह अध्ययन योजना के आलोचकों की आंखें खोलने वाला है। योजना का लाभ उठाने वालों को निश्शुल्क राशन, निश्शुल्क उपचार और निश्शुल्क गैस कनेक्शन का भी लाभ मिलता है। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना से अब लोग किसी भी शहर में सरकारी राशन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चार करोड़ पक्के घर में से एक करोड़ शहरी गरीबों को आवंटित किए गए हैं।

दिल्ली में तीन हजार झुग्गी वालों को दिए घर : मोदी पेज>>2

चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया चुनावी बांडों का ब्योरा

नई दिल्ली : चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावी बांडों से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक ने 12 मार्च को यह ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा था। कोर्ट ने आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस ब्योरे को 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपलोड करने को कहा था। चुनाव आयोग ने ब्योरे को दो भागों में वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। (पेज-3)

साथ नहीं देने वाले दलों का चुनाव में बहिष्कार करेंगे किसान

नई दिल्ली : एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में किसान संगठनों ने कहा कि मांगों का समर्थन नहीं करने वाले दलों का आगामी आम चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, उनका देश के विभिन्न स्थानों पर आंदोलन जारी रहेगा। (पेज-7)

दो चरणों में एक साथ चुनाव की सिफारिश

कोविन्द समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट, कहा- पहले चरण में हों लोकसभा व विधानसभा चुनाव

दूसरे चरण में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव

पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को एक देश एक चुनाव पर रिपोर्ट सौंपी। एएनआइ

एक देश-एक चुनाव

- 18,626 पृष्ठों की रिपोर्ट में कहा, दूसरे चरण में लोकसभा व विधानसभा चुनाव के सौ दिन के भीतर हों निकाय व पंचायत चुनाव
- भारत निर्वाचन आयोग व राज्य आयोगों के परामर्श से एकल मतदाता सूची व मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार हों
- सदन समयपूर्व भंग होने पर हो सकेंगे नए सिरे से चुनाव, लेकिन कार्यकाल बाकी बची अवधि का होगा

पहली बार के लिए ये हैं सिफारिशें

- एक साथ चुनावों के चक्र को बहाल करने को सरकार तंत्र विकसित करे।
- लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के लिए राष्ट्रपति आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को 'नियत तिथि' के रूप में अधिसूचित करेंगे।
- 'नियत तिथि' के बाद और लोस का कार्यकाल समाप्त होने से पहले चुनाव के जरिये गठित सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले संसदीय चुनाव तक की अवधि का होगा।

यह देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। एक देश-एक चुनाव पर राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में मोदी सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति ने आज अपनी रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति को सौंप दी। - **अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री व समिति के सदस्य**

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक देश-एक चुनाव को लेकर गठित पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अगुआई वाली उच्च स्तरीय कमेटी ने देश में लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने की सिफारिश की है। कमेटी ने गठन के 191 दिनों के भीतर दी गई अपनी सिफारिशों में इसे दो चरणों में पूरा करने का सुझाव दिया है। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है, जबकि दूसरे चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनावों के सौ दिनों के भीतर ही नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। कोविन्द ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कमेटी के सभी सदस्यों के साथ जाकर 18,626 पृष्ठों की अपनी विस्तृत रिपोर्ट गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को सौंप दी।

कोविन्द कमेटी ने इसके साथ ही त्रिशंकु सदन, अविश्वास प्रस्ताव या फिर ऐसी किसी स्थिति में नए सदन के गठन के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की सिफारिश तो की है, लेकिन ऐसी स्थिति में नई लोकसभा का कार्यकाल बची अवधि के लिए ही होगा। यानी चुनाव के बाद गठित सरकार यदि एक वर्ष के बाद किसी कारण से गिर जाए और दूसरा कोई दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है तो नए सिरे से चुनाव हो सकते हैं। लेकिन इस दौरान नए सदन का गठन बाकी बचे चार वर्षों के लिए ही होगा। मौजूदा व्यवस्था में बीच में चुनाव की नौबत आने के बाद सदन का कार्यकाल फिर पांच वर्षों का हो जाता है। इस कारण ही आजादी के बाद लोकसभा और विधानसभाओं के साथ शुरू हुए चुनाव आज अलग-अलग वर्षों में हो रहे हैं। कमेटी ने संविधान के अनुच्छेद-83 (संसद की अवधि) और अनुच्छेद-172 (राज्य विधानसभा की अवधि) में जरूरी संशोधनों की सिफारिश भी की है।

कमेटी ने देश में एक वोटर लिस्ट बनाने की सिफारिश भी की है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद-325 में जरूरी संशोधन करने का कहा है। कमेटी ने इसके लिए राज्यों के समर्थन की जरूरत बताई है। कोविन्द की अगुआई वाली इस उच्चस्तरीय कमेटी में वैसे तो सात सदस्य थे, लेकिन कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे के बाद कमेटी में छह सदस्य रह गए थे। इनमें गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डा. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया गया था।

बार-बार चुनाव से नीतिगत निर्णयों पर पड़ता है असर : कोविन्द समिति पेज>>7

कभी वापस नहीं लिया जाएगा सीएए : शाह

- गृह मंत्री बोले- नागरिकता संशोधन कानून शरणार्थियों की 75 साल की वेदना का अंत
- विपक्षी दलों पर लगाया वोटबैंक की राजनीति के लिए विरोध करने का आरोप
- नागरिकता कानून केंद्र का विषय, राज्यों का विरोध बेवुनियाद

नई दिल्ली में गुरुवार को एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान गृह मंत्री अमित शाह। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को भाजपा के लिए वोटबैंक नहीं, बल्कि भावनात्मक मुद्दा बताते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस कानून से किसी भी भारतीय मुसलमान की नागरिकता नहीं जाएगी, इसमें ऐसा कोई प्रविधान ही नहीं। यह तो सिर्फ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रताड़ित होने के कारण भारत में आए लोगों के लिए है। सीएए के कभी वापस नहीं लिए जाने का दावा करते हुए शाह ने साफ किया कि आगामी लोकसभा चुनाव में न तो विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए सत्ता में आने वाला है और न ही सीएए जाने वाला है। उन्होंने इस मुद्दे पर विपक्ष पर वोटबैंक के लिए झूठ की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वह इसके भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध होने का साक्ष्य तो दें।

एक न्यूज एजेंसी को दिए पोडकास्ट में कहा कि अखंड भारत के हिस्से में जिन लोगों के साथ प्रताड़ना हुई है, उनको शरण देना हमारी संवैधानिक और नैतिक जिम्मेदारी है। मोदी सरकार ने शरणार्थियों की 75 साल की वेदना का अंत किया है।

अब तो सीएए को सिर्फ अधिसूचित किया गया पेज>>6

आपा खो चुके हैं केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सीएए लागू होने के बाद अपराध बढ़ने की आशंका के बारे में शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद केजरीवाल अपना आपा खो चुके हैं। सीएए में साफ है कि सिर्फ 31 मार्च 2014 तक आने वाले शरणार्थियों को ही नागरिकता दी जाएगी। आखिरकार वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं। आने वाला दिल्ली का चुनाव केजरीवाल के लिए लोहे के चने चबाने जैसा होगा।

पेट्रोल-डीजल की कीमत में दो रुपये की कटौती

शुक्रवार सुबह छह बजे से लागू होंगी नई कीमतें

22 मई, 2022 के बाद हुआ कीमतों में बदलाव

पेट्रोल के दाम		
शहर	पहले	अब
दिल्ली	96.72	94.72
मुंबई	106.31	104.21
कोलकाता	106.30	103.94
चेन्नई	102.63	100.75

डीजल के दाम		
शहर	पहले	अब
दिल्ली	89.62	87.62
मुंबई	94.27	92.15
कोलकाता	92.76	90.76
चेन्नई	94.24	92.34

(नोट : राज्यवार पेट्रोल-डीजल की कीमत अलग-अलग हो सकती है)

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सरकार ने आम चुनाव के एलान के ठीक पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की कमी की है। यह कटौती आज यानी शुक्रवार सुबह छह बजे से लागू होगी। इस कटौती के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पेट्रोल की खुदरा कीमत 94.72 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.62 रुपये प्रति लीटर होगी। 22 मई, 2022 के बाद पेट्रोल व डीजल की खुदरा कीमतों में पहली बार बदलाव किया गया है। उस समय केंद्र सरकार ने इन दोनों पर लागू उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती की थी।

सरकार ने पेट्रोल व डीजल की कीमतें तय करने का अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को दे रखा है लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्थिति असामान्य होती है तो फैसला केंद्र सरकार की सलाह के बाद ही होता है। इस बार पेट्रोल व डीजल को सस्ता करने की घोषणा भी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से ही की गई है। मई, 2022 के बाद के आंकड़ों को देखें तो साफ हो जाता है कि सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल की कीमत तय करने में पारदर्शिता नहीं बरती है। इससे पहले गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत दिए गए गैस कनेक्शन के तहत साल में 12 एलपीजी सिलेंडर देने की योजना को मार्च, 2025 तक जारी रखने का फैसला किया गया। बाद में पीएम मोदी ने सिलेंडर के दाम में 100 रुपये की कमी करने का एलान किया था।

ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू होंगे नए चुनाव आयुक्त

- पीएम की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने उनके नामों को दी मंजूरी
- समिति में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने जताई असहमति

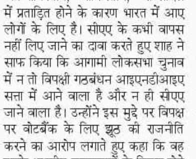

ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू। एएनआइ

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले निर्वाचन आयोग में आयुक्तों के खाली पड़े दोनों पदों पर वरिष्ठ अधिकारी ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू की नियुक्ति कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुआई वाली चयन समिति ने गुरुवार को इनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी। हालांकि, चयन समिति में शामिल कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इनकी नियुक्ति पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। आयोग में दोनों पद हाल ही में अरुण गोयल के इस्तीफा देने और अनूप चंद्र पांडेय के 14 फरवरी को सेवानिवृत्त होने के चलते खाली हो गए थे। माना जा रहा है कि दोनों नए चुनाव आयुक्त शुक्रवार को अपनी नई जिम्मेदारी संभाल लेंगे।

नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री मोदी के अतिरिक्त विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के नेता के तौर पर अधीर रंजन चौधरी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल शामिल थे। मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा नया कानून बनने के बाद समिति ने यह पहली नियुक्ति की है। केंद्र सरकार मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर यह कानून सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद लेकर आई थी, जिसमें जल्द ही एक पारदर्शी कानून बनाने की बात कही गई थी।

प्रेट्र के अनुसार, अधीर रंजन चौधरी ने चयन प्रक्रिया पर कहा कि उन्होंने असहमति नोट दिया है। उन्होंने शार्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम मांगे थे। लेकिन उन्हें चयन समिति की बैठक से एक रात पहले 212 उम्मीदवारों के नाम दिए गए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयुक्त बनाए जाने वाले उम्मीदवारों के नाम उन्हें नियुक्ति से ठीक 10 मिनट पहले दिए गए। इस तरह सरकार ने इस मामले में सिर्फ औपचारिकता पूरी की है।

नए चुनाव आयुक्तों को जानिये पेज>>6

बंगाल में कांग्रेस को वाममोर्चा ने भी दिया झटका

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस के बंगाल की सभी 42 लोस सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित होने के बाद कांग्रेस-वाममोर्चा में समझौते की उम्मीद जगी थी, लेकिन वाममोर्चा ने गुरुवार को 16 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर कांग्रेस को झटका दिया है। (पेज-7)

महासमर 2024

टिकट वितरण के 'भविष्य' का संकेत दे रही भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची पेज>>4
दक्षिण के लिए कांग्रेस का 'मिशन 50' पेज>>4
बिहार की तरह आंध्र प्रदेश में भी जातीय मोर्चेबंदी पेज>>4
तेलंगाना 34 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की पेज>>4
सत्ता में आने पर आइएनडीआइए बनेगा किसानों की आवाज : राहुल पेज>>5

अच्छी खबर

मानव विकास सूचकांक में भारत का औसत सर्वश्रेष्ठ, पिछले 12 महीनों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय में 6.3 प्रतिशत की वृद्धि

भारत की प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा में उछाल को यूएन का सलाम

जेएनएन, नई दिल्ली

2021 में एक भारतीय की औसत जीवन प्रत्याशा 62.7 वर्ष थी। ठीक एक साल बाद भारतीयों की औसत आयु पांच साल बढ़कर 67.7 वर्ष हो गई। इतना ही नहीं, 2022 में भारतीयों की सकल राष्ट्रीय आमदनी (प्रति व्यक्ति) 6,951 डालर दर्ज की गई। इस लिहाज से एक वर्ष में भारतीयों की औसत आमदनी में 6.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआइ) में भारत के इस प्रदर्शन की सराहना की गई है। मानव विकास सूचकांक में भारत के औसत को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है।

मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग में पिछले साल के मुकाबले एक पायदान का सुधार आया है। 2021 में कुल 193 देशों में भारत की स्थिति 135 थी जो वर्ष 2022 में 134 हो गई। एचडीआइ रिपोर्ट में स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों में वृद्धि (प्रति व्यक्ति 12.6 वर्ष) की बात भी कही गई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की प्रतिनिधि केटलिन विसेन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत ने मानव विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। 1990 के बाद से जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 9.1 साल बढ़ गई है। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित समय में 4.6 साल की बढ़ोतरी हुई है। व्यक्तिगत पूंजी में भी लगभग 287 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत के बढ़ते कदम। प्रतीकात्मक

तीन मानकों पर होता है एचडीआइ का आकलन

संयुक्त राष्ट्र की ओर से एचडीआइ का आकलन मानव विकास के तीन बुनियादी मानकों पर किया जाता है। इसमें स्वस्थ और दीर्घ जीवन, शिक्षा तक पहुंच और जीवन स्तर के आधार पर किसी देश का प्रदर्शन देखा जाता है। यह विभिन्न देशों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकसित और संकलित आंकड़ा है।

2022 के लिए भारत के एचडीआइ स्कोर में एक साल पहले की गिरावट के बाद वृद्धि दर्ज की गई है। उससे पहले के वर्षों में भारत का स्कोर स्थिर रहता था। 1990 में भारत का एचडीआइ स्कोर 0.434 था। इस लिहाज से देखें तो 2022 के स्कोर में 48.4 प्रतिशत का सकारात्मक बदलाव आया है।

देश ने लैंगिक असमानता सूचकांक को कम करने में भी खासी सफलता पाई है। 2021 में 191 देशों में लैंगिक असमानता में भारत की रैंकिंग 122 थी। उस रैंक में 14 पायदानों का सुधार आया है और उसने वर्ष 2022 में 193 देशों में 108वीं रैंक हासिल की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, विश्व की सबसे अधिक आबादी वाले देश भारत में लैंगिक असमानता सूचकांक (जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स-जीआइआइ) में इस उपलब्धि के बावजूद महिला और पुरुष श्रमिकों की भागीदारी का अंतर अभी भी बहुत बड़ा है। महिला कर्मियों (28.3 प्रतिशत) और पुरुष कर्मियों (76.1 प्रतिशत) के बीच 47.8 प्रतिशत का भारी अंतर है। 2021 में कोरोना के चलते भारत के एचडीआइ मूल्य में मामूली गिरावट आई थी, लेकिन फिर भी इसमें 2021 के 0.633 के एचडीआइ मूल्य की तुलना में 0.644 का इजाफा हुआ है।

दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में आइएएस अधिकारी को तीन साल कैद

केस के ट्रायल के दौरान नवीन तंवर का आइएएस में हुआ चयन

नवीन तंवर, डीआरडीए, हिमाचल प्रदेश

नौ साल पहले बैंक क्लर्क भर्ती परीक्षा मामले में हुए अन्य दोषी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद

एक अभूतपूर्व मामले में नौ वर्ष पहले दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के मामले में एक ऐसे व्यक्ति को तीन साल की सजा हुई है, जो अब आइएएस अधिकारी बन गया है। वर्ष 2019 बैच के आइएएस अधिकारी नवीन तंवर के साथ पांच अन्य लोगों को भी सजा सुनाई गई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को सीबीआइ कोर्ट में सजा सुनाए जाने के वक्त नवीन तंवर कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। तंवर पिछले 10 माह से हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उपमंडल भरमौर में अतिरिक्त उपायुक्त कम सह-परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास एजेंसी (डीआरडीए) के पद पर कार्यरत हैं।

उप्र के नोएडा के रहने वाले तंवर नौ साल पहले खुद सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। 13 दिसंबर, 2014 को गाजियाबाद स्थित आइडियल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आइबीपीएस) की क्लर्क भर्ती परीक्षा हुई थी। सीबीआइ ने अमित सिंह और अजय पाल के स्थान पर परीक्षा दे रहे नवीन तंवर और सावन को गिरफ्तार किया। अभियुक्तों को गिरफ्तारी के बाद जमानत मिल गई थी।

195 रहा गुरुवार को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ)। इस स्तर की हवा को 'मध्यम' श्रेणी का माना जाता है। सीपीसीबी के मुताबिक, अगले दो दिनों के दौरान भी हवा की गुणवत्ता का यही स्तर बना रहेगा।

www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
शुक्रवार 15 मार्च, 2024

आज का मौसम

आसमान साफ रहेगा। 25 से 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी।

पूर्वानुमान	अधिकतम	न्यूनतम
दिल्ली		
15 मार्च	29.0	14.0
16 मार्च	30.0	12.0
नोएडा		
15 मार्च	38.0	14.0
16 मार्च	28.0	14.0
गुरुग्राम		
15 मार्च	29.0	15.0
16 मार्च	30.0	14.0

डिग्री सेल्सियस में

सीएम ने समन पर व्यक्तिगत पेशी से मांगी छूट, ईडी ने किया पुरजोर विरोध

आबकारी घोटाला मामला ▶ मजिस्ट्रेट अदालत के समन को केजरीवाल ने दी है चुनौती

पहले समन पर दोनों पक्षों ने पेश किए तर्क, आज दूसरे समन पर जारी रहेगी बहस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

अरविंद केजरीवाल। फाइल

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी दो समन को गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी। विशेष न्यायाधीश राकेश सयाल के समक्ष अरविंद केजरीवाल व ईडी की तरफ से पेश हुए अधिवक्ताओं के बीच तीखी बहस हुई। पहले समन पर दोनों पक्षों की विस्तार से दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दूसरे समन पर बहस सुनने के लिए सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता और ईडी की तरफ से एडिशनल सालिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें रखीं।

ईडी की पहली शिकायत पर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) दिव्या मल्होत्रा ने अरविंद केजरीवाल को अदालत में पेश होने के लिए सात फरवरी को पहला समन जारी किया था। 17 फरवरी को वीडियो कान्फ्रेंसिंग से पेश होकर केजरीवाल ने बजट सत्र का हवाला देते हुए व्यक्तिगत पेशी से छूट मांगी थी और आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होंगे। इसके बाद जारी कई समन के बाद भी नहीं पेश होने पर ईडी ने केजरीवाल के विरुद्ध अदालत में दूसरी शिकायत दी थी। इस पर सुनवाई के बाद सात मार्च को अदालत ने केजरीवाल को 16 मार्च को पेश होने का समन जारी किया था। दोनों मामलों पर 16 मार्च को एसीएमएम द्वारा विचार किया जाना है। मनी लांड्रिंग मामले में ईडी केजरीवाल को अब तक आठ समन जारी कर चुकी है।

अदालत में आमने-सामने

अधिवक्ता रमेश गुप्ता	एएसजी एसवी राजू
• मजिस्ट्रेट के समक्ष दिल्ली के सीएम की व्यक्तिगत उपस्थिति से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और ईडी केवल प्रचार के लिए ऐसा कर रही है।	• स्टाप प्लेइंग फ्राम द गैलरी (भीड़ का ध्यान खींचने वाले हरकतें करना बंद करें)। केंद्रीय जांच एजेंसी प्रचार के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
• सीएम केवल अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट मांग रहे हैं और सीएम की तरफ से अधिवक्ता पेश होने के लिए तैयार हैं। यह एक समन ट्रायल केस है।	• सीएम ने 17 फरवरी को पेश होकर आश्वासन दिया था कि वह 16 मार्च को अदालत में पेश होंगे। अब एक महीने बाद सीएम छूट मांग रहे हैं।
• दावा किया कि मेरे पास प्रथमदृष्टया मामला है कि शिकायतकर्ता सशक्त नहीं है। मामला जांच अधिकारी ने ईडी के बजाय व्यक्तिगत क्षमता से दर्ज किया था।	• शिकायतकर्ता भले सशक्त न हो, फिर भी शिकायत खारिज नहीं की जा सकती। अगर जांच अधिकारी की कल मृत्यु हो जाती है तो क्या शिकायत दर्ज नहीं होगी?
• कार्यवाही पर रोक का अनुरोध छोड़ रहा हूं, लेकिन मुवक्किल की व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट की मांग करता हूं। विनम्र अनुरोध है कि अंतरिम आदेश पारित किया जाए।	• (आवेदन का विरोध करते हुए दावा किया) सीएम अंतिम क्षण में अदालत आए। सीएम ऐसे बहाने बना रहे हैं जिनकी इजाजत आम आदमी को नहीं दी जा सकती।
• यदि सीएम को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा? अगर सीएम ने कहा कि मैं ट्रायल कोर्ट में पेश होऊंगा तो इसका क्या मतलब है?	**अदालत** : पहले समन पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दूसरे समन पर बहस सुनने के लिए मामला शुक्रवार सुबह दस बजे के लिए सूचीबद्ध किया।

'आश्चर्य है, आप सरकार ने महिला के मातृत्व लाभ का किया विरोध'

विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली

▶ हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील खारिज कर 50 हजार रुपये भुगतान करने को कहा

दिल्ली राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अनुबंध के आधार पर स्टेनोग्राफर के रूप में कार्यरत एक महिला को मातृत्व लाभ देने के एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने के दिल्ली सरकार के निर्णय पर हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया। वयस्क महिलाओं को एक हजार रुपये देने संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्य की बात है कि जो सरकार इस योजना का खूब प्रचार कर रही है, उसने एक महिला को मातृत्व लाभ देने के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया।

न्यायमूर्ति रेखा पल्ली और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसकी अपील गलत थी, क्योंकि एकल पीठ के आदेश ने पांच साल से अधिक समय तक उपभोक्ता आयोग की सेवा करने वाली एक युवा महिला को लाभ दिया था। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की अपील खारिज कर महिला को चार सप्ताह में 50 हजार की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा, एकल पीठ के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यह अपीलकर्ताओं को 26 सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिवादी को वेतन व अन्य मौद्रिक लाभों का भुगतान करने का निर्देश देता है। इस अवधि के लिए महिला ने मातृत्व लाभ की मांग की थी। दिल्ली सरकार ने छह अक्टूबर 2023 को एकल पीठ द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी।

पालतू जानवरों की जांच कर रिपोर्ट पेश करे पुलिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: कुत्तों के हमले में डेढ़ साल की बच्ची की मौत में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि तुगलक लेन के धोबी घाट क्षेत्र में पालतू जानवरों की प्रकृति के संबंध में जांच करें।

न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि यह भी देखें कि क्षेत्र में एक पिटबुल था या नहीं। स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए पुलिस को यह भी पता लगाने को कहा कि जहां घटना हुई वहां आसपास के घरों में कोई पालतू कुत्ता था या नहीं। अदालत ने पुलिस को इस विवरण के साथ 19 मार्च से पहले एक रिपोर्ट पेश करने को कहा।

अदालत ने यह निर्देश बच्ची की मौत पर मुआवजे की मांग वाली याचिका पर किया। डेढ़ साल की बच्ची को कुत्तों के एक झुंड ने हमलाकर मार डाला था। बच्ची के पिता राहुल कन्नौजिया ने मौत के लिए 50 लाख रुपये के मुआवजे मांग की है।

न्यूज गैलरी

जामिया मिल्लिया ने शुरू किए तीन नए विभाग

नई दिल्ली : जामिया मिल्लिया इस्लामिया (जेएमआइ) ने कानून, दंत विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान के लिए नई सुविधाओं के साथ तीन नए विभाग शुरू किए हैं। जेएमआइ के विजटर के रूप में राष्ट्रपति ने तीन नए विभागों के निर्माण के लिए मौजूदा कानून 20 में संशोधन के लिए सहमति प्रदान की है। शिक्षा मंत्रालय ने 6 मार्च को एक पत्र में विभागों को मौजूदा विभागों में जोड़ने की मंजूरी दे दी। 13 मार्च को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये विभाग अध्ययन विभाग के रूप में भी काम करेंगे। फिलहाल इनमें पुराने कोर्स ही संचालित किए जाएंगे। बाद में नए कोर्स जोड़ने की योजना बनाई जाएगी। (जासं)

अफ्रीकी नागरिक के पास मिला हाथी दांत, गिरफ्तार

नई दिल्ली: आइजीआइ एयरपोर्ट पर हाथी दांत की तस्करी का मामला सामने आया है। इस मामले में अफ्रीकी देश नाइजीरिया के नागरिक फ्रांसिस चिजमीफ इहियोमा को गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से नक्काशी किया हाथी का दांत बरामद हुआ है, जिसका वजन 275 ग्राम है। आरोपित आइजीआइ एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 पर दोहा जाने के लिए पहुंचा था। उसे कतर एयरवेज की उड़ान पकड़नी थी। जब लगेज की जांच की जा रही थी, तब हाथी का दांत नजर आया। (जासं)

बिजली उपभोक्ता घर बैठे कर सकेंगे शिकायत

नई दिल्ली : बिजली उपभोक्ता दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के पास आनलाइन शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए एक वेबपोर्टल व मोबाइल एप बनाने का प्रस्ताव है। आयोग के इस कदम से उपभोक्ता घर बैठे शिकायत कर सकेंगे। लोगों से 15 अप्रैल तक इस पर सुझाव मांगे गए हैं। इसमें उपभोक्ताओं को आनलाइन शिकायत की सुविधा देने का प्रस्ताव है। डाक से भी शिकायत स्वीकार किए जाएंगे। (राब्यू)

झूठी शिकायत करने वाला पूर्व दानिक्स अधिकारी गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

▶ दिल्ली सरकार के पूर्व दानिक्स अधिकारी एवी प्रेमनाथ को तिरुपति रेलवे स्टेशन गिरफ्तार कर लिया गया

▶ नोटिस देने के बावजूद प्रेम नाथ जांच में शामिल नहीं हुए, भूमिगत हो गए तो गैरजमानती वारंट जारी किया गया

दिल्ली सरकार के सतर्कता सचिव वाईवीवीजे राजशेखर के विरुद्ध फर्जी ई-मेल आइडी बनाकर झूठी शिकायत करने के आरोपित दिल्ली सरकार के पूर्व दानिक्स अधिकारी एवी प्रेमनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरपीएफ और जीआरपी की मदद से आरोपित को तिरुपति रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया गया। दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आरोपित को तिरुपति से लाकर तीस हजारी कोर्ट दिल्ली में पेश किया। कोर्ट ने आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

नकुल कश्यप ने 16 जून 2023 को आइपी एस्टेट थाने में एफआइआर कराई थी कि प्रेमनाथ ने उन्हें दिल्ली सरकार के विशेष सतर्कता सचिव वाइवीवीजे राजशेखर के विरुद्ध झूठी शिकायत करने के लिए प्रेरित किया था। साथ ही आरोप लगाया था कि एवी प्रेमनाथ ने उनके नाम से फर्जी ई-मेल आइडी बनाकर दिल्ली के विभिन्न अधिकारियों को वाइवीवीजे राजशेखर की झूठी शिकायत नकुल कश्यप के नाम से मेल की थी।

मामले की प्रारंभिक जांच दिल्ली के मध्य जिले में की गई और बाद में तीन नवंबर 2023 को मामला अपराध शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया। प्रेमनाथ ने एफआइआर रद करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था, मगर हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। नोटिस दिए जाने के बावजूद, प्रेम नाथ जांच में शामिल नहीं हुए और भूमिगत हो गए तो उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था। इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

शास्त्री नगर में चार मंजिला मकान में आग, एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

सुमन व मनोज। सौ.- स्वजन

▶ बिजली के तारों में शार्ट सर्किट होने से पार्किंग में खड़े वाहनों में लगी थी आग

▶ भूतल पर बने फ्लैट में रहने वाला परिवार खुद को बचा नहीं पाया

शास्त्री नगर स्थित इसी मकान में लगी थी आग। पारसकुमार

शास्त्री नगर स्थित चार मंजिला मकान में गुरुवार तड़के बिजली के तारों में शार्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। तारों में लगी आग पार्किंग में खड़े वाहनों में लग गई। देखते ही देखते पार्किंग में धमाके होने लगे। धुंआ ऊपरी मंजिल पर फैल गया। भूतल पर बने फ्लैट में रहने वाला परिवार आग में बुरी तरह से फंस गया। ऊपरी मंजिल पर रहने वाले कई लोगों ने छत पर भागकर व बालकनी में खड़े होकर अपनी जान बचाई।

गीता कालोनी थाना पुलिस व दमकल ने 14 लोगों को रेस्क्यू किया। झुलसे हुए 14 लोगों को डा. हेडगेवार अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डाक्टरों ने एक ही परिवार के चार लोगों को मृत घोषित कर दिया। इनमें दो बच्चियां हैं। मृतकों की पहचान मनोज, उनकी पत्नी सुमन, पांच वर्षीय भतीजी सृष्टि और साढ़े तीन वर्षीय सुजाता के रूप में हुई है। मनोज के छोटे भाई नंदू, बड़े भाई राकेश उसकी पत्नी बेबी की जीटीबी अस्पताल में हालत नाजुक बनी हुई है। बाकी घायलों का भी इलाज चल रहा है। आग लगने से पार्किंग में खड़ी कार, चार मोटरसाइकिल, एक साइकिल व ठेला जलकर खाक हो गया। गीता कालोनी थाना पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में प्राथमिकी की है।

जिला पुलिस उपायुक्त सुरेंद्र चौधरी ने बताया कि गुरुवार सुबह 5:22 बजे पुलिस को शास्त्री नगर की गली नंबर-13 में एक मकान में आग लगने की सूचना मिली थी। थानाध्यक्ष सत्यवान लठवाल अपनी टीम और दमकल की नौ गाड़ियां मौके पर पहुंची। मकान 110 वर्ग गज का है, जिसमें नौ फ्लैट बने हुए हैं और उनमें 40 लोग रहते हैं। एक फ्लैट भूतल पर पार्किंग के पास बना हुआ है। मनोज अपने परिवार के साथ तीन माह पहले ही उसमें किराये पर रहने आए थे। पुलिस ने 14 लोगों को घर से रेस्क्यू किया, जिनमें से सात मनोज के परिवार के सदस्य थे।

दिल्ली में तीन हजार झुग्गी वालों को दिए घर : मोदी

▶ प्रथम पृष्ठ से आगे

प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली में तीन हजार झुग्गी वालों को घर दिए हैं और साढ़े तीन हजार मकान बनकर तैयार होने वाले हैं। दिल्ली के अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का काम चल रहा है। मध्यम वर्ग को अपना मकान बनाने के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। आवागमन सुगम बनाने के लिए कई शहरों में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जा रहा है। दिल्ली में पिछले 10 वर्षों में मेट्रो नेटवर्क लगभग दोगुना हो गया है। विश्व के बड़े मेट्रो नेटवर्क वाले शहरों में दिल्ली शामिल है। एनसीआर में नमो भारत रैपिड ट्रेन चलने लगी है। यहां प्रदूषण की समस्या दूर करने के लिए एक हजार से अधिक इलेक्ट्रिक बसें चलाई गई हैं। दिल्ली के चारों ओर कई एक्सप्रेस-वे बनाने से प्रदूषण कम हुआ है। द्वारका एक्सप्रेस-वे शुरू होने से दिल्लीवालों का जीवन आसान होगा। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया से सामान्य परिवारों के खिलाड़ियों को घर के पास प्रशिक्षण व खेल सुविधाएं मिल रही हैं।

लोगों के बीच मुद्दों की टोह लेने उतरे भाजपा प्रकोष्ठ के सिपाही

पार्टियों की रणनीति

संतोष कुमार सिंह, नई दिल्ली

▶ सभी वर्गों के बीच पहुंचने की प्रकोष्ठ को दी गई जिम्मेदारी

▶ विकसित भारत के संकल्प पर जनता से ले रहे हैं सुझाव

लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के रणनीतिकार मजबूत मोर्चेबंदी की तैयारी कर रहे हैं। जनता तक अपनी बात पहुंचाकर चुनावी राह आसान बनाने का काम शुरू हो गया है। इसमें दिल्ली भाजपा के प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उन्हें सबसे पहले संकल्प पत्र बनाने के लिए जनता से सुझाव लेने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता मुद्दों की टोह लेने अलग-अलग वर्गों के बीच पहुंच रहे हैं।

विभिन्न वर्गों को साधने के लिए भाजपा में व्यापार प्रकोष्ठ, रेजिडेंट वेलफेयर प्रकोष्ठ, चिकित्सक प्रकोष्ठ, अभियंता प्रकोष्ठ, विधि प्रकोष्ठ, आइटी पेशेवर प्रकोष्ठ, शिक्षक प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ सहित 30 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। प्रकोष्ठ की प्रदेश स्तरीय टीम के साथ ही जिलों और मंडलों में भी इकाई गठित की गई है। प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी अशोक ठाकुर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। इसमें नागरिकों के सुझाव लिए जा रहे हैं। उनके सुझाव से लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र तैयार होगा। इसके लिए व्यापारिक संगठनों, आरडब्ल्यूए के सदस्यों व अन्य वर्गों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की जा रही है। लोगों के सुझाव नमो एप पर अपलोड किया जाएगा।

भाजपा ने 29 फरवरी को शुरू किया था अभियान: भाजपा ने 29 फरवरी को जनता से सुझाव लेने का अभियान शुरू किया था। भाजपा नेताओं का दावा है कि दिल्ली की जनता के सुझाव से संकल्प पत्र में शामिल किए गए अधिकांश मुद्दों पर काम किया गया है।

तीन सीटों पर ही छूट रहे कांग्रेस के पसीने!

संजीव गुप्ता, नई दिल्ली

▶ निरंतर बैठकों के बाद भी पार्टी तय नहीं कर पा रही उम्मीदवार

▶ अब शुक्रवार की बजाए सोमवार तक टली तय नामों की घोषणा

अरविंदर सिंह लवली। फाइल

आम आदमी पार्टी (आप) से गठबंधन में मिली तीन लोकसभा सीटों पर भी कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। लगातार बैठकें करने के बावजूद पार्टी इन सीटों से प्रत्याशियों के नाम तय नहीं कर पा रही है। आलम यह है कि संभावित प्रत्याशियों की जोड़तोड़ में नए नए समीकरण भी जुड़ते जा रहे हैं। गौरतलब है कि राजधानी में सातों लोकसभा सीटों पर आप- कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही हैं। चार सीटें आप के पास हैं, जबकि तीन कांग्रेस को मिली हैं। दिलचस्प यह है कि आप अपने चारों उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। भाजपा ने भी सातों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार भी तय नहीं कर पा रही है।

प्रदेश कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी चार से पांच बैठकें कर चुकी हैं। दो बार तो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) की भी बैठकें हो चुकी हैं। अगली बैठक शुक्रवार को प्रस्तावित थी, लेकिन उसे अब सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। मतलब, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार सोमवार शाम तक ही घोषित किए जाने के आसार हैं। पार्टी सूत्र बताते हैं कि उत्तर पूर्वी दिल्ली से पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और पूर्व विधायक भीष्म शर्मा के नाम पर गंभीरता से विचार हो रहा है। वैसे कहने को इस सीट से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी सहित कई अन्य नेता भी ताल ठोक रहे हैं। चांदनी चौक से पूर्व सांसद जयप्रकाश अग्रवाल और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा के नाम प्राथमिकता से विचाराधीन हैं। अलका यहां से विधायक भी रह चुकी हैं, जबकि जयप्रकाश अग्रवाल का मान सम्मान काफी है। इस सीट से एक अन्य उम्मीदवार पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता भी हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से पूर्व सांसद उदित राज, पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान एवं पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार में से ही किसी एक के नाम पर मोहर लगना तय है।

कांग्रेस में स्थानीय दावेदार को टिकट देने की मांग जोर पकड़ रही : सूत्र की मानें तो भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद अब कांग्रेस में हर सीट पर स्थानीय दावेदार को ही टिकट देने की मांग जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने जागरण से बातचीत में कहा कि शुक्रवार को एक बार फिर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है।

सीईसी के निर्देशानुसार इसमें हर सीट से एक-एक नाम तय कर भेजे जाने हैं। सोमवार को सीईसी की बैठक प्रस्तावित है। संभावना है कि उस दिन तीनों सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर स्वीकृति की मुहर लग जाएगी और उसी दिन देर शाम तक घोषणा भी कर दी जाएगी।

अमेरिका के नागरिकों से ठगी करने वाले फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली

▶ छापेमारी कर पुलिस ने संचालक सहित दो जालसाजों को किया गिरफ्तार

▶ अमेरिकी नागरिकों को तकनीकी सेवाएं मुहैया कराने के नाम पर कर रहे थे ठगी

दक्षिण-पूर्वी जिले के साइबर थाना पुलिस ने मथुरा रोड स्थित मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट में छापेमारी कर अमेरिकी नागरिकों को ठगने वाले एक अंतरराष्ट्रीय फर्जी काल सेंटर का पर्दाफाश कर दो जालसाजों को गिरफ्तार किया है। गिरोह अमेरिका की बड़ी कंपनी के नाम पर तकनीकी सेवा मुहैया कराने के बहाने ठगी कर रहा था।

पुलिस उपायुक्त राजेश देव ने बताया कि जालसाजों की पहचान नोएडा के सुपरनोवा निवासी प्रकाश विश्वकर्मा और शाहीन बाग निवासी बरकतुल्ला खान के रूप में हुई। सात मार्च को सूचना मिली थी कि बदरपुर क्षेत्र में एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय काल सेंटर संचालित किया जा रहा है। यहां से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के नाम पर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी की जा रही है। पुलिस ने मोहन कोआपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट में छापेमारी की। यहां से संचालक प्रकाश विश्वकर्मा व बरकतुल्ला खान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 25 हार्ड डिस्क, तीन कम्प्यूटर, तीन मोबाइल, विभिन्न बैंक की कई चेक बुक, अपराध में प्रयुक्त 25 हेडफोन सहित अन्य सामान बरामद किया।

ऐसे बनाते थे अमेरिकी नागरिकों को शिकार: जांच में सामने आया कि जालसाज गूगल एड की मदद से अमेरिकी क्षेत्र में विज्ञापन चलाने के लिए गीक सपोर्ट, टेक सपोर्ट और माइक्रोसाफ्ट सपोर्ट जैसे कीवर्ड का प्रयोग कर रहे थे। जब भी कोई विदेशी नागरिक तकनीकी सहायता के लिए गूगल पर सर्च करता था, तो जालसाजों का विज्ञापन स्क्रीन पर आ जाता था। संबंधित लिंक पर क्लिक करते ही वह जालसाजों के मोबाइल नंबर के साथ बेयरडाट काम नाम की एक वेबसाइट पर पहुंच जाता था।

होगी सुविधा

ग्रीन लाइन के विस्तार से हरियाणा के बहादुरगढ़ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व इंद्रप्रस्थ तक उपलब्ध होगी सीधी मेट्रो, तीन कारिडोर के साथ इंटरचेंज वाले बनेंगे दो नए मेट्रो स्टेशन, अभी आजादपुर में निर्माणाधीन है ऐसा एक स्टेशन

दो नए मेट्रो कारिडोर से हो जाएंगे चार ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

आजादपुर, नई दिल्ली व लाजपत नगर भी बनेंगे बड़े ट्रांजिट प्वाइंट। फाइल

दो नए मेट्रो कारिडोर की लंबाई (किलोमीटर में)

कारिडोर	लंबाई	भूमिगत	एलिवेटेड	स्टेशनों की सं.
लाजपत नगर साकेत जी ब्लाक	8.385	0.00	8.385	8
इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ	12.377	11.349	1.028	10
कुल	20.762	11.349	9.413	18

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा फेज-चार में दिल्ली मेट्रो के दो नए कारिडोर के शिलान्यास के बाद लाजपत नगर से साकेत जी ब्लाक और इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ के बीच मेट्रो कारिडोर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। खास बात यह है कि इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ मेट्रो कारिडोर मौजूदा ग्रीन लाइन (कीर्ति नगर-इंद्रलोक- बहादुरगढ़ सिटी पार्क) की विस्तार परियोजना है। लिहाजा इस 12.37 किलोमीटर मेट्रो कारिडोर के निर्माण से न सिर्फ दिल्ली के लोगों को, बल्कि हरियाणा के बहादुरगढ़ और इसके आसपास के लोगों को भी फायदा होगा।

इस कारिडोर का निर्माण पूरा होने पर ग्रीन लाइन पर बहादुरगढ़ से सराय रोहिला रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन व इंद्रप्रस्थ के लिए सीधी मेट्रो उपलब्ध होगी। इससे मेट्रो से बहादुरगढ़ से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचना ज्यादा आसान हो जाएगा। वहीं दिल्ली में कश्मीरी गेट की तरह तीन मेट्रो लाइन के साथ चार बड़े ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन उपलब्ध हो जाएंगे।

मौजूदा समय में दिल्ली में सिर्फ कश्मीरी गेट तीन मेट्रो लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन है। कश्मीरी गेट में रेड लाइन (रिठाला-न्यू बस अड्डा गाजियाबाद), यलो लाइन (समयपुर बादली- मिलेनियम सिटी गुरुग्राम) व वायलेट लाइन (कश्मीरी गेट-बल्लभगढ़) के स्टेशन हैं। इससे मौजूदा समय में कश्मीरी गेट दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा ट्रांजिट प्वाइंट है। फेज-चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-आरके आश्रम कारिडोर पर आजादपुर में दूसरा ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बनाया जा रहा है। वर्तमान समय में आजादपुर में यलो लाइन व पिंक लाइन (मजलिस पार्क-शिव विहार) के साथ इंटरचेंज स्टेशन है।

अब लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक और इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कारिडोर का निर्माण होने पर लाजपत नगर व नई दिल्ली में दो नए ट्रिपल इंटरचेंज स्टेशन बनेंगे। मौजूदा समय में इन दोनों जगहों पर दो कारिडोर के साथ इंटरचेंज स्टेशन हैं। लाजपत नगर अभी वायलेट लाइन व पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज स्टेशन है। वहीं नई दिल्ली में यलो लाइन व एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन (आरेंज लाइन) के साथ इंटरचेंज स्टेशन है। अब नई दिल्ली में इंद्रलोक-इंद्रप्रस्थ कारिडोर का नया स्टेशन बनेगा। इसलिए यह ग्रीन लाइन के साथ ही इंटरचेंज स्टेशन होगा। वहीं लाजपत नगर में भी लाजपत नगर-साकेत जी ब्लाक का नया स्टेशन बनेगा। इसलिए फेज चार का निर्माण पूरा होने पर कश्मीरी गेट की तरह आजादपुर, नई दिल्ली व लाजपत नगर भी मेट्रो का बड़े ट्रांजिट प्वाइंट बनकर उभरेंगे।

****

कह कर रहेंगे माधव जोशी

18 वर्ष कर दी गई थी वोट देने की उम्र 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1989 में। इससे पहले वोट देने के लिए मतदाता की उम्र 21 वर्ष होना जरूरी था।

195 उम्मीदवारों की पहली सूची में 30 मौजूदा सांसदों का काटा गया टिकट

72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों के टिकट पर कैंची चली

267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है भाजपा

450 सीटों पर चुनाव लड़ने की है संभावना

51 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है उत्तर प्रदेश में

17 में से 15 उम्मीदवारों की घोषणा तेलंगाना में कर चुकी है पार्टी

टिकट वितरण के 'भविष्य' का संकेत दे रही भाजपा प्रत्याशियों की दूसरी सूची

नीलू रंजन • नई दिल्ली

देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा की दूसरी सूची 'भविष्य' का भी संकेत दे रही है। यानी ऐसे उम्मीदवारों पर पार्टी कोई दांव नहीं लगाएगी, जिसने दो कार्यकाल के बावजूद खुद के लिए नया वोट वर्ग तैयार नहीं किया। ऐसे उम्मीदवारों से भी परहेज ही रहेगा, जिसके बयानों की सफाई पार्टी को देनी पड़ती है। 195 उम्मीदवारों की पहली सूची में जब सिर्फ 30 मौजूदा सांसदों का टिकट काटा गया था, तब यह कयास लगने शुरू हो गए थे कि इस बार भाजपा पड़े पैमाने पर उम्मीदवारों को नहीं बदलेगी, लेकिन 72 उम्मीदवारों की दूसरी सूची में 33 मौजूदा सांसदों का टिकट काटकर भाजपा ने साफ कर दिया है कि उसके लिए उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता सबसे अहम है।

भाजपा लगभग 450 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अबतक 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। उम्मीदवारों में सबसे बड़ा उलटफेर दिल्ली मे देखने को मिला, जहां सात में छह उम्मीदवार बदल दिए गए और सिर्फ मनोज तिवारी अपनी उम्मीदवारी बचाने में सफल रहे। इसी तरह से हरियाणा में जिन छह उम्मीदवारों की घोषणा हुई है,

- **नया वोट वर्ग तैयार नहीं करने वाले नेताओं पर दांव नहीं लगाएगी देश की सबसे वड़ी पार्टी**
- **वेवजह वयानवाजी से दूरी और जीतने की संभावना भी है प्रत्याशी चयन का आधार**
- **मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा का टिकट कटा, उनके पास से लोस में पहुंचे थे रंगीन गैस छोड़ने वाले**

उनमें तीन नए हैं। महाराष्ट्र में 20 उम्मीदवारों में से 14 को दोबारा टिकट मिला है, जबकि पांच का टिकट काटा गया है। प्रीतम मुंडे की जगह इस बार उनकी बहन पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया गया है। जिस सांसद प्रताप सिम्हा के पास से रंगीन गैस छोड़ने वाले आरोपित लोकसभा के भीतर पहुंचे थे, मैसूर से उनका टिकट भी कट गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 15 अगस्त के लालकिले से अपने भाषण से खुद को 140 करोड़ देशवासियों के परिवार के सदस्य के रूप में पेश करते रहे हैं।

इसलिए कटा टिकट: भाजपा ने इस बार टिकट बंटवारे में अनावश्यक बयानबाजी करने वाले और दूसरे समुदाय के खिलाफ अनर्गल बातें बोलने वालों को टिकट देने से परहेज किया है। इनमें दिल्ली से प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और प्रज्ञा ठाकुर का नाम प्रमुख है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लोकसभा के भीतर महात्मा गांधी के बारे में आपत्तिजनक बातें कहीं थी, तो रमेश बिधूड़ी ने बसपा सासंद दानिश अली के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। प्रवेश वर्मा दिल्ली के दंगे के दौरान अपने बयानबाजी को लेकर विवादों में रहे थे। उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चर्चा हो चुकी है, लेकिन घोषणा सिर्फ 51 की हुई है। माना जा रहा है कि बची हुई सीटों पर बड़े बदलाव दिखेंगे।

इसलिए इन पर खेला दांव

मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ में बहुत सारे सांसदों के विधानसभा का चुनाव लड़ने के कारण स्वाभाविक रूप से उनकी जगह नए चेहरों को उतारा गया तो तेलंगाना में दूसरी पार्टी से आने वालों को ज्यादा तरजीह मिली। तेलंगाना में 17 में से जिन 15 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है, उनमें से 10 बीआरएस व अन्य पार्टियों से पिछले पांच सालों के दौरान भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा के मूल कैडर में इसको लेकर भले ही थोड़ी नाराजगी दिख रही हो, लेकिन जीत की संभावना को देखते हुए भाजपा ने इन पर दांव खेलना उचित समझा।

अतीत के आईने से

आम चुनाव 2009
फिर बनी संप्रग सरकार

पांच साल तक सफलता के साथ गठबंधन सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने 2009 के लोस चुनाव में पिछले चुनाव की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया और संप्रग सरकार ने वापसी की। कांग्रेस ने मनमोहन सिंह को दोबारा प्रधानमंत्री बनाया।

क्या रहे नतीजे

2009 के लोस चुनाव में कांग्रेस की अगुआई वाले संप्रग को 262 सीटें मिली। कांग्रेस ने 206 सीटें जीतीं। वहीं, राजग को कुल 159 सीटों पर जीत मिली थी। भाजपा को 116 सीटें मिलीं थीं। सरकार को सपा-बसपा ने बाहर से समर्थन दिया था।

किसको-कितनी सीटें मिलीं

कांग्रेस	206
भाजपा	116
सीपीएम	16
सीपीआइ	4
सपा	23
बसपा	21
राजद	4
एनसीपी	9

16 अप्रैल से 13 मई के बीच पांच चरणों में हुए। कुल सीटें, 543 बहुमत के लिए, 272

कर्जमाफी से मिला फायदा

कांग्रेस के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार ने 2008 में देशभर के किसानों का 65 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। इससे कांग्रेस को सत्ता में वापसी करने में मदद मिली।

मनरेगा का असर

2006 में कांग्रेस ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (अब मनरेगा) बनाया। योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में लोगों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी देने की बात कही गई। चुनाव में इस योजना का काफी असर रहा।

महासमर की अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

दक्षिण के लिए कांग्रेस का 'मिशन 50'

2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़ी चुनौतियों के बाद अब पार्टी को दक्षिण से ही आस

संजय मिश्र • नई दिल्ली

दक्षिण के पांच राज्यों तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव की लड़ाई 2024 में इसलिए भी बेहद दिलचस्प है कि जहां क्षेत्रीय पार्टियां अपना आधार कायम रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, वहीं दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस के बीच भी दक्षिण का बाजीगर बनने की जबरदस्त होड़ है। इसका ही नतीजा है कि कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति में विपक्षी विकल्प की धुरी बने रहने के लिए कम से कम दक्षिण भारत में भाजपा को आगे नहीं निकलने देने की रणनीति के इर्द-गिर्द अपने चुनावी प्रबंधन को दशा-दिशा देने में जुटी है। चुनावी प्रबंधन की अपनी इस अंदरूनी रणनीति के तहत कांग्रेस ने दक्षिण के उक्त पांच राज्यों में मिशन 50 का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। यानी पार्टी दक्षिण भारत से लोकसभा की कम से कम 50 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही है।

पार्टी की सियासत के साथ-साथ विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए के भविष्य की संभावनाओं को जीवंत रखने के लिए दक्षिणी राज्यों के चुनाव कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दक्षिण में कांग्रेस के अपने मिशन 50 के बड़े लक्ष्य की वजह यह भी है कि पिछले दो 2014 व 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी के बेहद खराब दौर में दक्षिण के राज्यों ने ही उसे राजनीतिक सहारा दिया है।

सूत्रों के अनुसार पार्टी के चुनावी रणनीतिकार सुनील कानुगोलू की टीम इस मिशन को लेकर जमीनी स्तर पर गंभीरता से काम कर रही है और केरल, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु इन चार राज्यों में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन से लक्ष्य हासिल करने की रणनीति बनी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के रणनीतिक सिपहसालारों में शामिल एक वरिष्ठ नेता ने इस बारे में कहा कि भाजपा की तरह हम 370 या 400 सीटों के बड़े-बड़े दावे नहीं करेंगे, मगर यह सही है कि प्रत्येक प्रदेश के साथ क्षेत्र के स्तर पर पार्टी ने निश्चित संख्या में सीटें जीतने का मिशन तय किया गया है। संभावनाओं वाली इन सभी सीटों पर पार्टी पूरी ताकत झोंकने में कोई कसर नहीं रखेगी।

दक्षिण के किस राज्य में कितनी सीटें जीतीं पिछली बार

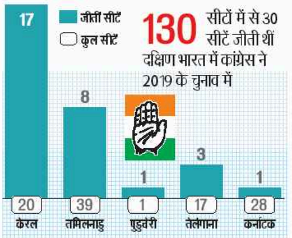

130 सीटों में से 30 सीटें जीती थीं दक्षिण भारत में कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में

20 सीटों में से कम से कम 17 सीटें इस बार भी केरल में मिलना तय मान रही कांग्रेस

39 में आठ से नौ सीटों पर जीत की संभावना देख रही है तमिलनाडु में

28 लोकसभा सीटों में पार्टी अंदरूनी तौर पर 12-13 सीटों के अलावा ज्यादा संभावनाएं नहीं देख रही कर्नाटक में

- **अपने साथ-साथ विपक्षी गठवंधन आइएनडीआइए के भविष्य की संभावनाओं को जीवंत रखने की कोशिश में कांग्रेस**
- **क्षेत्रीय पार्टियां अपना आधार कायम रखने को प्रतिवद्ध हैं तो भाजपा-कांग्रेस में दक्षिण का वाजीगर वनने की होड़**

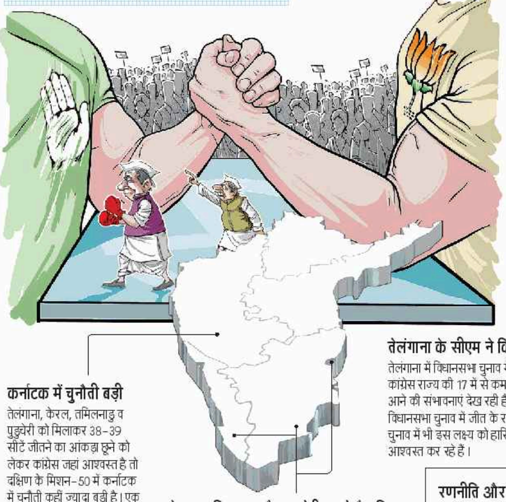

किस राज्य में कांग्रेस ने जीतीं कितनी सीटें

राज्य	कुल	जीती
उत्तर प्रदेश	80	1
मध्य प्रदेश	29	1
राजस्थान	25	0
छत्तीसगढ़	11	2
बिहार	40	1
बंगाल	42	2
झारखंड	14	1
दिल्ली	7	0
हरियाणा	10	0
पंजाब	13	8
जम्मू-कश्मीर	6	0
उत्तराखंड	5	0
हिमाचल प्रदेश	4	0

कर्नाटक में चुनौती बड़ी

तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु व पुडुचेरी को मिलाकर 38-39 सीटें जीतने का आंकड़ा छूने को लेकर कांग्रेस जहां आश्वस्त है तो दक्षिण के मिशन-50 में कर्नाटक में चुनौती कहीं ज्यादा बड़ी है। एक साल पहले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए इस प्रदर्शन के आस-पास टिके रहना कठिन बताया जा रहा है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि राज्य की 28 लोकसभा सीटों में पार्टी अंदरूनी तौर पर 12-13 सीटों के अलावा ज्यादा संभावनाएं नहीं देख रही।

केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी का ये है गणित

केरल, तेलंगाना, कर्नाटक तथा तमिलनाडु को मिलाकर 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने दक्षिण भारत की लोकसभा की कुल 130 सीटों में से 30 सीटें जीती थीं। पार्टी का मानना है कि केरल की 20 सीटों में से कम से कम 17 सीटें इस बार भी मिलनी तय हैं तो तमिलनाडु की 39 में आठ से नौ सीटों और पुडुचेरी की एक सीट के लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नहीं है। तमिलनाडु में द्रमुक के साथ मजबूत गठबंधन का कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी फायदा मिला था और इस चुनाव में भी अन्नाद्रमुक के बिखराव का इस गठबंधन को फायदा मिल सकता है।

तेलंगाना के सीएम ने किया हाईकमान को आश्वस्त

तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने से उत्साहित कांग्रेस राज्य की 17 में से कम से कम 12 सीटें अपने खाते में आने की संभावनाएं देख रही है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और विधानसभा चुनाव में जीत के रणनीतिकार कानुगोलू लोकसभा चुनाव में भी इस लक्ष्य को हासिल करने को लेकर हाईकमान को आश्वस्त कर रहे हैं।

रणनीति और प्रबंधन के साथ लगाना होगा चुनावी मैदान में जोर

कर्नाटक में कांग्रेस पिछले लोकसभा में केवल एक सीट ही जीत पाई थी और इस लिहाज से दहाई का आंकड़ा पार करने का इस बार का लक्ष्य बहुत बड़ा है। पार्टी के रणनीतिकार भी मानते हैं कि कांग्रेस के मिशन दक्षिण के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर्नाटक में कम से कम 10-12 सीटें हासिल करना अपरिहार्य है और इसके लिए पार्टी को रणनीति, प्रबंधन से लेकर मैदान में पूरा जोर लगाना होगा।

संदेशखाली का बड़ा संदेश

बंगाल के संदेशखाली में प्रताड़ना के बाद विरोध-प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं से मिलने पहुंचे थे राज्यपाल डा. सीवी आनंद बोस। इस दौरान पीड़िताओं ने अपनी व्यथा कही • जागरण आर्काइव

विशाल श्रेष्ठ • कोलकाता

बंगाल के पावर हब और जहां खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवास करती हैं, उस कोलकाता से महज 75 किलोमीटर दूर संदेशखाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न की वारदात ने सबको झकझोर दिया है। महिलाओं में इसे लेकर भारी रोष दिख रहा है। इसे लेकर राजनीति भी गर्म है। बंगाल में सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस इसे जहां 'सजाई हुई घटना' करार दे रही है, वहीं भाजपा इसे लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। इस बीच संदेशखाली कड़ा संदेश दे रही है।

संदेशखाली बंगाल की महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। नंदीग्राम से भी आवाजें उठ रही हैं, जहां की महिलाओं ने वाममोर्चा के 34 वर्षों के शासन का सफाया करने के लिए ममता के साथ कदम से कदम मिलाया था। मालूम हो कि 2007-08 में वाममोर्चा के शासनकाल में नंदीग्राम में जबरन भूमि अधिग्रहण हुआ था, जिसका विरोध करने पर स्थानीय लोगों को काफी प्रताड़ित किया गया था। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थीं। इसके खिलाफ आंदोलन करने वाली 66 साल की राधा रानी ने कहा-हमें पता चल गया है कि जब जो सत्ता में होता है, वही अत्याचार करने लग जाता है। संदेशखाली की महिलाएं हमारी तरह ही विरोध-प्रदर्शन कर रही हैं। हम उनका समर्थन करते हैं। नंदीग्राम के आंदोलन में शामिल रहीं कल्पना मुनियान ने कहा-बंगाल में महिलाएं हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी के निशाने पर रहती हैं, पर अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हम संदेशखाली की प्रताड़ित मां-बहनों के साथ हैं।

मुद्दे को भुनाने की जुगत में भाजपा: लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बंगाल में संदेशखाली के रूप में भाजपा के हाथ बड़ा मुद्दा लगा है। भाजपा ममता बनर्जी के शासन में महिलाओं की अस्मिता व सुरक्षा पर लगातार सवाल उठाती आई है। इस बार महिलाएं खुद सामने आकर तृणमूल नेताओं पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए विरोध-प्रदर्शन कर रही हैं। बंगाल की राजनीति पर पैनी नजर रखने वालों का कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर जल्द ही इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाईं तो चुनाव में उनकी पार्टी के लिए यह बेहद नुकसानदेय साबित हो सकता है, क्योंकि ममता को जिताने में शुरू से ही महिलाओं की अग्रणी भूमिका रही है।

महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझना बेहद निंदनीय है। सभ्य समाज में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संदेशखाली के अलावा अगर कहीं और भी इस तरह की वारदात हो रही हों तो वहां की महिलाओं को भी सामने आकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

उमा झुनझुनवाला, रंगमंच कलाकार

संदेशखाली की वारदात झकझोरने वाली है। महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार को किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। संदेशखाली के दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।

महाश्वेता मुखर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता

बंगाल में इस तरह की वारदात अकल्पनीय है, जहां की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं। यहां की सभ्यता व संस्कृति की मिसालें पेश की जाती हैं। कोलकाता को 'जेंटलमैंस सिटी' कहा जाता है। इससे कुछ किलोमीटर की दूरी पर इस तरह की घटनाएं हैरत करने वाली हैं। केंद्र सरकार को भी इस मामले में बेहद सख्त रुख अपनाना चाहिए था, जोकि देखने को नहीं मिला।

निशि पाठक, कामकाजी महिला

...तो ऐसे बना आपका मतदाता पहचान पत्र

आज लगभग सबके पास मतदाता पहचान पत्र है। ये मतदान के अलावा दूसरी जगहों पर भी पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ के तौर पर काम आता है। चुनाव में फर्जी मतदान रोकने के लिए मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत 1993 में हुई, लेकिन इसे जारी करने का सुझाव पहली बार 1957 में दिया गया था। ये अलग बात है कि कई तरह की मुश्किलों और भारी खर्च के कारण इसे मतदाताओं तक पहुंचाने में तीन दशक से अधिक समय लगा।

₹25 लाख खर्च आया था सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में पहचान पत्र जारी करने के प्रोजेक्ट पर

2.13 लाख मतदाताओं की फोटो ही ली जा सकी थीं कलकत्ता के दक्षिण पश्चिम लोकसभा क्षेत्र में

1993 में चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर की मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत

ऐसे आया पहचान पत्र का विचार

चुनाव आयोग ने 1962 लोकसभा चुनाव पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि 1957 के आम चुनाव के बाद घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्र के सभी मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करने का सुझाव दिया गया था। माना गया था कि इससे चुनाव के समय मतदाता की पहचान करने में मदद मिलेगी। बाद में इस पर पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया।

असफल रहा पायलट प्रोजेक्ट

मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र जारी करने का पायलट प्रोजेक्ट 1960 में चलाया गया। मौका था कलकत्ता (दक्षिण पश्चिम) लोकसभा के उपचुनाव का। हालांकि, यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ। बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं ने पुरुष या महिला छायाकारों से फोटो खिंचवाने से मना कर दिया। बहुत से मतदाता मिले ही नहीं। ऐसे में 10 माह में सिर्फ 2.10 लाख पहचान पत्र ही जारी किए जा सके।

विधेयक में किया गया प्रविधान

चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित किताब 'लीप आफ फेथ' के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1958 में फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रविधान किया गया था। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के छोटे भाई और तत्कालीन कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने 27 नवंबर, 1958 को विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया। 30 दिसंबर, 1958 को यह विधेयक कानून बन गया।

सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार करने के बाद चुनाव आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मतदाता पहचान पत्र का सिस्टम बड़े पैमाने पर कलकत्ता या देश में कहीं भी लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा।

केवीके सुंदरम, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त

मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रानिक वर्जन

चुनाव आयोग ने 2021 में मतदाता पहचान पत्र का इलेक्ट्रानिक वर्जन (e-EPIC) लांच किया। यह मतदाता पहचान पत्र का सुरक्षित पीडीएफ वर्जन है। इसे संपादित नहीं किया जा सकता है। इसे मोबाइल पर डाउनलोड करके स्टोर कर सकते हैं।

बिहार की तरह आंध्र प्रदेश में भी जातीय मोर्चेबंदी

अरविंद शर्मा • नई दिल्ली

आंध्र प्रदेश में बिहार की तरह ही चुनाव में जाति की हवा बहाई जा रही है। बिहार के बाद देश का यह दूसरा राज्य है, जहां जातिवार गणना का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश की राजनीति में तीन बड़ी जातियों की धाक है-कम्मा, कापू और रेड्डी। जिसमें रेड्डी सर्वाधिक संपन्न, शिक्षित और शक्तिशाली हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन स्वयं रेड्डी हैं। हालांकि,रेड्डी संख्या में कम्मा और कापू की तुलना में कम हैं। इसकी भरपाई के लिए जगन ने ओबीसी एवं एससी-एसटी वर्ग को लुभाने के लिए पांच वर्षों में कई योजनाएं चला रखी हैं, जो भाजपा-तेदेपा गठबंधन के सामने बड़ी चुनौती हैं। जगन की वाइएसआर कांग्रेस की इस जुगत से निपटने को भाजपा ने भी बड़ा दांव चला है। कम्मा समुदाय के चंद्र बाबू नायडू और कापू के पवन कल्याण के दलों से गठबंधन कर भाजपा ने जगन मोहन के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। राज्य की 25 प्रतिशत आबादी वाली कम्मा और 15 प्रतिशत आबादी वाली कापू जातियों के वोटरों का जमीनी स्तर पर अगर तालमेल हो गया तो 10 प्रतिशत आबादी वाली रेड्डी के लिए यह चुनाव आसान नहीं होगा। सच्चाई यह भी है कि आंध्र प्रदेश की राजनीति में कम्मा एवं कापू एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं।

आंध्र की आबादी का गणित: 2011 की जनगणना के अनुसार पांच करोड़ की आबादी वाले आंध्र प्रदेश में हिंदू 90.89 प्रतिशत, मुस्लिम 7.30 प्रतिशत और ईसाई 1.38 प्रतिशत हैं। हिंदुओं में अनुसूचित जाति की आबादी 17 प्रतिशत है। पिछड़ा वर्ग में 143 जातियां शामिल हैं, जिनकी संख्या लगभग 37 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त कापू और विभिन्न अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी लगभग 15 प्रतिशत है।

भाजपा का कापू और ओबीसी पर फोकस

भाजपा ने पहले से ही कापू व ओबीसी पर फोकस बढा रखा है। फिल्म 'बाहुबली' की पटकथा लिखने वाले केवी विजयेंद्र प्रसाद को राज्यसभा भेजकर डेढ़ वर्ष पहले ही चुनावी पिच तैयार कर दी थी। प्रसाद कापू समुदाय से आते हैं। पीएम नरेन्द्र मोदी यदि परिवारवादी दलों को टारगेट करते हैं तो उनकी सूची में जगन मोहन रेड्डी भी होते हैं, जिनके पिता राजशेखर रेड्डी ने राज्य में लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार चलाई। 2009 में उनके निधन और कांग्रेस में उपेक्षा के बाद जगन ने वाइएसआर कांग्रेस नाम से अलग पार्टी बनाई और सत्ता में आए। तेलंगाना की तरह आंध्र में प्रभाव बढाने में जुटी भाजपा को जातिवार गणना कराकर जगन मोहन ओबीसी विरोधी साबित करना और जातिगत गोलबंदी के जरिए हिंदुत्व के एजेंडे में सेंध लगाना चाहते हैं।

- **कम्मा और कापू अगर एक हो गए तो जगन रेड्डी को हो सकती है मुश्किल**
- **ओबीसी व एससी-एसटी को लुभाने को जगन की योजनाएं भाजपा-तेदेपा के लिए चुनौती**

जगन मोहन रेड्डी

पवन कल्याण

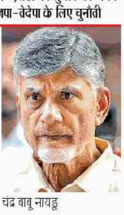

चंद्र बाबू नायडू

कम्मा की संख्या सर्वाधिक: आंध्र प्रदेश में कम्मा संपन्न एवं प्रभावशाली हैं। संख्या भी सर्वाधिक है। तेलुगु देसद पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष चंद्र बाबू नायडू इसी समुदाय के हैं। सबसे पहले तेलुगु फिल्मों से राजनीति में आए एनटी रामाराव ने राजनीति में रेड्डी के वर्चस्व के विरुद्ध कम्मा को एकजुट किया। सत्ता की भूख जगाई। रेड्डी के प्रभाव की प्रतिक्रिया में कापू ने भी एनटी रामाराव का साथ दिया था। लिहाजा 1983 में सत्ता रेड्डी से फिसल कर कम्मा के पास आ गई। तबसे इन्हीं दोनों समुदायों के नेताओं के हाथ में सत्ता आती और जाती रही है।

40 विस क्षेत्रों में कापू का दबदबा: कापू जाति पिछड़ी जातियों में सबसे प्रमुख है। इसकी कुछ उपजातियां सवर्ण में भी आती हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व अभी जन सेना पार्टी के पवन कल्याण कर रहे हैं, जो मुन्नुरू उपजाति से हैं। पवन भी फिल्मों से राजनीति में आए हैं। अपने बड़े भाई चिरंजीव की प्रजा राज्यम पार्टी से राजनीति की शुरुआत की थी। चिरंजीव उस समय असफल हो गए, जब वर्ष 2011 में उन्होंने अपने दल का विलय कांग्रेस में कर दिया। अब पवन कापू लोगों में राजनीतिक भूख जगाने में जुटे हैं। राज्य के लगभग 40 विस क्षेत्रों में कापू का दबदबा है।

रेड्डी आंध्र प्रदेश की तीसरी बड़ी आबादी: रेड्डी आंध्र प्रदेश की तीसरी बड़ी आबादी है, जिसने जातीय अस्मिता के नाम पर राज्य की राजनीति में वर्चस्व बनाकर रखा है। यह बेहद संपन्न एवं उच्च शिक्षित है, जो राजनीतिक रूप से बेहद सक्रिय है। आबादी 10 प्रतिशत है, लेकिन विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटों पर इनका ही कब्जा रहता है। इस जाति से अभी तक 12 मुख्यमंत्री हो चुके हैं। हालांकि धर्म के आधार पर यह जाति विभाजित है। जगन मोहन स्वयं ईसाई हैं। भाजपा उन पर ईसाइयों के तुष्टीकरण का आरोप भी लगाती रही है।

****

15 मार्च को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैदराबाद में रोड शो करेंगे। तेलंगाना में 17 और 18 मार्च को रैलियों को संबोधित करेंगे। भाजपा सूत्रों के अनुसार मिजगिरी से मलकाजगिरि तक शुक्रवार शाम एक घंटे तक रोड शो चलेगा।

बंगाल में कांग्रेस को वाममोर्चा ने भी दिया झटका, उतारे 16 प्रत्याशी

सियासी विश्लेषक इसे बता रहे वाममोर्चा की कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस गत रविवार को बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर चुकी है, जिसके बाद कांग्रेस-वाममोर्चा में समझौते की उम्मीद जगी थी लेकिन वाममोर्चा ने गुरुवार को अचानक 16 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर कांग्रेस को एक और झटका दिया है। वाममोर्चा की सूची में 13 प्रत्याशी माकपा व भाकपा, आरएसपी व फारवर्ड ब्लाक से एक-एक हैं। 16 में से 14 नए चेहरे हैं। वाममोर्चा के अध्यक्ष बिमान बसु ने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करते हुए कहा कि सीट बंटवारे पर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के साथ बातचीत बेनतीजा रही है। हालांकि उन्होंने आगे यह भी कहा कि सीट बंटवारे के फार्मूले पर चर्चा के लिए कांग्रेस के लिए दरवाजा अब भी खुला है। कांग्रेस व्यावहारिक प्रस्ताव लाए तो समझौता हो सकता है। वाममोर्चा अभी भी गठबंधन की संभावना से इन्कार नहीं कर रहा है। सियासी विश्लेषक इसे वाममोर्चा की कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति बता रहे हैं। दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वाममोर्चा के साथ राज्य स्तर पर कोई बात नहीं हुई है।

नए चेहरों का अभाव, आप ने पंजाब से पांच मंत्री उतारे मैदान में

इन्द्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

आम आदमी पार्टी ने वीरवार को लोकसभा चुनाव में पंजाब की कुल 13 सीटों में से आठ पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की ओर से जारी की गई पहली सूची में नए चेहरों के अभाव में पार्टी ने पांच दिग्गज मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारा है। साफ है कि पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को जिताकर संसद में पहुंचाना चाहती है। इस सूची में पांच मंत्रियों के अलावा दो कांग्रेस से आप में शामिल हुए पूर्व विधायक और एक कलाकार भी हैं।

आम आदमी पार्टी की ओर से जिन पांच मंत्रियों को चुनाव में उतारा है, इनमें खेल मंत्री गुरमीत हेयर संगरूर, एनआरआइ मामलों के मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल अमृतसर, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर खडूर साहिब, कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां बठिंडा और स्वास्थ्य मंत्री डा. बलबीर सिंह पटियाला से पार्टी के प्रत्याशी होंगे।

इसके अलावा आप ने कांग्रेस से आप में शामिल हुए दो पूर्व विधायकों आप के जालंधर से मौजूदा सांसद सुशील रिंकू को एक बार फिर से जालंधर और हाल ही में आप में शामिल हुए बस्सी पठाणा के पूर्व विधायक गुरप्रीत सिंह जीपी को फतेहगढ़ साहिब से टिकट दिया गया है। इसी तरह फरीदकोट से मुख्यमंत्री के करीबी करमजीत अनमोल को टिकट दी गई है। दिलचस्प बात यह है कि अगर इन पांच मंत्रियों में से कोई भी जीतता है तो उक्त विधानसभा क्षेत्र के लोगों को उपचुनाव के लिए भी तैयार रहना होगा।

पंजाब की चार प्रमुख पार्टियों में से अभी तक केवल आम आदमी पार्टी ने ही अपने पत्ते खोले हैं जबकि इससे पहले शिरोमणि अकाली दल ही सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करता था। चूंकि अभी उनकी भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से चुनावी गठबंधन होने की बातचीत चल रही है इसलिए पार्टी ने अभी तक किसी भी सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। आम आदमी पार्टी के दिग्गज मंत्रियों को चुनाव मैदान में उतारने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस भी अपने दिग्गज विधायकों को भी चुनावी रण में उतार सकती है।

- आम आदमी पार्टी ने की पंजाब में आठ प्रत्याशियों की घोषणा
- एक कलाकार और दो कांग्रेस से आए नेताओं को दी टिकट

कुलदीप सिंह धालीवाल। लालजीत सिंह भुल्लर। गुरमीत सिंह खुड्डियां। गुरमीत हेयर। फाइल बलबीर सिंह।

बीआरएस ने की दो और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा

हैदराबाद, प्रेट्र: भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूर्व विधायक अत्राम सक्कू को आदिलाबाद और रागिदी लक्ष्मा रेड्डी को मल्काजगिरी निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार घोषित किया। बीआरएस अब तक तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में से 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है। सक्कू आसिफाबाद से पूर्व विधायक हैं और लक्ष्मा रेड्डी गत वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीआरएस में शामिल हुए थे।

बता दें कि बीआरएस ने कहा था कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए तेलंगाना में बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के साथ गठबंधन करेगी। बीआरएस ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राज्य से सटे हुए महाराष्ट्र के इलाकों से भी प्रचार शुरू किया था। ताकि वहां से भी उम्मीदवार उतारे जा सकें।

गठबंधन को लेकर बयान पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिल्ली तलब

जासं, भुवनेश्वर : ओडिशा में गुरुवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल द्वारा भाजपा और बीजू जनता दल में चुनावी गठबंधन नहीं होने से संबंधित बयान देने के चंद घंटे बाद ही उन्हें पार्टी ने दिल्ली तलब कर लिया। मनमोहन गुरुवार को भुवनेश्वर से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं, दिल्ली तलब किए जाने के साथ ही उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से ओडिशा में अकेले चुनाव लड़ने से संबंधित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। बता दें कि सामल पूर्व में भी कह चुके हैं कि भाजपा और बीजद के बीच गठबंधन नहीं होने के आशय का बयान दे चुके हैं। मनमोहन ने कहा था कि भाजपा ओडिशा में बिना किसी दल के समर्थन के अकेले सरकार बनाएगी। साथ ही लोकसभा का चुनाव भी पार्टी अकेले अपने दम पर लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि शुक्रवार को पार्टी की चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम संसदीय बोर्ड के पास भेजा जाएगा।

मनमोहन सामल

तेदेपा ने 34 और सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की

अमरावती, प्रेट्र: तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो एन. चंद्रबाबू नायडू ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 34 और सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों की दूसरी सूची की घोषणा की। कुछ नये नामों के साथ तेदेपा अब तक 128 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब पार्टी को 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है। राजग गठबंधन में शामिल तेदेपा 175 सदस्यीय आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए 144 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तेदेपा प्रमुख ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करने की जानकारी एक्स पोस्ट पर देते हुए कहा कि 34 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में जनता की राय को प्रमुखता दी गई है। उन्होंने लोगों से तेदेपा उम्मीदवारों को आशीर्वाद देकर चुनाव उनकी जीत सुनिश्चित करने का आह्वान किया। अभी हाल ही में राजग में शामिल सहयोगियों के बीच लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा तय हुआ है। इसके तहत भाजपा आंध्र प्रदेश में छह सीटों पर लोकसभा और 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। तेदेपा को लोकसभा के लिए 17 और 144 विधानसभा सीटें व पवन कल्याण की पार्टी जनसेना को दो लोकसभा सीटें व 21 विधानसभा सीटें मिली हैं। इधर, जनसेना के मुखिया पवन कल्याण ने गुरुवार को आगामी विधानसभा चुनाव में पीथापुरम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने मुझसे आगामी चुनाव में लोकसभा सीट के लिए लड़ने को कहा और कुछ ने मेरे लिए विधायक के रूप में विधानसभा जाने की कामना की।

- पार्टी को 16 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा करनी है
- भाजपा आंध्र प्रदेश में छह सीटों पर लोकसभा और 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी

परनीत कौर के भाजपा में शामिल होने से कांग्रेस के लिए गढ़ बचाने की चुनौती

कैलाश नाथ, चंडीगढ़

पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी और पटियाला से कांग्रेस सांसद परनीत कौर ने गुरुवार को भाजपा की सदस्यता ले ली। उनका भाजपा में आना औपचारिकता भर थी, लेकिन इस प्रतीकात्मक घटना से भी कांग्रेस की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पटियाला हमेशा से कांग्रेस का मजबूत गढ़ रहा है और पांच दशकों से उसकी राजनीति मोती महल (कैप्टन के निवास) के इर्द-गिर्द घूमती रही है। इस लोकसभा सीट पर 16 बार हुए चुनाव में कांग्रेस ने दस बार जीत हासिल की है। इसमें छह बार शाही घराना (कैप्टन का परिवार) जीता है। कैप्टन अमरिंदर के भाजपा में जाने के बाद से माना जा रहा था कि परनीत कौर भी भाजपा में शामिल होंगी। परनीत ने काफी लंबा समय लिया और बीते बुधवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक रूप से इस सीट पर शाही परिवार का दबदबा रहा है। शाही घराने की तीसरी पीढ़ी जय इंदर कौर भी अब सक्रिय हो गई हैं। पटियाला सीट पर 1967 में शाही घराने की एंट्री हुई। इस चुनाव में मोहिंदर कौर (कैप्टन की मां) विजयी रहीं। 1977 में कैप्टन अमरिंदर सिंह पहली बार इस सीट से लड़े लेकिन उन्हें अकाली दल के कद्दावर नेता गुरचरण टोहरा के हाथों हार का सामना करना पड़ा। 1980 के चुनाव में उन्होंने विजय हासिल की। 1999 से 2019 तक के पांच लोकसभा चुनाव में चार बार परनीत कौर जीत चुकी हैं। 2014 में वह आप के धरमवीर गांधी से हार गई थीं।

नवजोत सिद्धू पर दांव खेल सकती है कांग्रेस: कैप्टन के कांग्रेस से जाने के बाद से ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर छोड़ पटियाला में वापसी कर चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस के पास इस सीट पर सिद्धू ही एक मात्र मजबूत विकल्प हैं। पंजाब कांग्रेस भी सिद्धू का नाम प्रस्तावित कर रही है।

दल बदल

कैप्शन: परनीत कौर का पार्टी में स्वागत करते भाजपा के प्रदेश प्रभारी विजय रूपाणी। साथ में प्रदेश प्रधान सुनील जाखड़। स्रत

आज भाजपा में शामिल होंगे टीएमसी सांसद दिब्येंदु व अर्जुन सिंह

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस द्वारा टिकट नहीं दिए जाने से नाराज चल रहे बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह फिर से भाजपा में लौटने जा रहे हैं। शुक्रवार को नई दिल्ली में वह औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाएंगे। अर्जुन ने गुरुवार को मीडिया को खुद इसकी जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु के भाई व तृणमूल कांग्रेस सांसद दिव्येंदु अधिकारी भी अर्जुन सिंह के साथ दिल्ली पहुंच गए हैं। वह भी भाजपा में शामिल होंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर दो साल पहले तृणमूल में वापसी करने वाले अर्जुन के एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर बैरकपुर से चुनाव लड़ने की बात है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बात हुई है।

कांग्रेस को झटका, पूर्व एथलीट पद्मिनी थामस भाजपा में शामिल

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र: केरल में कांग्रेस को एक और झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री करुणाकरन की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल के बाद गुरुवार को पूर्व एथलीट पद्मिनी थामस भी कांग्रेस से किनारा कर भाजपा में शामिल हो गई। इस दौरान उनके साथ तिरुअनंतपुरम जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव थंपनूर सतीश ने भी भाजपा की सदस्यता ली। 1982 के एशियाई खेलों में रजत और कांस्य पदक जीतने वाली थामस ने कहा कि वह कांग्रेस में तंग आ चुकी थी। अर्जुन अवार्ड विजेता ने कहा कि मैं किसी पद के लिए भाजपा में शामिल नहीं हुई हूं। महिलाओं को प्राथमिकता और आरक्षण देने के कारण मैं मोदी सरकार से खुश और प्रभावित हूं। इस दौरान सतीश ने आरोप लगाया कि पार्टी के दिग्गज के. करुणाकरन की मौत के बाद ही कांग्रेस का पतन शुरू हो गया था।

केंद्र के दावे पर अभिषेक ने दी बहस की चुनौती, भाजपा का मंच साझा करने से इन्कार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने केंद्र की ओर से बंगाल को पिछले पांच वर्षों में विभिन्न योजनाओं के लिए 5.36 लाख करोड़ रुपये दिए जाने के दावे पर गुरुवार को भाजपा को खुली बहस की चुनौती दी। भाजपा की बंगाल इकाई की ओर से चुनौती स्वीकार कर ली गई लेकिन बहस के लिए कोई नहीं पहुंचा। भाजपा की ओर से कहा गया कि आप (अभिषेक) जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के साथ एक फ्रेम में आने में भाजपा कार्यकर्ता खुद को अपमानित करने जैसा मानते हैं। इसपर तृणमूल की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि भाजपा को इस मामले में यू टर्न लेने में एक घंटा भी नहीं लगा। लगता है कि डर गई। मालूम हो कि केंद्र की ओर से विज्ञापन देकर बंगाल के लिए 5.36 लाख करोड़ रुपये जारी करने का दावा किया गया है। इसपर अभिषेक ने एक्स पर लिखा-'भाजपा झूठ फैलाने के लिए सरकारी फंड का अपव्यय कर रही है। मैं भाजपा नेतृत्व को अपने साथ बहस की चुनौती देता हूं। साथ में यह भी चुनौती देता हूं कि 2021 का बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद से अगर केंद्र ने आवास योजना व मनरेगा के लिए एक भी पैसा दिया है तो श्वेतपत्र जारी करके इसे साबित करें।'

इसके जवाब में बंगाल भाजपा की ओर से एक्स पर कहा गया-'आप (अभिषेक) अपने समय व सुविधानुसार जगह बता दें। हम बहस के लिए अपने युवा मोर्चा के किसी कार्यकर्ता को भेज देंगे।' चूंकि अभिषेक उत्तर बंगाल के दौरे पर हैं इसलिए उन्होंने मयनागुड़ी की सभा में बहस के लिए आमंत्रित किया लेकिन वहां भाजपा का कोई प्रतिनिधि नहीं पहुंचा। भाजपा ने कारण बताते हुए कहा कि उनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अभिषेक बनर्जी जैसे भ्रष्ट व्यक्ति के साथ मंच साझा नहीं करना चाहते।

- केंद्र की ओर से बंगाल को विभिन्न योजनाओं के लिए 5.36 लाख करोड़ रुपये दिए जाने का किया गया है दावा

बंगाल

ट्रेडमिल पर वाक के दौरान गिरने से घायल बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। एएनआइ

घर पर टहलते समय गिरने से घायल हुईं ममता बनर्जी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गुरुवार शाम अपने घर पर टहलने के दौरान गिरने से घायल हो गईं। उन्हें कोलकाता के सरकारी एसएसकेएम अस्पताल में देर शाम भर्ती कराया गया। इसकी जानकारी उनकी पार्टी तृणमूल की ओर से दी गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी मुख्यमंत्री के स्वस्थ्य होने की कामना की। वहीं, पीएम नरेन्द्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर ममता के शीघ्र स्वस्थ्य होने और सर्वोत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की है। बताया गया कि मुख्यमंत्री शाम को कोलकाता में एक कार्यक्रम से लौटकर अपने कालीघाट स्थित आवास पर टहल रही थीं। टहलते समय वह अचानक गिर गईं, जिससे उनके माथे में चोट आई। तृणमूल ने एक्स पर ममता के घायल होने की तस्वीर साझा की, जिसमें देखा जा सकता है कि वह अस्पताल में बेड पर हैं और उनके माथे से खून निकल रहा है। घटना के वक्त सांसद अभिषेक बनर्जी वहां मौजूद थे।

बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर लगी मुहर, आज घोषणा संभव

राज्य ब्यूरो, पटना

बिहार के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर मुहर लग गई है। शुक्रवार को इसकी घोषणा संभव है। विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव में चुने जाने के बाद अपना प्रमाण पत्र लेकर लौटने के क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इसपर काम हो रहा है, आज रात ही सबकुछ तय हो जाएगा। सीट शेयरिंग के फार्मूले के बारे में मिली जानकारी के अनुसार राज्य की लोकसभा की कुल 40 में जदयू 16 और भाजपा 17 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। लोजपा (रामविलास) को चार सीटें देने पर पूर्व से सहमति है। वहीं तीन सीटों का विभाजन हम, रालोजपा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच होगा। हम को एक, उपेंद्र कुशवाहा को एक और पशुपति पारस को एक सीट मिल सकती है।

बिहार

- जदयू 16, भाजपा 17 और लोजपा (रा) चार सीटों पर लड़ सकती है चुनाव
- रालोजपा, हम और रालोमो को मिल सकती एक-एक सीट

जदयू झारखंड में भी चाह रहा एक सीट: एनडीए सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जदयू झारखंड में भी एक सीट चाह रहा है। नीतीश कुमार के करीबी रहे बिहार के एक नेता को जदयू अपने टिकट पर मैदान में उतारना चाहता है। वह झारखंड में भी एक सीट चाह रहा है। अगर जदयू को झारखंड की एक सीट मिल जाती है तो बिहार में उसे 15 सीट दिए जाने की चर्चा है।

कुछ सीटों की आपस में हो सकती अदला-बदली: एनडीए में जदयू, भाजपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, रालोजपा और हम के बीच आपस में सीटों की अदला-बदली हो सकती है। ऐसी चर्चा है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के टिकट पर कुशवाहा लड़ना चाहते हैं।

फिल्म अभिनेता राज बब्बर को हरियाणा से चुनाव लड़ा सकती कांग्रेस

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

हरियाणा कांग्रेस की तीसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में राज्य की नौ लोकसभा सीटों के लिए फाइनल पैनल तैयार कर लिए गए हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट के लिए एक-दो नामों के पैनल तैयार हुए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की 18 मार्च को होने वाली बैठक में हरियाणा के इन पैनलों पर चर्चा होगी, जिसके बाद उसी दिन आधा दर्जन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। फिल्म अभिनेता और वरिष्ठ कांग्रेस नेता राज बब्बर को इस बार हरियाणा की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़वाया जा सकता है।

कांग्रेस के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाईकमान यदि राज बब्बर को हरियाणा से चुनाव लड़वाने पर राजी हुआ तो उन्हें फरीदाबाद, गुरुग्राम और करनाल लोकसभा सीटों की पेशकश की जा सकती है। फरीदाबाद व गुरुग्राम लोकसभा सीटें दिल्ली के नजदीक हैं, जबकि करनाल सीट पर निवर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के पास यहां सरदार त्रिलोचन सिंह के रूप में भी मजबूत उम्मीदवार है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा यहां तक है कि यदि किसी कारण से भाजपा ने रोहतक में मौजूदा सांसद डा. अरविंद शर्मा को टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस उन्हें करनाल से मनोहर लाल के सामने उतार सकती है, लेकिन यह बाद की बात है। हरियाणा की नई दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में चेयरमैन भगत चरण दास, कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया, पूर्व सीएम और विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कमेटी की सदस्य यशोमति ठाकुर व नीरज डांगी मौजूद रहे। एक लोकसभा सीट कुरुक्षेत्र आम आदमी पार्टी को दी जा चुकी है। इसलिए नौ लोकसभा सीटों के पैनल बनाए जा चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने हालांकि लोकसभा चुनाव लड़ने में अधिक रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन बताया जाता है कि कांग्रेस हाईकमान वरिष्ठ नेताओं के नाम पर विचार करेगा। कांग्रेस की रणनीति ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीतने की है। इसके लिए वह वरिष्ठ नेताओं को भी चुनावी रण में उतार सकती है। बैठक के बाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी की तीसरी बैठक में फाइनल पैनल तैयार किए हैं।

हरियाणा

- प्रदेश की नौ लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने पैनल तैयार किए

राबड़ी देवी का बागवानी करता वीडियो प्रचारित

राज्य, पटना: नीतीश के मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक वीडियो एक्स मीडिया पर काफी प्रचारित हुआ। इस वीडियो में राबड़ी देवी अपने आवास में बागवानी करती दिख रही हैं। उनके इस वीडियो को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी अपने एक्स मीडिया पर पोस्ट किया है और लिखा है मां। राबड़ी देवी ने अपने इस वीडियो के साथ एक्स मीडिया पर लिखा कि जड़ों से जुड़ाव ही जीवन की सच्चाई और गहराई से परिचय कराता है।

आदिवासी वर्ग दे सकता है भाजपा को 'अजेय' होने का मंत्र

धनंजय प्रताप सिंह, भोपाल

लोकसभा चुनाव को जीत-हार के लक्ष्य से परे 'अबकी बार 400 पार' का नारा लेकर भाजपा अगर आगे बढ़ रही है तो तैयारी भी एक-एक सीट पर जीत के लिए की जा रही है, विशेषकर हिंदीभाषी राज्यों में, जहां पार्टी वोट शेयर 50 प्रतिशत से अधिक पहुंचाकर अजेय बनने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है। इसके लिए ओबीसी और आदिवासी की जुगलबंदी पर फोकस किया जा रहा है। मध्यप्रदेश में 29 में से तीन आदिवासी महिलाओं और नौ ओबीसी को पार्टी ने टिकट दिया है।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को देश में 37.7 प्रतिशत वोट हासिल हुए थे। दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में सभी सीटें जीतकर भाजपा ने 55 प्रतिशत से ज्यादा वोट शेयर प्राप्त किया था, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश में एक-एक सीट छोड़कर सभी सीटें भाजपा ने जीतीं। झारखंड में भी 14 में से 11 सीटें भाजपा ने जीती। उत्तर प्रदेश सहित इन सभी राज्यों में भाजपा का वोट शेयर 55 से 58 प्रतिशत था। मध्य प्रदेश में सियासत की धुरी भले ही आदिवासी वर्ग न बन पाया हो, लेकिन सत्ता का रास्ता आदिवासी ही दिखाते रहे हैं। पिछले चार दशक में जिस पार्टी के साथ आदिवासी वर्ग चला, सत्ता की चाबी उसे ही मिली। इस बीच भाजपा ने लंबे दौर तक ओबीसी मुख्यमंत्री देकर इस वर्ग में भी अपनी बढ़ी पैठ बना ली। उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव भी ओबीसी वर्ग से ही आते हैं। बीते विधानसभा चुनाव में जिन सीटों पर आदिवासी वर्ग का प्रभाव था, वहां भाजपा ने खासी सफलता हासिल की है। ऐसे में ओबीसी और आदिवासी वर्ग को साथ लेकर अजेय बनने का मंत्र मध्य प्रदेश में भाजपा को बड़ी सफलता दिला सकता है। इस फार्मूले को भाजपा अन्य राज्यों में भी लागू कर रही है।

प्रतीकात्मक

- मप्र में तीन आदिवासी महिलाओं व नौ ओबीसी को पार्टी ने दिया टिकट
- हिंदीभाषी राज्यों में बड़ी जीत की रणनीति पर आगे बढ़ रही है भाजपा

भाजपा की डबल इंजन सरकार ने लगातार जनजाति वर्ग की बुनियादी समस्याओं का समाधान देते हुए उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। राष्ट्र के विकास में उनकी भागीदारी बढ़ रही है। निशुल्क राशन, पक्का मकान, आयुष्मान भारत में पांच लाख के स्वास्थ्य बीमा से लेकर नई पीढ़ी को पढ़ने और बढ़ने के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। इस वर्ग की महिलाएं शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आत्मविश्वास से समाज से कदमताल कर रही हैं। राजनीतिक भागीदारी, पंचायत से लेकर सरपंच और संसद तक में मौका मिल रहा है। राष्ट्रपति भवन में भी महिला की गरिमामई उपस्थिति हुई है, लेकिन कांग्रेस आज भी भरमाने की राजनीति करते हुए इस वर्ग में अलगाव की भावना भरने की नाकाम कोशिश कर रही है। -रजनीश अग्रवाल, प्रदेश मंत्री भाजपा

कांग्रेस को नहीं मिली इन वर्गों में बढ़त: विधानसभा चुनाव के परिणाम में देखें तो कांग्रेस ने ओबीसी और आदिवासी वर्ग के बीच कोई बढ़त हासिल नहीं की है, बल्कि नुकसान ही हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा को इन दोनों वर्गों का साथ मिल रहा है। राष्ट्रपति चुनाव से लेकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का नाम तय करने तक भाजपा ने इन दोनों वर्गों को महत्व देकर जो संदेश दिया है, उसका प्रभाव ही, इसकी तैयारी है।

पत्नी ने उतारी गडकरी की आरती...

भाजपा की दूसरी सूची में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने पर गुरुवार को नागपुर में अपने आवास पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का उनकी धर्मपत्नी कंचन और अन्य स्वजनों ने कुछ इस तरह विधिवत स्वागत किया। प्रेट्र

11 उम्मीदवार बिहार विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राजद से चार, माले एक, भाजपा तीन, जदयू दो एवं हम से एक उम्मीदवार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की ओर से अधिकृत भोला यादव ने उनका प्रमाण पत्र लिया।

सत्ता में आने पर आइएनडीआइए बनेगा किसानों की आवाज : राहुल गांधी

यात्रा ▸ कृषि को जीएसटी से बाहर करने व फसल बीमा योजना के पुनर्गठन का किया वादा

शरद पवार बोले, उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान कर रहे आत्महत्या

नासिक जिले के चांदवाड में किसान महापंचायत के दौरान राकांपा प्रमुख शरद पवार से चर्चा करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी। प्रेट्र

राज्य ब्यूरो, मुंबई: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि अगर विपक्षी दलों का गठबंधन आइएनडीआइए सत्ता में आता है तो वह किसानों की आवाज बनेगा और उनकी रक्षा के लिए नीतियां बनाएगा। उन्होंने कृषि को जीएसटी से बाहर करने और फसल बीमा योजना का पुनर्गठन करने का वादा भी किया।

राहुल गांधी अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान नासिक जिले के चांदवाड में एक किसान रैली को संबोधित कर रहे थे। इस रैली में उनके साथ राकांपा (शरदचंद्र पवार) प्रमुख शरद पवार और शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत भी शामिल थे। राहुल ने कहा कि सत्ता में आने पर उनके और आइएनडीआइए के दरवाजे किसानों के लिए हमेशा खुले रहेंगे।

महाराष्ट्र

उन्होंने किसानों से ऋण माफी, फसल बीमा योजना के पुनर्गठन, कृषि को जीएसटी से बाहर करने और केवल एक कर पर काम करने के प्रयास का वादा किया। राहुल गांधी ने स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानूनी गारंटी देने के कांग्रेस के वादे को दोहराया। उन्होंने किसानों को याद दिलाया कि पिछली कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने किसानों का 70,000 करोड़ रुपये का कर्ज माफ किया था। जबकि नरेन्द्र मोदी सरकार ने उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया जो मनरेगा की 24 वर्षों की धनराशि के बराबर है।

उन्होंने कहा, 'जैसे सैनिक हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, किसान देश के भीतर नागरिकों की रक्षा करते हैं। अगर हम अपने जवानों और किसानों की रक्षा नहीं करेंगे तो देश प्रगति नहीं कर सकता।' राहुल ने कहा, 'देश में आज किसान, महंगाई, बेरोजगारी और अग्निवीर के मुद्दे हैं, लेकिन टीवी चैनलों पर आपको कभी इन मुद्दों पर चर्चा दिखाई नहीं देगी। इसके बजाय टीवी चैनल 24 घंटे प्रधानमंत्री मोदी को दिखाते हैं, कभी वह पूजा करने के लिए समुद्र के नीचे जाते हैं और टीवी कैमरे उनके साथ जाते हैं, उसके बाद वह सी प्लेन पर उड़ान भरते हैं। बाद में वह चीन सीमा पर जाएंगे और मीडिया उनके पीछे जाएगा। फिर वह पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। उसके बाद कोविड-19 महामारी आएगी और सब ताली व बर्तन बजाएंगे। वह हर किसी को नाच नचाएंगे।'

राकांपा (शरदचंद्र पवार) नेता शरद पवार ने केंद्र सरकार पर किसानों और कृषि क्षेत्र की दुर्दशा के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण किसान कर्ज में डूबे हुए हैं और आत्महत्या कर रहे हैं।

पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि महंगाई को आमंत्रित करने वाली किसान विरोधी और युवा विरोधी सरकार को हराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा कि महाविकास आघाड़ी (एमवीए) लोगों के हितों के लिए संघर्ष में राहुल गांधी के साथ है।

बता दें कि एमवीए में कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और राकांपा (शरदचंद्र पवार) शामिल हैं। ये राष्ट्रीय स्तर के विपक्षी गठबंधन आइएनडीआइए का हिस्सा हैं। बाद में कांग्रेस महासचिव और पार्टी के संचार प्रभारी जयराम रमेश ने पत्रकारों से कहा कि अगर इस साल के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन सरकार बनाता है तो ऋण माफी की मात्रा तय करने के लिए एक अलग आयोग का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में एक नई फसल बीमा योजना भी बनाई जाएगी।

त्र्यंबकेश्वर मंदिर में की पूजा-अर्चना

राहुल गांधी ने बाद में नासिक में रोडशो और नुक्कड़ सभा की जिसमें उन्होंने जातिगत गणना की मांग दोहराई। वह त्र्यंबकेश्वर मंदिर भी गए और वहां पूजा-अर्चना की। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है।

चंदा जुटाने में भाजपा ने किया एजेंसियों का दुरुपयो : कांग्रेस

नई दिल्ली, प्रेट्र: कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि भाजपा ने 45 कंपनियों पर छापेमारी के बाद उनसे चुनावी बांड के जरिये 400 करोड़ रुपये जुटाने के लिए ईडी और सीबीआइ जैसी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा, हालिया जांच से पता चला है कि छापेमारी किए जाने के बाद 15 और कंपनियों ने भाजपा को चंदा दिया।

अजीत गुट को शरद पवार का फोटो व नाम उपयोग नहीं करने का निर्देश

राकांपा विवाद

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट की शिकायत पर अजीत गुट से मांगा जवाब

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दो गुटों में बंटने के बाद भी झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। अब चाचा शरद पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर राकांपा से अलग हो गए अजीत पवार गुट पर शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अजीत गुट से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि जब उन्होंने अलग पहचान बना ली है तो उन्हें शरद पवार की फोटो और नाम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने अजीत पवार गुट को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में शनिवार तक कोर्ट में हलफनामा दाखिल करें कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल नहीं करेंगे।

ये निर्देश गुरुवार को जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की पीठ ने शरद गुट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलें सुनने के बाद दिए। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा ये लोग घड़ी चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं जो प्रतीक ऐतिहासिक रूप से शरद पवार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अजीत पवार गुट के एक नेता के बयान का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण मतदाताओं को लुभाने के लिए पोस्टर में घड़ी चिन्ह और शरद पवार की फोटो का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इस पर पीठ ने मनिंदर सिंह से पूछा कि आप उनकी फोटो का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? मनिंदर सिंह ने कहा कि पार्टी ऐसा नहीं कर रही है, हो सकता है कुछ भटके हुए सदस्यों ने ऐसा किया हो। इंटरनेट मीडिया पर सभी पोस्टरों को नियंत्रित करना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सदस्यों को अनुशासित करे।

'यशवंत राव चह्वाण के नाम और फोटो का उपयोग किया शुरू'

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि उनके चाचा शरद पवार की आपत्ति के बाद उनकी पार्टी ने महाराष्ट्र के पहले मुख्यमंत्री यशवंत राव चाह्वाण के नाम और फोटो का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। पुणे में एक कार्यक्रम में अजीत पवार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के बाद गुरुवार की शाम संवाददाताओं से कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना के गठबंधन की सरकार से जुड़ने के बाद उनकी पार्टी ने शरद पवार के नाम और फोटो का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब उन्होंने आपत्ति जताई और कार्रवाई करने की चेतावनी दी तो ऐसा करना बंद कर दिया था। अब हम यशवंत राव चाह्वाण की फोटो और नाम के साथ जा रहे हैं।

मोदी सरकार 370 हटा सकती है तो कश्मीरी हिंदुओं का घाटी में स्थायी पुनर्वास भी संभव : पूनिया

राज्य ब्यूरो, जम्मू

▸ **जम्मू पहुंचे भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य ने विपक्षी दलों पर भ्रम फैलाने का आरोप जड़ा**

▸ **भाजपा का संकल्प पत्र तैयार करने के लिए लोगों की उम्मीदें जानी, पूरा करने का भरोसा भी दिया**

भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा. सतीश पूनिया ने कहा है कि मोदी सरकार अगर अनुच्छेद 370 हटा सकती है तो कश्मीरी हिंदुओं का घाटी में स्थायी पुनर्वास भी संभव कर सकती है। जम्मू में कश्मीरी हिंदुओं से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि कश्मीरी हिंदुओं ने दंश झेला है, केंद्र सरकार उनकी हर मांग को पूरा करेगी।

जम्मू-कश्मीर

भाजपा के संकल्प पत्र के लिए लोगों की उम्मीदें जानने पूनिया वीरवार को जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं, व्यापारी संगठनों के प्रतिनिधियों व दिव्यांगों से अलग-अलग बैठकें कर उनकी उम्मीदें जानीं। उन्होंने कहा कि इन उम्मीदों को भाजपा के चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने के लिए पार्टी हाईकमान को सौंपा जाएगा। उन्होंने भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं से बैठक कर लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रचार को तेजी देने में पूरा सहयोग दिया जाएगा।

विभिन्न लोगों से मुलाकात के बाद पूनिया ने प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता की और विपक्षी दलों पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 370 हटाने, राम मंदिर बनाने व नागरिकता संशोधन कानून लाने वाली मोदी सरकार कश्मीरी हिंदुओं का कश्मीर में पुनर्वास को भी संभव कर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे नेताओं को छोड़कर इस कानून से सभी धर्मों के लोग खुश हैं। इस मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के बयान देशद्रोह से कम नहीं हैं। प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले भारतवंशी हिंदू विस्थापितों की पीड़ा कम की है। वे अपने देश की मिट्टी में अंतिम सांस लेना चाहते हैं, अपने पुरखों के देश में आकर रहने की उनकी मांग पूरी की है। इससे हिंदू, मुस्लिम, सिख खुश हैं। मुस्लिम संगठन इसकी सराहना कर रहे हैं। इस मौके पर जम्मू-रियासी लोकसभा सीट के प्रत्याशी जुगल किशोर शर्मा, वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा, प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता सुनील सेठी, प्रवक्ता अभिनव शर्मा, जम्मू के पूर्व मेयर चन्द्रमोहन गुप्ता भी मौजूद रहे।

सतीश पूनिया। फाइल

जम्मू के व्यापारियों के हितों के संरक्षण का भरोसा: पूनिया ने कश्मीरी हिंदुओं, व्यापारियों व दिव्यांगों के संगठनों से बैठकें कर उनकी आकांक्षाएं समझीं। उन्होंने कहा कि यह सही है कि रेलगाड़ी, नेशनल हाईवे से पर्यटकों के सीधे कटड़ा चले जाने से जम्मू के व्यापार पर प्रभाव पड़ा है। भरोसा रखें कि व्यापारियों के हितों का संरक्षण किया जाएगा।

10 वर्षों में जम्मू-कश्मीर का हुआ कायाकल्प: पूनिया ने कहा कि पहले की सरकारों ने स्वार्थी नीतियों से जम्मू व कश्मीर के लोगों का भविष्य अंधकारमय बनाने की कोशिश की थी। अब मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश का कायाकल्प हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब श्रीनगर में लाल चौक पर तिरंगा लहरा रहा है। महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कश्मीर की सड़कों पर क्रिकेट खेल रहे हैं। यह बदलाव मोदी सरकार ने लाया है। देशवासियों ने केंद्रीय योजनाओं से कश्मीर व पूर्वोत्तर में आए बेहतर बदलाव को देखा व महसूस किया है।

वडोदरा में प्रत्याशी का विरोध करने पर भाजपा की महिला नेता निलंबित

राज्य ब्यूरो, अहमदाबाद: वडोदरा से सांसद तथा भाजपा उम्मीदवार डा रंजन भट्ट का विरोध करने के चलते महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. ज्योति पंड्या को निलंबित कर दिया गया है। ज्योति ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता पार्टी कार्यकर्ताओं पर अनावश्यक दबाव डालते हैं, इसलिए वे तनाव में रहते हैं। ज्योति पंड्या वडोदरा की वर्तमान सांसद को उम्मीदवार बनाए जाने से नाराज थीं। ज्योति ने सांसद पर आरोप लगाया कि वे वडोदरा के विकास के पैसे से अपना माल बनवा रही हैं। ज्योति ने कहा कि मेरे अंदर भाजपा का डीएनए है, मैं किसी अन्य दल से नहीं आई हूं। उन्होंने पार्टी से पूछा कि मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, जिसके कारण विधानसभा तथा लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलता। शहर के लोगों से पूछकर वे अपनी भावी रणनीति का एलान करेंगी। उधर भाजपा ने एक विज्ञप्ति जारी कर ज्योतिबेन को पार्टी से निलंबित करने की सूचना दी है।

जजपा में बढ़ी कलह... व्हिप का उल्लंघन करने वाले पांच विधायकों पर होगी कार्रवाई

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

▸ **विश्वास मत पर चर्चा के दौरान सदन में पहुंचे विधायकों को दिए जाएंगे कारण बताओ नोटिस**

▸ **लोकसभा चुनावों को लेकर आज से तीन दिन चलेंगी मंथन बैठकें, रायशुमारी के बाद होगा फैसला**

हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा गठबंधन तोड़ने के बाद जननायक जनता पार्टी (जजपा) में अंतर्कलह और बढ़ने के आसार हैं। जजपा ने अपने पांच विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है जो बुधवार को व्हिप जारी करने के बावजूद सदन की कार्यवाही का हिस्सा बने थे। इन सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। वहीं, लोकसभा के चुनावी रण में 'एकला चलो रे' की रणनीति पर चल रही पार्टी लगातार तीन दिन कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों का मन टटोलेगी जिसके बाद निर्णय लिया जाएगा कि कहां से उम्मीदवार उतारे जाएंगे और कहां पर नहीं। जजपा के कुल 10 विधायक हैं। जजपा कोटे से मनोहर सरकार में मंत्री रहे देवेंद्र बबली के साथ ही विधायक ईश्वर सिंह, रामकुमार गौतम, जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा की भाजपा से नजदीकियां किसी से छिपी नहीं। देवेंद्र बबली और रामकुमार गौतम कई मौकों पर बयानबाजी कर पार्टी आलाकमान को खुली चुनौती देते रहे हैं। पिछले महीने विधानसभा के बजट सत्र में दुष्यंत और दादा गौतम के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए, जब सदन में ही दोनों में न केवल जमकर आरोप-प्रत्यारोप चले, बल्कि एक-दूसरे को इस्तीफा देने तक की नसीहत दे डाली। एक दिन पहले मामला फिर गर्मा गया जब पांचों जजपा विधायक हिसार में आयोजित नवसंकल्प रैली से दूरी बनाते हुए चंडीगढ़ पहुंच गए और विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा बने।

राष्ट्रीय फलक

समाजसेवी सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ

सुधा मूर्ति ने ली शपथ : इंफोसिस की संस्थापक एवं लेखिका सुधा मूर्ति को गुरुवार को नई दिल्ली स्थित संसद भवन में उपराष्ट्रपति एवं सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी उपस्थित रहे। एएनआइ

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंजीनियर से समाजसेवी बनीं सुधा मूर्ति ने अपने पति एनआर नारायण मूर्ति की मौजूदगी में राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन स्थित अपने कक्ष में उन्हें शपथ दिलाई। इस अवसर पर सदन के नेता पीयूष गोयल भी उपस्थित थे। इंफोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष और बच्चों के लिए कई किताबें लिख चुकीं सुधा मूर्ति को पिछले शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया था। कन्नड़ और अंग्रेजी साहित्य में योगदान के लिए प्रख्यात सुधा मूर्ति को साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार, पद्मश्री (2006) और पद्मभूषण (2023) जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। सुधा मूर्ति व्यावसायिक वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड (टेल्को) के साथ काम करने वाली पहली महिला इंजीनियर थीं।

झारखंड में दोनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित

राज्य ब्यूरो, रांची

▸ **झामुमो के सरफराज अहमद और भाजपा के डा. प्रदीप वर्मा का हुआ निर्वाचन**

▸ **कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू तथा भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल तीन मई को हो रहा है खत्म**

झारखंड में राज्यसभा के लिए खाली हो रही दो सीटों के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के प्रत्याशी डा. सरफराज अहमद तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डा. प्रदीप वर्मा निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। गुरुवार को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापसी के बाद विधानसभा के प्रभारी सचिव सह निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर ने इसकी घोषणा करते हुए दोनों को राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने का प्रमाणपत्र सौंपा। बता दें कि कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू तथा भाजपा के समीर उरांव का कार्यकाल तीन मई को खत्म हो रहा है। डा. अहमद और डा. वर्मा का निर्वाचन इन्हीं सीटों के लिए ही हुआ है।

झारखंड में पांचवीं बार राज्यसभा सदस्य के लिए निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इससे पहले वर्ष 2004 में भाजपा के यशवंत सिन्हा तथा झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी, वर्ष 2006 में कांग्रेस की माबेल रेबेलो तथा भाजपा के एसएस अहलुवालिया, वर्ष 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी तथा राजद के प्रेमचंद गुप्ता और वर्ष 2022 में भाजपा के आदित्य साहू तथा झामुमो की महुआ माजी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ था।

भाजपा के डा. प्रदीप वर्मा (बाएं से दूसरे) को राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र सौंपते निर्वाची पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर। साथ में झामुमो के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य सरफराज अहमद (बाएं से चौथे) व अन्य नेता। जागरण

'परियोजनाओं को पूरा करना पीएम मोदी के विकास माडल की पहचान'

▸ **कहा- 2014 से पहले आधारशिला रखी गई, लेकिन समय से पूरी नहीं हुईं परियोजनाएं**

गुवाहाटी, प्रेट्र: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि नींव रखने के बाद परियोजनाओं को पूरा करना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकास माडल की पहचान है। सीतारमण ने दावा किया कि 2014 से पहले परियोजनाओं की आधारशिला तो रखी गई वे समय पर पूरी नहीं हुईं।

आइआइटी-गुवाहाटी में आयोजित 'विकसित भारत एंबेसडर कैंपस डायलाग' में सीतारमण ने कहा, परियोजनाओं को पूरा करने में देरी ने देश की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। इससे धारणा बनी कि भारत अपनी परियोजनाएं पूरी नहीं करता है। वित्त मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री का मानना है कि सरकार सिर्फ शिलान्यास ही नहीं करेगी बल्कि परियोजनाओं को पूरा भी करेगी। इससे पूर्वोत्तर को भी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास माडल में पूर्वोत्तर क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। पिछले दशक में प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र का 65 बार दौरा किया है, जबकि अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने 850 बार दौरा किया है। यह क्षेत्र के विकास पर सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। उन्होंने पूर्वोत्तर को विकास का इंजन बनाने के लिए पिछले दशक में भाजपा द्वारा की गई विभिन्न पहलों के बारे में बताया।

गुवाहाटी में गुरुवार को कामाख्या देवी मंदिर में प्रार्थना करतीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

हिमाचल में विधानसभा अध्यक्ष ने वापस ली भाजपा विधायकों के विरुद्ध शिकायत

राज्य ब्यूरो, शिमला

▸ **सदन में कागज उछालने पर लिया था स्वत : संज्ञान**

कुलदीप सिंह पठानिया के अनुसार विशेषाधिकार समिति के पास कोई मामला नहीं

हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने भाजपा विधायकों के विरुद्ध शिकायत वापस ले ली है। विशेषाधिकार समिति के पास अब कोई मामला नहीं है। बजट सत्र के दौरान 27 फरवरी को भाजपा विधायकों ने कटौती प्रस्ताव का विरोध किया था। इस दौरान कुछ विधायकों ने सदन में कागज उछाले थे। इस पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने स्वतः संज्ञान लिया था व मामले की शिकायत विशेषाधिकार समिति को भेजी थी। अब इसे वापस लेने से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, विपिन सिंह परमार, सतपाल सत्ती, डा. हंसराज, इंद्र सिंह गांधी, दीपराज व लोकेंद्र कुमार पर कार्रवाई होने से जुड़ा मामला समाप्त हो गया है। विधानसभा में बजट 28 फरवरी को पारित हुआ था। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय प्रशासन से संपर्क करने पर बताया गया कि भाजपा के किसी भी विधायक को विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं दिया गया था। केवल अध्यक्ष की ओर से स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। उसके अलावा किसी तरह की कार्रवाई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी।

जयराम ठाकुर ने व्यक्त किया था संदेह: बजट सत्र के दौरान वार्षिक बजट पारित करवाने के लिए निलंबित किए भाजपा के विधायकों पर कार्रवाई के उपरांत नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा था कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के पराजित होने के बाद सरकार अल्पमत में आ गई थी। सरकार को बचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाकर भाजपा के सात विधायकों को विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाकर निलंबित किया जा रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष की ओर से विशेषाधिकार हनन कमेटी को भेजी शिकायत वापस ले ली है। सीधे तौर पर हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी। ऐसे में भाजपा विधायकों के संबंध में कोई मामला नहीं होने के कारण किसी प्रकार की कार्रवाई का औचित्य नहीं रह जाता है। - विनय कुमार, विस उपाध्यक्ष एवं सभापति विशेषाधिकार हनन समिति

हिमाचल में सीआरपीएफ की सुरक्षा में अयोग्य ठहराए विधायकों के घर

जागरण संवाददाता, गगरेट: हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रास वोटिंग करने वाले सभी नौ विधायकों के घरों पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स (सीआरपीएफ) तैनात कर दी गई है। इनमें छह कांग्रेस के और तीन निर्दलीय विधायक हैं। भाजपा विधायक बिक्रम ठाकुर के घर के बाहर भी सीआरपीएफ तैनात की गई है। राज्यसभा चुनाव में इन्होंने क्रास वोटिंग की थी। पार्टी विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस के छह विधायकों राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा व देवेंद्र भुट्टो को अयोग्य घोषित किया था।

अयोग्य घोषित विधायक देवेंद्र भुट्टो के चराड़ा पंचायत स्थित आवास पर तैनात सीआरपीएफ जवान। जागरण

युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को बर्बाद कर देगी उप्र सरकार : योगी आदित्यनाथ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

▸ **बोले, परीक्षा में सेंधमारी करने वालों की जब्त कर रहे संपत्ति**

▸ **मुख्यमंत्री ने 96 नव चयनित अधिकारियों को बांटे नियुक्ति पत्र**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से नव चयनित 96 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। नियुक्ति पत्र पाने वालों में 39 उप जिलाधिकारी, 41 पुलिस उपाधीक्षक और 16 कोषाधिकारी व लेखाधिकारी शामिल हैं। कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। युवाओं के भविष्य से खेलने वालों को सरकार पूरी तरह बर्बाद कर देगी।

मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास, पांच कालिदास मार्ग पर आयोजित कार्यक्रम में कहा कि परीक्षा की शुचिता व पारदर्शिता में सेंधमारी करने वालों के साथ सरकार सख्ती से निपट रही है। ऐसे लोगों के घर छापे डाले जा रहे हैं और उनकी प्रापर्टी भी जब्त की जा रही है। ऐसे लोग चाहे जहां भी छिपे हों उन्हें ढूंढ़ने में समय नहीं लगेगा। यह काम पुलिस बखूबी कर रही है। मालूम हो कि अभी हाल ही में पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ भर्ती परीक्षा को गड़बड़ी उजागर होने के बाद रद किया गया है। योगी ने अपने संबोधन में इन दोनों भर्ती परीक्षाओं का जिक्र तो नहीं किया लेकिन उनका इशारा इसमें गड़बड़ी करने वालों की ओर ही था।

लोक सेवा आयोग ने इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ सिर्फ नौ महीने में ही पूरी की है। बिना किसी सिफारिश व हस्तक्षेप के योग्य लोगों का चयन किया गया। बीते सात वर्षों में साढ़े छह लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गईं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले सात वर्षों में हमारी सरकार में पूरी ईमानदारी के साथ काम हुआ। अब उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की सोच बदली है और अच्छी हुई है। लोग भी पूरे गर्व से बताते हैं कि वह उप्र के हैं।

अयोध्या में गुरुवार को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के बाद श्रद्धालुओं का अभिवादन करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एएनआइ

****

72 लाख लोगों के पास दिल्ली में राशन कार्ड हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि ये कम पड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उसे बढ़ाने की अनुमति नहीं दे रही है।

'नागरिकता कानून को लेकर लोगों को किया जा रहा गुमराह'

बारपेटा, प्रेट्र : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कानून भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। असम के बारपेटा में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सीएए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 2014 तक भारत आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा।

▸ रक्षा मंत्री ने कहा सीएए भारत आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित लोगों को नागरिकता प्रदान करेगा

राजनाथ सिंह भाजपा के सहयोगी असम गण परिषद के उम्मीदवार फणी भूषण चौधरी के लिए प्रचार कर रहे थे जो बारपेटा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। बारपेटा से वर्तमान में कांग्रेस के अब्दुल खालिक सांसद हैं। सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में राम राज्य की स्थापना को कोई नहीं रोक सकता है। वहीं, असम के कोकराझार में एनडीए के तीन सहयोगी पार्टी भाजपा, एजीपी और यूपीपीएल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सिंह ने आश्वासन दिया कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने पर सभी को पक्का आवास मिलेगा।

असम के कोकराझार में गुरुवार को भाजपा, यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल और असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं की संयुक्त बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राज नाथ सिंह को पुष्प गुच्छ भेंट किया गया। एएनआइ

हरदीप सिंह पुरी बोले, विपक्ष को सीएए के बारे में है अधूरी जानकारी: केंद्रीय शहरी विकास व पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कोलकाता में कहा कि सीएए के बारे में विपक्ष को गलत व अधूरी जानकारी है। उन्होंने अपने बीते दिनों को याद करते हुए कहा कि मैं शरणार्थी की संतान हूं। मेरे माता-पिता कई दशक पहले पाकिस्तान से ट्रेन से यहां आए थे।

हिमंत ने कहा, असम में सीएए का कोई महत्व नहीं: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि देशभर में सीएए लागू हो गया है, लेकिन असम में यह कानून पूरी तरह से महत्वहीन है। उन्होंने दावा किया कि पोर्टल पर सीएए के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने वालों की संख्या असम से बहुत ही कम होगी। उन्होंने कहा कि सीएए में 2014 का कटआफ है, अगर कोई उससे पहले भारत में आया है, तो उसने एनआरसी में आवेदन क्यों नहीं किया। एनआरसी डाटा की वजह से असम में 2014 से पहले आए लोगों का प्रमाण है। जिस भी व्यक्ति को असम एनआरसी सूची में अपना नाम नहीं मिला है, वह सीएए के जरिये आवेदन दे सकते हैं।

केरल के सीएम विजयन बोले, सीएए असंवैधानिक

तिरुअनंतपुरम, प्रेट्र : केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) असंवैधानिक है और यह मानवाधिकारों और 'भारत की विचारधारा' के लिए एक चुनौती है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस कानून के जरिये धार्मिक भेदभाव को कानूनीजामा पहनाया गया है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सीएए के मुद्दे पर उसने खुद को संयुक्त मोर्चा से अलग कर लिया है।

सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं होने की बड़ी वजह पीएफआइ पर प्रतिबंध

नीलू रंजन, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए लागू हुए तीन दिन हो चुके हैं। आवेदन के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है और मोबाइल एप के सहारे आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। यही नहीं, आवेदन करने में शरणार्थियों को मदद करने लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की तैयारी है। इसके बावजूद 2019 और 2020 की तरह सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देश में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इसकी एक प्रमुख वजह देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे कट्टरपंथी संगठन पापुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआइ) पर लगाए गए प्रतिबंध को मान रही हैं। उनके अनुसार उस समय विरोध प्रदर्शनों और हिंसक घटनाओं में पीएफआइ की अहम भूमिका थी।

दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक सीएए के खिलाफ देश के विभिन्न भागों में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के पीछे पीएफआइ की भूमिका कई एजेंसियों की जांच में सामने आई थी। उत्तर प्रदेश एटीएस, दिल्ली पुलिस और ईडी समेत कई एजेंसियों ने इसकी जांच भी की थी। ईडी ने अपनी जांच में विस्तार से बताया था कि किस तरह से विरोध प्रदर्शनों के लिए पीएफआइ ने फंडिंग की थी। इस सिलसिले में ईडी ने पीएफआइ से जुड़े 27 बैंक खातों का पता लगाया था, जिनका इस्तेमाल हिंसक विरोध प्रदर्शनों के लिए किया गया था। ध्यान देने की बात है कि दिल्ली का शाहीन बाग, जो कि सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का प्रतीक बन गया था, में पीएफआइ की मजबूत पकड़ थी और वहीं उसका कार्यालय भी था। सीएए विरोध प्रदर्शनों के साथ ही दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा की वृहद साजिश के पीछे पीएफआइ की सक्रिय भूमिका के आरोप हैं। इन विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए ही उस वक्त केंद्र सरकार ने सीएए को तत्काल लागू करने से परहेज किया था।

▸ दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 तक सीएए के खिलाफ देश में कई जगह हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे था पीएफआइ का हाथ

ध्यान देने की बात है कि सितंबर 2022 में पीएफआइ पर प्रतिबंध लगाने के बाद 10 राज्यों में 100 से अधिक स्थानों पर छापेमारी में 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया था। पूरी तैयारी के साथ पीएफआइ के खिलाफ कार्रवाई ने संगठन की कमर तोड़ दी और उसके सभी बैंक खाते भी सीज कर दिए गए थे। पीएफआइ की फंडिंग का पता लगाकर कार्रवाई करने में ईडी की अहम भूमिका रही। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पीएफआइ को प्रतिबंधित करने और उसके संगठन को ध्वस्त करने के बाद सीएए लागू करने का फैसला सही साबित हुआ। सीएए को लेकर फिलहाल राजनीतिक विरोध और समर्थन का सिलसिला जारी है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। इसमें हिंसक विरोध प्रदर्शन की कोई जगह नहीं होनी चाहिए।

अब तो सीएए को सिर्फ अधिसूचित किया गया

प्रथम पृष्ठ से आगे

सीएए को लागू करने के समय पर उठाए गए सवाल पर गृह मंत्री ने कहा कि यह 2019 में भाजपा के चुनावी एजेंडे का हिस्सा था और उसी साल संसद में इस पर मुहर लगा थी। अब सिर्फ इस कानून के नियमों को अधिसूचित किया गया है, जिसके बारे में चार वर्षों में वह 41 बार एलान कर चुके हैं। उन्होंने ममता बनर्जी को बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का अहित नहीं करने की सलाह दी। कहा कि ममता को सीएए के विरोध के बजाय घुसपैठ को रोकना चाहिए। केरल, तमिलनाडु और बंगाल की सरकारों द्वारा वहां सीएए लागू नहीं करने के एलान का पर शाह ने कहा कि संविधान नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ भारत सरकार को देता है। राज्यों का विरोध बेबुनियाद है।

बताया- मुस्लिम क्यों सीएए के पात्र नहीं : गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए के तहत मुसलमानों को भारत की नागरिकता नहीं देने के पीछे का कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि इस कानून में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताडित हिंदू , जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को नागरिकता प्रदान करने का प्रविधान है। उन्होंने कहा कि ये तीनों देश इस्लामिक हैं। फिर वहां मुसलमान धार्मिक अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं?

देश के किसानों पर लाठियां-गोलियां, पाकिस्तानियों को सम्मान : केजरीवाल

तल्ख तेवर बरकरार ▸ गुरुवार को भी केंद्र सरकार पर बरसे दिल्ली के मुख्यमंत्री

बोले, कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने हुड़दंग किया और दिल्ली पुलिस ने उन्हें संरक्षण दिया

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) पर सियासी घमासान जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक्स पर कहा, 'आज कुछ पाकिस्तानियों ने मेरे घर के सामने प्रदर्शन और हुड़दंग किया। दिल्ली पुलिस ने उन्हें पूरा सम्मान और संरक्षण दिया। भाजपा ने इनका पूरा समर्थन किया। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि दिल्ली की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुने गए सीएम को हमारे ही मुल्क में घुसकर माफी मांगने को कह रहे हैं और भाजपा इनका समर्थन कर रही है। भाजपा मुझसे नफरत करते-करते पाकिस्तानियों के साथ खड़ी हो गई है, भारत के साथ गद्दारी करने लगी? सीएए के बाद ये पाकिस्तानी पूरे देश में फैल जाएंगे और इसी तरह हमारे ही मुल्क के लोगों को हड़काएंगे और हुड़दंग करेंगे। भाजपा इन्हें अपना वोट बैंक बनाना चाहती है।'

नई दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को प्रेस कान्फ्रेंस को संबोधित करते हुए। प्रेट्र

इससे पूर्व एक्स पर एक अन्य बयान में उन्होंने कहा, 'पाकिस्तानियों को पूरी पुलिस सुरक्षा और सम्मान के साथ मेरे घर के बाहर प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई और इस देश के किसानों को दिल्ली में आने की भी इजाज़त नहीं है। भारत के किसानों पर अश्रु गैस के गोले, लाठियां, डंडे और गोलियां और पाकिस्तानियों को इतना सम्मान?'

दोपहर में प्रेस वार्ता कर केजरीवाल ने कहा कि हम अपने देश के बच्चों को रोजगार-घर नहीं दे पा रहे तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को कहां से देंगे? गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को किए गए मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। सीएम ने कहा, आजादी के बाद बड़े स्तर पर पलायन हुआ था। अब सीएए की वजह से जो पलायन होने वाला है, वो आजादी के दौरान हुए पलायन से कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। इन तीनों देशों में करीब ढाई से तीन करोड़ अल्पसंख्यक रहते हैं। वहां बहुत गरीबी है और उनके पास रोजगार नहीं है।

उन्होंने कहा, आज दिल्ली में 72 लाख लोगों के पास राशन कार्ड हैं, जो कम पड़ते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे लोगों के लिए राशन कार्ड की संख्या बढ़ाने की इजाजत नहीं देती, जबकि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लाकर लोगों के राशन कार्ड बनाएंगे। यह सही नहीं है।

आक्रोशित सिख, हिंदू शरणार्थियों का मुख्यमंत्री आवास के नजदीक प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास के पास अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश के हिंदू व सिख समेत अन्य लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। सीएम से शरणार्थियों से संबंधित विवादस्पद बयानों को लेकर माफी मांगने की मांग की। कहा कि उनमें संवेदनहीनता है। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी सोहन दास ने कहा कि वे सभी पड़ोसी मुल्कों से अपनी जान बचाकर आए हैं। पाक में वे सभी अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर वैध दस्तावेज पर भारत आए हैं। वे घुसपैठिए नहीं है। अफगानिस्तान से आए सिख शरणार्थी करतार सिंह ने कहा कि कृपया उनके साथ सहानुभूति रखी जाए। राजनीतिक मोहरा न बनाया जाए। वे लोग पीड़ित हैं। मुख्यमंत्री उन लोगों का अपमान न करें।

अब अलीगढ़ की लाजवंती को आस, 19 साल बाद पूरा होगा परिवार

सुरजीत पुंढीर, अलीगढ़

अलीगढ़ में रहने वाली 71 वर्षीय लाजवंती के परिवार में सात लोग हैं। इनमें बेटी, बेटा-बहू, नातिन व पति शामिल हैं। 2005 में ये लोग पाकिस्तान से वीजा पर अलीगढ़ आए थे। यहां रहना शुरू कर दिया। वीजा का नवीनीकरण कराते रहे। लाजवंती, इनके पति रमेशलाल व बेटी पूजा को तीन-चार साल पहले भारत की नागरिकता मिल गई, बाकी चार लोग अब भी भटक रहे हैं। कई बार ये लोग लखनऊ-दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। अब सीएए लागू होने के बाद लाजवंती की आस बढ़ गई है। उम्मीद है कि केंद्र के इस निर्णय से जल्द ही परिवार के बाकी लोगों को भी नागरिकता मिल जाएगी। लाजवंती की तरह अलीगढ़ में गैर मुस्लिम 16 लोगों को भी नागरिकता की उम्मीद है। ये लोग 2014 से पहले से वीजा पर यहां रह रहे हैं।

एलआइयू रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 54 लोग वीजा पर रह रहे हैं। इसमें 16 हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन समाज से जुड़े हैं। इन्हें हर साल वीजा का नवीनीकरण कराना पड़ता है। खुफिया विभाग में हाजिरी देनी होती है। सीएए लागू होने से सबसे अधिक खुशी इन्हीं लोगों को है। ये लोग नागरिकता के लिए आवेदन की प्रक्रिया जानने को कलक्ट्रेट पहुंच रहे हैं।

एक बेटा अभी भी पाकिस्तान में : लाजवंती का जन्म 1953 में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुआ था। 1972 में इनकी रमेश लाल से शादी हो गई। 2005 में बलूचिस्तान में अराजकता बढ़ गई। लाजवंती के पति रमेशलाल ने अलीगढ़ में रहने वाले भाई बच्चाराम से संपर्क किया। उसके बाद वह परिवार समेत यहां आ गए। यहां किराने की दुकान खोल ली। नई बस्ती में घर बनाया। रमेशलाल ने 2015 में अपना, पत्नी लाजवंती, पुत्र कैलाश व बेटी पूजा का भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया। एक साल कार्रवाई नहीं हुई। कई बार दिल्ली और लखनऊ के चक्कर काटे। 2019 में लाजवंती, रमेशलाल व पूजा को नागरिता मिल गई। दो बेटे, पुत्रवधू व नातिन अब भी नागरिकता की कतार में हैं। इनका एक बेटा पाकिस्तान में रहता है।

▸ पति और बेटी को मिल चुकी है नागरिकता, बाकी अब भी भटक रहे

भारत की नागरिकता का प्रमाणपत्र दिखातीं लाजवंती। जागरण आर्काइव

आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने को प्रतिबद्ध : शाह

नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार नए आपराधिक कानूनों को निर्बाध रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। एक जुलाई से लागू होने वाले तीन नए कानून - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को बदल देंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को नई प्रौद्योगिकी और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से सशक्त बना रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की वेबसाइट और मोबाइल एप 'संकलन' को लांच करते हुए उन्होंने कहा कि पोर्टल और एप तीन नए कानूनों पर नागरिकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों का मार्गदर्शन करेंगे। एप नए और पुराने आपराधिक कानूनों को जोड़कर नई न्याय प्रणाली के सुचारू क्रियान्वयन को सक्षम करेगा। उन्होंने एक्स पर कहा- 'मोदी सरकार नई आपराधिक न्याय प्रणाली को निर्बाध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।'

▸ गृह मंत्री ने एनसीआरबी की वेबसाइट और मोबाइल एप 'संकलन' को किया लांच

▸ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को नई प्रौद्योगिकी से और सशक्त बना रहे

सीसीएमएस का उद्घाटन करते अमित शाह। प्रेट्र

बता दें कि तीनों कानूनों को 21 दिसंबर को संसद से मंजूरी मिल गई थी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 25 दिसंबर को इन पर अपनी मुहर लगा दी थी। ये कानून क्रमशः औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इससे पूर्व वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शाह ने एनआइए के अत्याधुनिक आपराधिक मामला प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) साफ्टवेयर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने जम्मू और कोच्चि में एनआइए के दो कार्यालयों का भी उद्घाटन किया और रांची में एक आवासीय परिसर की आधारशिला रखी।

मोदी ने असंभव कामों का बनाया संभव : शाह ने अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में 3,012 करोड़ रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का गुरुवार को वर्चुअली उद्घाटन व शिलान्यास किया। इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने असंभव दिखने वाले कार्यों को पूरा किया है, चाहे वह जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाना हो या फिर वन रैंक वन पेंशन लागू करना हो। शाह ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के विपरीत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सभी विकास कार्य तक समय पर पूरे किए जा रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में मैंने जिन परियोजनाओं के लिए भूमि पूजन किया, उनमें से 91 प्रतिशत पूरे हो चुके हैं। यह भाजपा की कार्य संस्कृति है।

गुजरात में परीक्षा में उतरवाया हिजाब, प्रशासक पर कार्रवाई

भरुच, प्रेट्र : गुजरात में एक प्राइवेट स्कूल में दसवीं कक्षा की परीक्षा देने वाली कुछ छात्राओं के अभिभावकों ने गंभीर आरोप लगाए कि परीक्षा केंद्र के प्रशासक ने उनके बच्चों को पेपर से पहले हिजाब हटाने के लिए मजबूर किया। अभिभावकों ने कहा कि यह घटना भरूच जिले के अंकलेश्वर में बुधवार को गणित के पेपर से पहले हुई। आरोप के बाद राज्य शिक्षा विभाग ने गुरुवार को परीक्षा केंद्र प्रशासक इला बेन सुरतिया को हटाने के आदेश दिए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी स्वाति रावल ने इन छात्राओं के माता-पिता से मुलाकात के बाद कार्रवाई की। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (जीएसएचएसईबी) ने स्पष्ट किया है परीक्षार्थी किसी भी सभ्य पोशाक में परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

एक अभिभावक ने कहा कि स्कूल के प्रधानाचार्य और अन्य कर्मियों ने परीक्षा से पहले हिजाब उतारने के लिए कहकर मेरी बेटी समेत सभी छात्राओं को परेशान किया। मेरी बेटी घर लौटने के बाद तीन घंटे तक रोती रही। हम चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो।

चुनाव आयोग ने सार्वजनिक किया चुनावी बांडों का ब्योरा

नई दिल्ली, प्रेट्र : चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनावी बांडों से जुड़ा ब्योरा सार्वजनिक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआइ) ने 12 मार्च को यह ब्योरा चुनाव आयोग को सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर इस ब्योरे को 15 मार्च को शाम पांच बजे तक अपलोड करने का समय दिया था।

चुनाव आयोग ने एसबीआइ द्वारा सौंपे गए चुनावी बांड के ब्योरे को दो भागों में वेबसाइट पर प्रकाशित किया है। इस ब्योरे के मुताबिक चुनाव बांड के खरीदारों में फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज, मेघा इंजीनियरिंग, डीएलएफ ग्रुप, वेदांता लिमिटेड, भारती समूह, जैसी कंपनियां शामिल हैं। चुनावी बांड को भुनाने वाली पार्टियों में भाजपा, कांग्रेस, अन्नाद्रमुक, बीआरएस, शिवसेना, तेदेपा, वाईएसआर कांग्रेस, द्रमुक, जदएस, राजद, आप और समाजवादी पार्टी शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को दिए केंद्र की चुनावी बांड योजना को खत्म करते हुए उसका ब्योरा उजागर करने का निर्देश दिया था।

चुनाव बांड के शीर्ष खरीदार

- फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज- 1,368 करोड़ रुपये
- मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड- 966 करोड़
- क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड- 410 करोड़
- वेदांता लिमिटेड- 400 करोड़
- हल्दिया एनर्जी लिमिटेड- 377 करोड़
- भारती समूह- 247 करोड़
- एस्सेल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड- 224 करोड़
- वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन- 220 करोड़
- केवेंटर फूडपार्क इन्फ्रा लिमिटेड- 194 करोड़
- मदनलाल लिमिटेड- 185 करोड़
- डीएलएफ ग्रुप- 170 करोड़
- यशोदा सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल- 162 करोड़
- उत्कल एल्युमिना इंटरनेशनल- 145.3 करोड़
- जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड- 123 करोड़

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, प्रेट्र : मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फार डेमोक्रेटिक रिफार्म्स की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेगी।

एनजीओ ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023 की धारा सात की वैधता को चुनौती देते हुए इस पर स्थगनादेश की मांग की है। इस अधिनियम के जरिये मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर कर दिया गया है। इस मामले की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुवार को ही दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने पूर्व आइएएस अधिकारयों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का चुनाव आयुक्त के रूप में चयन किया।

जवाब तलब

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपेन स्कूल को पत्र लिख कर आयोग ने सात दिन में मांगा जवाब, आयोग ने कहा- तत्काल प्रभाव से ये कोर्स बंद कराएं, बच्चों को औपचारिक स्कूलों में भेजें

बाल आयोग ने जमीयत के स्कूलों का लिया संज्ञान

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ओपेन स्कूल (एनआइओएस) के सहयोग से जमीयत ओपेन स्कूल चलने की शिकायत पर संज्ञान लिया है और पत्र जारी कर एनआइओएस से सात दिन में जवाब मांगा है।

आयोग के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने एनआइओएस को भेजे पत्र में पूछा है कि क्या एनआइओएस और जमीयत उलमा-ए-हिंद या जमीयत एजुकेशन फाउंडेशन या जमीयत ओपेन स्कूल के बीच इस बारे में कोई समझौता हुआ है और उस समझौता पत्र (एमओयू) का ब्योरा उपलब्ध कराने को कहा है। यह भी पूछा है कि एनआइओएस और जमीयत ओपेन स्कूल के बीच प्रत्येक छात्र पर कितनी फीस का हिस्सा तय हुआ है। आयोग ने कहा कि पता चला है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद ने एनआइओएस के सहयोग से ओपेन स्कूल चलाने के आधार पर ब्रिटेन से बहुत राशि एकत्र की है। इस फंडिंग में एनआइओएस का कितना हिस्सा है।

प्रियांक कानूनगो। फाइल

आयोग के पत्र में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार सभी बच्चों का मौलिक अधिकार है। इस शिक्षा के अधिकार को ओपेन स्कूलिंग के जरिये कक्षा तीन, पांच आठ के छात्रों तक विस्तारित करना शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है। देश भर में करीब 15 लाख स्कूल हैं और हर एक से तीन किलोमीटर पर सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चे प्राथमिक शिक्षा पा सकते हैं तो फिर प्राथमिक स्तर पर ओपेन स्कूल के जरिए शिक्षा की क्या जरूरत है। आयोग ने एनआइओएस से कहा है कि वह तत्काल प्रभाव से इन चल रहे पाठ्यक्रमों को बंद कराए और बच्चों को औपचारिक स्कूल भेजने के लिए कदम उठाए। कहा है कि जो बच्चे औपचारिक स्कूलों में नहीं जा रहे हैं वे औपचारिक शिक्षा, मिड डे मील, यूनीफार्म और प्रशिक्षित शिक्षकों से वंचित हैं।

बाल आयोग ने एनआइओएस के अध्यक्ष को भेजे पत्र में कहा है कि वह जांच कराए कि एनआइओएस के कौन से अधिकारी जमीयत उलमा ए हिंद द्वारा किए जा रहे उल्लंघन में शामिल हैं। आयोग ने एनआइओएस से मदरसा में स्थिति एनआइओएस के सेंटरों, या जमीयत से जुड़े किसी भी संस्थान में एनआइओएस के सेंटरों की सूची उपलब्ध कराने को कहा है। कानूनगो जमीयत के ओपेन स्कूल के बारे में आई शिकायत पर कहते हैं कि ओपेन स्कूल नवीं-दसवीं कक्षा से शुरू होता है तो फिर ये मदरसा में पढ़ने वाले कक्षा तीन से आठ तक के छात्रों के लिए कैसे हैं और जमीयत उलमा-ए-हिंद ओपेन स्कूल कैसे चला सकता है।

****

छात्रवृत्ति व योजनाओं का लाभ लेने को दिव्यांगों के लिए आधार अनिवार्य

नई दिल्ली, प्रेट्र : सरकार ने दिव्यांगों के लिए छह छात्रवृत्तियों और कई योजनाओं-पहलों का लाभ लेने के लिए पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दिव्यांगों को अन्य दस्तावेजों के साथ आधार नामांकन पर्ची को जमा करनी होगी।

दिव्यांग सशक्तीकरण विभाग ने अधिसूचना जारी कर बताया कि छह छात्रवृत्तियों प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी की शिक्षा, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों को आधार का उपयोग करना ही होगा। साथ ही बच्चों व वयस्कों के लिए दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना, निरामाया योजना, बच्चों व वयस्कों के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के तहत सेवाओं का लाभ लेने के लिए आधार की जरूरत होगी।

नए चुनाव आयुक्तों को जानिये

ज्ञानेश कुमार

- 1988 बैच, केरल कैडर के आइएएस अधिकारी
- सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद से रिटायर
- सहकारिता मंत्रालय के गठन से लेकर देश में सहकारिता की कार्यप्रणाली लागू करने में ज्ञानेश कुमार की अहम भूमिका रही।
- इससे पहले ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी, जम्मू-कश्मीर डिवीजन रहे। उनके कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया।
- ज्ञानेश कुमार वर्तमान में श्रीराम मंदिर तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट में सरकार के प्रतिनिधि हैं। भगवान राम की जो मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के निर्णायक मंडल में भी वह शामिल रहे।

सुखबीर सिंह संधू

- 1988 बैच, उत्तराखंड कैडर के आइएएस अधिकारी
- सुखबीर संधू डाक्टर और इतिहासकार भी हैं। उनके पास कानून की डिग्री है।
- संधू ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के अलावा केंद्र में भी विभिन्न पदों पर काम किया है।
- उत्तराखंड और पंजाब में चार मुख्यमंत्रियों के मुख्य सचिव के रूप में सेवा दे चुके हैं।
- संधू को 2021 में उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया।
- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) के अध्यक्ष के रूप में केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर रहे।

न्यूज गैलरी

सिख नववर्ष के शुरू होने पर प्रधानमंत्री ने बधाई दी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोगों को गुरुवार से शुरू हुए सिख नववर्ष की बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सिख नववर्ष प्रारंभ होने पर शुभकामनाएं। वाहेगुरु की असीम कृपा सभी को कल्याण और समृद्धि प्रदान करे। गुरु साहिब का ज्ञान हमारे समाज को अपने उज्ज्वल मार्गदर्शन से आलोकित करता रहे। (प्रेट्र)

अग्निवीरों के तीसरे बैच का पासिंग आउट परेड आज

नई दिल्ली : आइएनएस चिल्का पर शुक्रवार को अग्निवीरों के तीसरे बैच का पासिंग आउट परेड (पीओपी) निर्धारित है। पीओपी प्रशिक्षण के सफलता पूर्वक संपन्न होने का प्रतीक है। महिलाओं समेत 26000 अग्निवीरों ने ओडिशा नौसैनिक अड्डे चिल्का में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। नौसेना स्टाफ प्रमुख एडमिरल आर. हरि कुमार पीओपी में मुख्य अतिथि होंगे। वाइस एडमिरल वी. श्रीनिवास, फ्लैग अधिकारी कमांडिंग इन चीफ दक्षिणी नौसेना कमान भी उपस्थित रहेंगे।

एयर इंडिया भवन की मालिक बनी महाराष्ट्र सरकार

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के हस्तांरण को स्वीकृति देने के साथ ही गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार एयर इंडिया भवन की मालिक बन गई। महाराष्ट्र सरकार ने नरीमन प्वाइंट स्थित एयर इंडिया के भवन के लिए 1,601 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सरकार ने 27 जनवरी, 2022 को एयर इंडिया का स्वामित्व टाटा समूह को हस्तांतरित कर दिया। एयर इंडिया के लिए टाटा ने अक्टूबर 2021 में 18000 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी। (प्रेट्र)

असम में 110 करोड़ रुपये की ड्रग्स खेप जब्त

गुवाहाटी : असम के कछार जिले में गुरुवार को अनुमानित 110 करोड़ रुपये की ड्रग्स की एक बड़ी खेप जब्त की गई है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि गुप्त सूचना पर धोलाइ क्षेत्र के लोकनाथपुर में एक अभियान के दौरान 12 किलो हेरोइन और ब्राउन शुगर बरामद की गई। पड़ोसी राज्य से लाए जा रहे नशीले पदार्थों को चमड़े के बैग और साबुन के डिब्बों में छिपाया गया था। (प्रेट्र)

नवी मुंबई में पिटाई से छात्र की मौत, साथी नामजद

ठाणे : नवी मुंबई के तुरभे में कालेज के छह साथियों की पिटाई से 17 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। पुलिस ने गुरुवार को बताया कि इस घटना के बाद मृत छात्र के छह साथियों के विरुद्ध मामला पंजीकृत किया गया है। यह घटना बुधवार को एक बजे दिन में कालेज परिसर से बाहर हुई। मारपीट में मृत छात्र का एक मित्र घायल भी हो गया। (प्रेट्र)

नागपुर में भूमि हड़पने पर 18 आरोपितों पर मकोका

नागपुर : नागपुर पुलिस ने एक महिला की भूमि फर्जी तरीके से बेचने के मामले में आरोपित 18 व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया है। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि गजानन नगर में नवजीवन कालोनी की निवासी 63 वर्षीया महिला ने छह नवंबर, 2023 को शिकायत सौंपी थी। महिला ने पाया कि मौजा नारा क्षेत्र में उसकी 3000 वर्ग फीट भूमि जाली दस्तावेजों का प्रयोग कर पांच लाख रुपये में इमाम खान अब्दुल रहीम खान को बेच दी गई है। (प्रेट्र)

मिजोरम में बिना परमिट घुसे 1000 लोग गिरफ्तार

आइजल : मिजोरम में बिना इनर लाइन परमिट (आइएलपी) के राज्य में प्रवेश करने के लिए 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस और सिविल सोसायटी संगठन यंग मिजो एसोसिएशन के स्वयंसेवियों ने मंगलवार रात संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाया था। (प्रेट्र)

नारी शक्ति का मिशन दिव्यास्त्र की सफलता में अहम योगदान

- शीना रानी के नेतृत्व में अग्नि-5 मिसाइल को बड़ी सफलता
- डा. शंकरी एस.समेत कई महिला वैज्ञानिकों की अहम भूमिका

नई दिल्ली, एएनआइ : देश में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाते हुए कार्यक्रम निदेशक शीना रानी के नेतृत्व में मिशन दिव्यास्त्र की सफलता में बड़ी संख्या में महिला विज्ञानी शामिल थीं। वरिष्ठ विज्ञानी व प्रोग्राम डायरेक्टर शीना रानी पहले भी कई मिसाइल परीक्षणों में शामिल रही हैं।

रक्षा अधिकारियों ने कहा कि कार्यक्रम की प्रोजेक्ट डायरेक्टर डा. शंकरी एस. ने भी मिशन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अग्नि-5 मिसाइल के लिए मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल (एमआइआरवी) तकनीक विकसित करने के मिशन के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला वैज्ञानिकों ने काम किया। परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला वैज्ञानिकों में उषा वर्मा, नीरजा, विजय लक्ष्मी और वेंकटमणि शामिल हैं और ये सभी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) की रणनीतिक मिसाइल प्रयोगशालाओं का हिस्सा हैं। इस बीच, डीआरडीओ के पूर्व चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी ने कहा कि अग्नि-5 मिसाइल का सफल परीक्षण सशस्त्र सेनाओं के लिए गेमचेंजर है। भारत ने कई स्वतंत्र रूप से लक्षित री-एंट्री वाहन (एमआइआरवी) तकनीक के साथ अग्नि-5 मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो सैकड़ों किलोमीटर पार कई परमाणु हथियार पहुंचाने की क्षमता देगा।

बार-बार चुनाव से नीतिगत निर्णयों पर असर : कोविन्द समिति

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

एक देश-एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली उच्चस्तरीय समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि बार-बार चुनाव होने से अनिश्चितता का वातावरण बनता है और नीतिगत निर्णयों पर असर पड़ता है। समिति ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी।

कोविन्द समिति ने कहा है कि सिफारिशों से लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। भारत की आकांक्षाओं को भी ये साकार करेंगी। साथ ही मतदाताओं के बीच पारदर्शिता आएगी। देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास और मजबूत होगा। एक साथ चुनाव मतदाताओं के लिए सुगम और सुविधाजनक होंगे। मतदान के प्रति उनकी उदासीनता दूर होगी। साथ-साथ चुनाव कराने से ऊंची आर्थिक वृद्धि व स्थिरता सुनिश्चित होगी क्योंकि इससे कारोबारी और उद्योग जगत किसी प्रतिकूल बदलाव की आशंका से मुक्त होकर अपने काम-धंधे को आगे बढ़ाने का फैसला ले सकेंगे। नीति निर्माण में निश्चितता बढ़ेगी। सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा। सरकारी कर्मचारियों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सुरक्षाबलों का समय और ऊर्जा बचेगी। प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार चुनाव होने से सामाजिक तालमेल बढ़ेगा।

प्रतीकात्मक फोटो

इन हितधारकों से किया परामर्श

हितधारक संख्या	21,558
नागरिक (वेबसाइट, ईमेल और पोस्ट)	
देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश	04
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश	01
हाई कोर्टों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश	12
पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त	04
राज्य निर्वाचन आयुक्त	08
बार काउंसिल आफ इंडिया	01
व्यवसायिक संगठन	03
राजनीतिक दल	47
अर्थशास्त्री	14
विधि आयोग	02

47 राजनीतिक दलों से ली गई राय, 32 ने किया समर्थन : कोविन्द कमेटी ने एक देश-एक चुनाव के मुद्दे पर मशविरे के लिए देश के 62 राजनीतिक दलों से संपर्क किया था। इनमें से 47 दलों ने समिति के समक्ष अपनी राय रखी। भाजपा समेत 32 दलों ने लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों को एक साथ कराने का समर्थन किया। विरोध करने वाले 15 दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेस और सपा शामिल हैं।

इन देशों की चुनावी प्रक्रिया का किया अध्ययन : समिति ने दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, इंडोनेशिया व फिलीपींस जैसे देशों में एक साथ होने वाले चुनावी प्रक्रिया का अध्ययन किया। समिति का मानना था कि देश के लिए एक समुचित समकालिक चुनाव माडल विकसित करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा।

गायत्री प्रजापति व उनके करीबियों के 13 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

बहुचर्चित खनन घोटाले व आय से अधिक संपत्ति में उप्र के पूर्व मंत्री के विरुद्ध चल रही जांच

लखनऊ, अमेठी, दिल्ली व मुंबई में करीबियों के ठिकानों में छानबीन, 44 लाख रुपये किए गए बरामद

राज्य ब्यूरो, लखनऊ

बहुचर्चित खनन घोटाले में आरोपित अखिलेश यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति और उनके करीबियों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। ईडी ने गुरुवार को गायत्री प्रजापति व उसके करीबियों के लखनऊ में छह, अमेठी में दो, दिल्ली में एक तथा मुंबई में चार ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। कुछ ठिकानों पर तो देर रात तक छानबीन जारी रही। ईडी ने अमेठी में गायत्री प्रजापति के बेटे अनुराग प्रजापति से लंबी पूछताछ भी की और लखनऊ लेकर आई है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी में संपत्तियों से जुड़े कई अहम दस्तावेज कब्जे में लिए गए हैं और 44 लाख रुपये भी बरामद हुए हैं।

पूर्व मंत्री गायत्री दुष्कर्म के मामले में वर्तमान में लखनऊ जेल में बंद हैं। खनन घोटाले की जांच सीबीआइ भी कर रही है। सीबीआइ ने मामले में बीते दिनों सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को बतौर गवाह नोटिस देकर 29 फरवरी को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया था। अखिलेश ने एजेंसी को नोटिस का जवाब भेजा था।

अमेठी के गंगागंज स्थित पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की करीबी गुड्डा देवी के घर पर खड़ा केंद्रीय रिजर्व पुलिस का जवान। जागरण

ईडी की टीमों ने गुरुवार सुबह लगभग छह बजे गायत्री प्रजापति व उसके करीबियों की ठिकानों पर छानबीन शुरू की। अमेठी में गायत्री के परिवार की करीबी महिला के अलावा लखनऊ स्थित दामाद के फ्लैट में भी छानबीन की। लखनऊ में और कई जगह भी छापेमारी की गई। ईडी ने इससे पूर्व भी गायत्री के ठिकानों पर छानबीन की थी। गायत्री से कई बार लंबी पूछताछ भी की गई थी। ईडी अब तक गायत्री व उसके कुनबे की लगभग 50 करोड़ की संपत्ति जब्त कर चुकी है। ईडी ने गायत्री समेत अन्य के विरुद्ध 2019 में खनन घोटाले में मनी लांड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जबकि गायत्री के विरुद्ध 2021 में आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। ईडी कई बेनामी संपत्ति की पड़ताल भी कर रहा है। गायत्री ने घोटाले की काली कमाई से करीबियों के नाम भी कई संपत्ति जुटाई थीं।

विधायक पत्नी की तबीयत बिगड़ी : अमेठी में ईडी की सात सदस्यीय टीम ने गायत्री प्रजापति के घर व उनकी करीबी गुड्डा देवी के आवास पर बेनामी संपत्ति से जुड़े अभिलेखों को 12 घंटे तक खंगाला। गुड्डा देवी के न मिलने पर मिस्त्री को बुलाकर टीम ने आलमारी का ताला तोड़वाकर बेनामी संपत्ति के अभिलेख की तलाश की। ईडी की टीम ने महाराजी प्रजापति, छोटे पुत्र अनुराग व बहू से अलग-अलग पूछताछ की। पूछताछ में विधायक महाराजी देवी की तबीयत खराब हो गई। विधायक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, बड़ी बेटी सुधा ने कहा कि पूछताछ के नाम पर मां महाराजी देवी व भाइयों अनुराग व अनिल को परेशान किया जा रहा है।

ईडी ने शाहजहां शेख के करीबी व्यापारियों के घरों पर मारे छापे

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : ईडी ने बंगाल राशन वितरण घोटाले की जांच के सिलसिले में गुरुवार को पूर्व तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख के साथ करीबी संबंध रखने वाले दो व्यापारियों के आवासों पर छापेमारी की। ईडी अधिकारी ने कहा कि इन दोनों व्यापारियों ने शेख को राशन वितरण के लिए आए पैसे के हेरफेर करने में मदद की थी और उस पैसे का इस्तेमाल मछली व्यापार में किया था। उन्होंने कहा कि ईडी भी अधिकारियों पर हमले में उनकी भूमिका की जांच कर रहा है। शेख को राज्य पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था।

जांच एजेंसी के अधिकारियों ने व्यवसायी नशीरुद्दीन मोल्ला के स्वामित्व वाले बाजार पर भी छापा मारा। यह बाजार झींगा के थोक व्यापार के रूप में लोकप्रिय है। नशीरुद्दीन मोल्ला, शाहजहां के मछली निर्यात व्यवसाय में सक्रिय सहयोगी है, वह संदेशखाली में ईडी और सीएपीएफ कर्मियों पर हमले में भी आरोपित है।

राष्ट्रपति 30 मार्च को पांचों विभूतियों को भारत रत्न से करेंगी सम्मानित

- राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा सम्मान समारोह
- सम्मानित विभूतियों के परिवार जनों को सौंपा जाएगा मेडल

नीलू रंजन, नई दिल्ली

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 30 मार्च को विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए अप्रतिम योगदान करने वाले पांच विभूतियों को भारत रत्न प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर, पूर्व प्रधानमंत्री व किसान नेता चौधरी चरण सिंह और कृषि क्रांति के प्रणेता एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने का निर्णय लिया था।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, भारत रत्न देने का सम्मान समारोह 30 मार्च को 11 बजे राष्ट्रपति भवन में आयोजित किया जाएगा। समारोह में भारत रत्न से जुड़े मेडल और प्रशस्ति पत्र इससे सम्मानित विभूतियों के परिवार जनों को सौंपा जाएगा। लालकृष्ण आडवाणी को छोड़कर अन्य चार विभूतियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, जाहिर है ये सम्मान उनके परिवार जन ही स्वीकार करेंगे। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के स्वास्थ्य को देखते हुए राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उनकी उपस्थिति की संभावना कम है। ऐसे में आडवाणी के लिए सम्मान भी उनके परिवार की ओर से लिए जाने की संभावना है।

राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक रहे लालकृष्ण अडवाणी, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा कर्पुरी ठाकुर, आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से भारत के विकास के युग का सूत्रपात करने वाले नरसिंह राव और किसानों के सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह और किसानों की समृद्धि की राह प्रशस्त करने वाले व भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले स्वामीनाथन को लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत रत्न देने को मोदी सरकार का राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने के बाद उनके पौत्र जयंत चौधरी ने निरुत्तर होने व राजग के साथ जाने का एलान किया था, वहीं कर्पूरी ठाकुर को सम्मानित किये जाने के बाद नीतीश कुमार राजद से नाता तोड़कर भाजपा के साथ फिर आने का फ़ैसला किया था। इससे भारत रत्न के वृहत्तर राजनीतिक प्रभावों को समझा जा सकता है। अप्रैल में मतदान शुरू होने के पहले भारत रत्न पुरस्कार देने के समारोह के आयोजन को इसी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु। फाइल

साथ नहीं देने वाले राजनीतिक दलों का चुनाव में बहिष्कार करेंगे किसान

- रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में किसानों का एलान
- 23 मार्च को सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाएंगे किसान संगठन

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

एमएसपी की गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर गुरुवार को रामलीला मैदान में आयोजित महापंचायत में किसान संगठनों ने एलान किया कि उनकी मांगों का समर्थन नहीं करने वाले राजनीतिक दलों का आगामी आम चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं, उनका देश के विभिन्न स्थानों पर आंदोलन जारी रहेगा। तय हुआ कि किसान संगठन 23 मार्च को देश के सभी गांवों में लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाकर लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी को भाजपा प्रत्याशी बनाए जाने का विरोध करेंगे।

हरियाणा से सटे पंजाब के शंभू बार्डर पर जुटे किसानों के समर्थन में आयोजित इस महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा, आल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआइकेकेएमएस), भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के साथ ही कई वामपंथी संगठनों की सहभागिता थी। केंद्र पर हमलावर वक्ताओं ने कहा, किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका दमन किया जा रहा है। भाकियू के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि किसानों से सरकार कोई बातचीत नहीं कर रही है। ऐसे में कैसे समाधान निकलेगा। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कि सरकार ने बैरिकेडिंग कर कीलें लगाकर किसानों को दिल्ली आने से रोका है। उसी तरह हम सरकार के लोगों को गांवों में आने से रोकेंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज हरियाणा व पंजाब का युवा जमीन बेचकर विदेश जा रहा है। हम देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगला आंदोलन आरपार का होगा। सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटेकर ने कहा कि किसानों को न्यूनतम मूल्य भी नहीं देने वाली सरकार उद्यमियों को अधिकतम मुनाफा करा रही है।

रामलीला मैदान के आसपास के मार्ग हो गए जाम : दोपहर में रामलीला मैदान के आसपास की सड़कों के साथ रिंग रोड, सुभाष मार्ग, तुर्कमान गेट समेत अन्य मार्गों पर जाम की स्थिति रहीं। वहीं, आंदोलन स्थल के आसपास बड़ी संख्या में पुलिस व अर्द्धसैनिक बल तैनात रहा।

नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित किसान मजदूर महापंचायत में भीड़ का नजारा। ध्रुव कुमार

शुभकरण की मौत की न्यायिक जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हरियाणा

- हरियाणा सरकार की दलील, जब पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली तो न्यायिक जांच की आवश्यकता नहीं

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़

प्रदर्शनकारी किसान शुभकरण सिंह की मौत के मामले की न्यायिक जांच के हाई कोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने जांच के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। हरियाणा और पंजाब सीमा पर गत 21 फरवरी को प्रदर्शनकारी किसानों और पुलिस के बीच झड़प के बाद शुभकरण सिंह की मौत हो गई थी।

विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में हरियाणा ने तर्क दिया है कि जब राज्य पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है और जांच को तैयार है, तो जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हरियाणा ने पंजाब पुलिस से घटना से संबंधित रिकार्ड मांगा है। इस अनुमति याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि तीन सदस्यीय कमेटी की अध्यक्षता पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस जयश्री ठाकुर करेंगे। उनके साथ हरियाणा के एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लों व पंजाब के एडीजीपी प्रमोद बन को कमेटी का हिस्सा बनाया है। जस्टिस जयश्री ठाकुर को प्रतिमाह पांच लाख रुपये का भुगतान दोनों सरकारों को बराबर हिस्से में करना होगा। कमेटी तय करेगी कि शुभकरण की मौत हरियाणा के क्षेत्राधिकार में हुई थी या पंजाब के क्षेत्र में। मौत का कारण क्या था और किस हथियार का इस्तेमाल किया गया था। आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किया गया था क्या वह परिस्थितियों के अनुरूप था या नहीं। शुभकरण की मौत के मुआवजे को लेकर भी कमेटी फैसला लेगी।

पीएम मोदी ने भूटानी समकक्ष से की बात

नई दिल्ली, प्रेट्र : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को अपने भूटानी समकक्ष शेरिंग तोबगे के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। जनवरी में भूटान के पीएम पद का कार्यभार संभालने के बाद तोबगे पहली विदेश यात्रा पर भारत आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में हवाईअड्डे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शेरिंग तोबगे का स्वागत किया।

भूटान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के ठीक पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में भूटान को सहयोग देने को लेकर भारत ने तीन प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसमें एक समझौता दोनों देशों के बीच ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा क्षमता बढ़ाने को लेकर है जबकि एक समझौता भूटान को पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति देने को लेकर है। भूटान के पीएम की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब चीन और भूटान अपने सीमा विवाद के शीघ्र समाधान पर विचार कर रहे हैं जिसका भारत के सुरक्षा हितों पर प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि भूटान के हितों को प्राथमिकता दे रहा है।

जागरण विशेष
कर्मठ किसान

जहां थी पलायन की मार, वहां तकनीक और नवाचार से आई बहार

उत्तरकाशी में जगमोहन सिंह ने कृषि से पहाड़ी युवाओं को दिया सकारात्मक संदेश, पहाड़ की असिंचित भूमि को बनाया सोना उगलने वाली जमीन

शैलेंद्र गोदियाल • उत्तरकाशी

उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन की खबर हर किसी को चिंतित करती हैं। रोजगार के लिए युवा बड़ी संख्या में पहाड़ छोड़ रहे हैं। ऐसे में हिमरोल गांव निवासी जगमोहन राणा ने इस धारणा को बदलने का कार्य किया। उन्होंने दिखाया कि गांव में खेती-किसानी करने वाला व्यक्ति अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती-किसानी की जानकारी रखने के साथ नवाचार भी करे तो उत्पादन और आमदनी बढ़ना तय है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 88 किमी दूर हिमरोल गांव निवासी जगमोहन सिंह राणा आनलाइन व आफलाइन माध्यम से गांव के विभिन्न उत्पादों को 'यमुना वैली' नाम से शहरों तक पहुंचा रहे हैं। उनका एक वर्ष का खेती-बागवानी का टर्नओवर 25 से 30 लाख रुपये के बीच है। जगमोहन ने इस पहल से हिमरोल समेत आसपास के गांवों के एक हजार से अधिक ग्रामीणों को जोड़ा है, जिससे वर्तमान तो खुशहाल हो ही रहा है, सुनहरे भविष्य की उम्मीदें भी जगी हैं।

जगमोहन ने अपनी मेहनत, नवाचार और तकनीक के बूते पहाड़ी ढलान की असिंचित भूमि को सोना उगलने वाला बना दिया। हिमरोल में 70 नाली (1,51,200 वर्ग मीटर) भूमि पर वह वर्ष 2018 से सेब, आड़ू, चुल्लू व खुबानी के साथ सब्जी, औषधीय पौधों और मोटे अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। इतिहास विषय में एमए और बीएड की पढ़ाई पूरी करने के बाद जगमोहन ने नौकरी के बजाय गांव में ही पुश्तैनी खेती-बागवानी से स्वरोजगार को आगे बढ़ाने की ठानी।

यहं बनी हर्बल चाय की है अच्छी मांग

जगमोहन सिंह राणा के प्लांट में हर्बल चाय तैयार करती महिलाएं • साभार: जगमोहन

जगमोहन ग्रामीणों को रोजगार देकर औषधीय गुणों से भरपूर हर्बल चाय का भी उत्पादन कर रहे हैं। इस चाय की मांग स्थानीय बाजार से लेकर दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर तक से आ रही है। इसके अलावा वह देहरादून की एक कंपनी को भी प्रतिवर्ष तीन से चार क्विंटल हर्बल चाय उपलब्ध करा रहे हैं।

सेब की पैकिंग करते हुए युवा कृषक जगमोहन सिंह राणा • जागरण आर्काइव

बढ़ रहा रोजगार

जगमोहन बताते हैं कि लाल चावल, मंडुवा, झंगोरा व चौलाई के उत्पादन के साथ एक हजार से अधिक ग्रामीणों से पैकेजिंग का कार्य भी हिमरोल गांव में ही कराया जा रहा है। देश के विभिन्न स्थानों से उत्पादों की आनलाइन और आफलाइन मांग आती है। इन सभी उत्पादों को 'यमुना घाटी' ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है।

जूस की बोतलों पर 'यमुना वैली' ब्रांड की लेबलिंग करती महिला • साभार: जगमोहन

सघन बागवानी की अपनाई तकनीक : जगमोहन कहते हैं कि पहले पांच नाली (10,800 वर्ग मीटर) भूमि पर सेब के 40 पेड़ थे, जिनसे अच्छा लाभ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में वर्ष 2019 में उन्होंने करीब 40 नाली भूमि पर अल्ट्रा हाई डेंसिटी सीडलिंग सेब और अल्ट्रा हाई डेंसिटी रूट स्टाक प्रणाली पर आधारित सेब की डार्क बैरन गाला, किंगरोट व रेड डिलीशियस प्रजाति के 1600 से अधिक पौधे लगाए। सीडलिंग सघन बागवानी की एक नवीन तकनीक है। इसमें पैदावार के साथ पौधों की आयु भी अधिक होती है। इस वर्ष 10 टन सेब उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

यह मिला सम्मान : उन्नत किस्म की खेती के लिए कृषि और उद्यान विभाग ने भी जगमोहन का हौसला बढ़ाया। खेती-किसानी के लिए वर्ष 2022 में जगमोहन को ब्लाक स्तर पर 'किसान श्री' सम्मान मिला। वर्ष 2023 में जिला स्तरीय 'किसान भूषण' सम्मान और सितंबर 2023 में राज्य स्तर पर सतत विकास लक्ष्य में पहला सम्मान जगमोहन को मिल चुका है। इसके अलावा अन्य कई संस्थाओं ने भी उनको सम्मानित किया।

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने के लिए स्कैन करें।

जम्मू में बना एनआइए का कार्यालय, शाह ने आनलाइन किया उद्घाटन

राज्य ब्यूरो, जम्मू : एनआइए की जम्मू-कश्मीर शाखा अब किराये की इमारत में बैठकर जांच नहीं करेगी। अब उसका अपना कार्यालय न सिर्फ बनकर तैयार है बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को उसका ई-उद्घाटन कर उसे पूरी तरह से क्रियाशील बना दिया। एनआइए कार्यालय परिसर में अधिकारियों और कर्मियों के लिए आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जम्मू स्थित एनआइए का क्षेत्रीय कार्यालय न सिर्फ जम्मू-कश्मीर बल्कि लद्दाख प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब से जुड़े मामलों की जांच में भी अहम भूमिका निभाता है। जम्मू-कश्मीर में एनआइए ने अस्थायी कार्यालय अगस्त 2016 में स्थापित किया था। यह एक किराए की इमारत में था और अब इसका अपना कार्यालय परिसर जम्मू के बाहरी हिस्से में स्थित सिद्धड़ा में बनाया गया है।

दैनिक जागरण

सफलता कोई गंतव्य न होकर एक निरंतर चलने वाली यात्रा है

एक साथ चुनाव

एक साथ चुनाव की संभावना पर विचार करने वाली राम नाथ कोविन्द समिति की ओर से राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट कितनी व्यापक है, इसका पता इससे चलता है कि वह करीब 18 हजार पन्नों की है। यह हैरानी की बात है कि इतनी विस्तृत रिपोर्ट पढ़े बगैर ही कई दल उसके विरोध में उतर आए। यह हर सुधार के खिलाफ आंख मूदकर खड़े हो जाने की आदत का ही उदाहरण है। क्या यह उचित नहीं होता कि एक साथ चुनाव की सिफारिश का विरोध करने के पहले यह जान लिया जाता कि रिपोर्ट में लिखा क्या है? एक साथ चुनाव के विरोध में जो तर्क दिए जा रहे, वे घिसे-पिटे ही अधिक हैं। इन तर्कों में कोई दम इसलिए नहीं, क्योंकि 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही होते थे। क्या जब ऐसा होता था, तब भारत में लोकतंत्र नहीं था? पिछले कुछ समय से तो लोकसभा के साथ ही ओडिशा और आंध्र प्रदेश विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं। क्या यह संविधानसम्मत नहीं? क्या ऐसा कुछ है कि ओडिशा और आंध्र विधानसभा के साथ ही लोकसभा चुनाव होने से केंद्र में सत्तासीन भाजपा को लाभ मिलता है? पिछली बार तो आंध्र में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। साफ है कि एक साथ चुनाव के विरोध में दिए जा रहे इस तर्क में कोई दम नहीं कि ऐसा होने से राष्ट्रीय दल फायदे में रहेगा।

एक साथ चुनाव के विरोधियों को कम से कम ऐसे तर्क तो देने ही चाहिए, जिन पर गौर किया जा सके। इसी के साथ उन्हें एक देश-एक चुनाव से होने वाले लाभों पर भी गौर करना चाहिए। ऐसा होने से केवल समय और संसाधन की बचत ही नहीं होगी, बल्कि शासन-प्रशासन को विकास और जनकल्याण के लिए काम करने का अधिक समय भी मिलेगा। कोई भी इससे अपरिचित नहीं कि रह-रहकर चुनाव होते रहने और आचार संहिता लागू हो जाने से किस तरह तमाम काम रुक जाते हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं कि राजनीतिक दलों को किस तरह अपनी अन्य प्राथमिकताओं को किनारे करके सारी ऊर्जा चुनाव लड़ने में खपानी पड़ती है। लोकसभा संग विधानसभा चुनाव कराने और इसके बाद सौ दिन के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव कराने की सिफारिश करने वाली समिति ने इस प्रश्न का भी उत्तर दिया है कि यदि पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के पहले कोई सरकार गिर जाती है तो क्या होगा? समिति के अनुसार ऐसी स्थिति में शेष कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। आखिर ऐसा करना क्यों नहीं संभव? इसी तरह क्या यह समय की मांग नहीं कि सभी चुनावों के लिए एकल मतदाता सूची हो? अच्छा होगा कि कोविन्द समिति की रिपोर्ट खारिज करने वाले नीर-क्षीर ढंग से विचार करें और यह भी देखें कि 32 दल एक साथ चुनाव के पक्ष में हैं।

नियमों का पालन जरूरी

बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में दो प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। राहत की बात यह है कि वृद्धि दर अन्य वर्षों की तुलना में कम है। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 14 प्रतिशत और मृत्यु में 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। ताजा रिपोर्ट में दुर्घटनाओं की संख्या भले ही कम बताई गई हो, लेकिन प्रतिदिन हादसे में लोग जान गंवा रहे हैं। इसपर नियंत्रण हम सबकी जिम्मेदारी है। एक-दूसरे से आगे निकलने की होड़ से बचना होगा। ओवरटेक करने के प्रयास में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। निःसंदेह राज्य में सड़क निर्माण की दिशा में काफी काम हुआ है। कई नई सड़कें बनी हैं, तो कई पहले से बनी सड़कें चौड़ी हुई हैं। ऐसे में लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर जान की परवाह किए बिना तेज रफ्तार में वाहन चलाते हैं। तेज रफ्तार की वजह से ही अधिकतर हादसे हो रहे हैं। राज्य सरकार ने यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्ती बरतने का फैसला किया है। फिलहाल यातायात और परिवहन अधिकारियों को गाड़ी की जांच के लिए हैंड हेल्ड डिवाइस दिए गए हैं, जिससे नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों से आनलाइन जुर्माना वसूला जा रहा है। अब सरकार ड्राइविंग लाइसेंस और आनर बुक की आनलाइन स्कैनिंग की व्यवस्था भी करने जा रही है। सभी यातायात चेकपोस्ट के साथ प्रमुख चौक-चौराहों पर स्कैनर लगाए जाएंगे। इससे फर्जी लाइसेंस की भी आसानी से पहचान हो सकेगी। हाईवे पर इंटरसेप्टर वाहनों से पेट्रोलिंग की भी तैयारी है, ताकि तेज गति के वाहनों को नियंत्रित किया जा सके। बड़े शहरों में बाइक सवार दोनों यात्रियों के लिए हेलमेट अनिवार्य है, लेकिन लोग इसका पालन नहीं करते। सड़कों पर अतिक्रमण भी हादसों के कारण बनते हैं।

लोग अपने वाहन नियंत्रित तरीके से चलाएं। सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन जरूरी है

और अधिक सक्षम होती अर्थव्यवस्था

धर्मकीर्ति जोशी

जिस रफ्तार से भारत वृद्धि कर रहा है, उसे देखते हुए 2030 के आसपास तक देश सात ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन सकता है

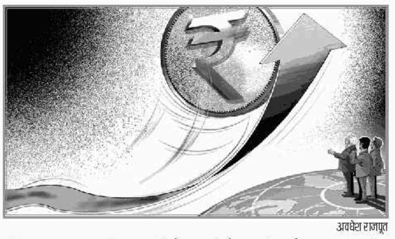

अवधेश राजपूत

अस्थिरता से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत इस समय उम्मीद की किरण बना हुआ है। भारत ही इकलौती ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो लंबे समय तक औसतन 6.8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज करने में सक्षम है। चालू वित्त वर्ष में भी अर्थव्यवस्था 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकती है। हालांकि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि की रफ्तार कुछ थम सकती है, लेकिन फिर भी वह विश्व में सबसे अधिक और मौजूदा परिस्थितियों में अपेक्षाकृत बेहतर रहेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत स्तंभ इतने मजबूत हैं कि कुछ ही वर्षों में उसका आकार दोगुना हो सकता है। सार्वजनिक विमर्श में भारत को पांच ट्रिलियन (पांच लाख करोड़) डालर की आर्थिकी बनाने की चर्चा है, लेकिन जिस रफ्तार से भारत वृद्धि कर रहा है, उसे देखते हुए 2030 के आसपास तक देश सात ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। अभी अर्थव्यवस्था का आकार करीब 3.6 ट्रिलियन डालर है। इस लिहाज से देखें तो करीब सात वर्षों के दौरान आर्थिकी का आकार बढ़कर दोगुना हो जाएगा। यदि आने वाले वर्षों में आर्थिक वृद्धि की दर कुछ कमजोर पड़े तो उसे लेकर चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा होता है तो वृद्धि की पूर्ववर्ती तेज दर को बरकरार रखना उतना आसान नहीं होता। विकसित देशों की अर्थव्यवस्थाओं में यह रुझान स्पष्ट दिखता है। अगले सात वर्षों में आर्थिकी का आकार बढ़ेगा तो उसका असर स्वाभाविक रूप से प्रति व्यक्ति आय पर भी पड़ेगा। उम्मीद है 2030 के आसपास तक भारत 4,000 से 4,500 डालर प्रति व्यक्ति आय के साथ उच्च-मध्यम आमदनी वाले देशों की श्रेणी में जगह बना सकेगा। ये सभी संकेत भारत को जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का इशारा करते हैं।

भारत की सफलता गाथा में मुख्य रूप से तीन बिंदुओं की अहम भूमिका होगी। ये तीन बिंदु हैं पूंजी, श्रम और सक्षमता। इनकी गिनती तो अलग-अलग होती है, लेकिन असल में ये एक-दूसरे पर निर्भर होकर एक प्रकार से अन्योन्याश्रित ही हैं। पूंजी के स्तर पर देखें तो सरकार ने संकट के समय अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोला तो स्थितियां सुधरते ही राजकोषीय अनुशासन का भी रुख किया। कोविड महामारी के दौरान सरकार ने लोगों को मदद पहुंचाई और आर्थिकी में मांग का स्तर उतना कमजोर नहीं पड़ने दिया। सरकार बुनियादी ढांचे के विकास को भी प्राथमिकता देती रही। जनधन-आधार-मोबाइल यानी जैम की त्रिशक्ति से डिजिटल ढांचा भी निरंतर सशक्त होता रहा।

विधायी मोर्चे पर जीएसटी जैसे कर सुधार ने आर्थिक सुगमता एवं सक्षमता को बढ़ाया है। जीएसटी से जहां कई प्रकार के अवरोध दूर हुए और चुंगियां समाप्त हुईं, वहीं बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर से आवाजाही सुगम हुई। आवाजाही सुगम होने से ईंधन और समय की बचत होने लगी है। डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर से जहां भुगतान सुगम हुए और उनमें जोखिम घटे तो इनोवेशन की एक संस्कृति विकसित हुई। आज तमाम स्टार्टअप इसी मिलीजुली समन्वित आर्थिक कार्यसंस्कृति से फल-फूलकर यूनिकार्न के मुकाम तक पहुंचने में भी सफल हुए हैं। भारतीय यूपीआइ को कई देशों में मान्यता मिली है और तमाम देश उसे अपनाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। यह सही है कि निजी निवेश अभी इस क्षेत्र की क्षमताओं से कम है, लेकिन धीरे-धीरे उसमें बढ़ोतरी की उम्मीद जग रही है। सरकार अपने स्तर पर इसके लिए प्रोत्साहन देकर प्रयास कर रही है। इस दिशा में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआइ योजना खासी उपयोगी सिद्ध हुई है। इसके माध्यम से अभी तक मोबाइल हैंडसेट निर्माण और फार्मा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता मिली है। अगले चरण में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी और स्टील जैसे क्षेत्रों में कामयाबी मिलने की उम्मीद है।

श्रम एक ऐसा मुद्दा है, जिस पर भारतीय नीति-नियंताओं को गहन मंथन करने की आवश्यकता है। भारत एक श्रम बहुल अर्थव्यवस्था है, लेकिन इस श्रम को भारत की पूंजी बनाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जाने शेष हैं। देश में करीब 97 करोड़ लोग कामकाजी आबादी का हिस्सा हैं, लेकिन इनमें एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनके पास किसी रोजगार के लिए आवश्यक कौशल का अभाव है। निःसंदेह सरकार और निजी क्षेत्र इस दिशा में प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन परिणाम अभी भी अपेक्षा के अनुरूप नहीं। इतनी बड़ी कामकाजी आबादी का लाभ उठाने के लिए उनकी शिक्षा एवं कौशल विकास के स्तर पर समुचित प्रयास करने होंगे। कोई भी अर्थव्यवस्था पूंजी और श्रम के बेहतर संयोजन के साथ ही आवश्यक सक्षमता के स्तर को प्राप्त कर सकती है। चूंकि दूरगामी एवं व्यापक श्रम सुधार अभी आकार लेते नहीं दिख रहे हैं तो नीति-नियंताओं को फिलहाल उपलब्ध गुंजाइश को देखते हुए नीतिगत हस्तक्षेप करना होगा। तभी अर्थव्यवस्था से जुड़ी संभावनाओं को भुनाया जा सकता है।

दूरगामी-दीर्घकालिक पहलुओं से इतर तात्कालिक बिंदुओं की बात करें तो अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में है। अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर कुछ घटी तो उसमें ऊंची ब्याज दरों की भूमिका हो सकती है। चूंकि महंगाई दर अभी भी रिजर्व बैंक के लिए सहज सीमा से ऊपर है तो अभी दरों में कटौती के आसार नहीं दिखते। हालांकि महंगाई में अभी केवल खाद्य उत्पादों की कीमतें ही परेशानी का सबब हैं और यदि मानसून मेहरबान रहा तो ये कीमतें भी नरम हो सकती हैं। तब केंद्रीय बैंक के पास दरें घटाने की गुंजाइश होगी, जिसका असर आर्थिक गतिविधियों एवं वृद्धि पर भी दिखेगा। राजकोषीय स्तर पर जहां सरकार अपना घाटा घटाने पर ध्यान केंद्रित किए हुए है, वहीं चालू खाते का घाटा भी इस साल जीडीपी के एक प्रतिशत से कम रह सकता है। विदेशी मुद्रा भंडार भी भरा हुआ है। ये सभी पहलू दर्शाते हैं कि अर्थव्यवस्था घरेलू और बाहरी झटकों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार है। कोविड महामारी से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और हाल में इजरायल-हमास टकराव के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी इस क्षमता को बार-बार दिखाया भी है।

(लेखक क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री हैं)

response@jagran.com

रेवड़ी संस्कृति को रोकने का समय

आरके सिन्हा

मुफ्त की सुविधाओं का लाभ उठाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना ही छोड़ देते हैं

आगामी लोकसभा चुनावों की घोषणा शीघ्र ही होने वाली है। इस सिलसिले में विभिन्न राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। इसी के साथ उन्होंने लोकलुभावन घोषणाएं करना भी शुरू कर दिया है। यह मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में राजनीतिक दल जनता को लुभाने के लिए बहुत कुछ मुफ्त में देने का वादा करेंगे। राहुल गांधी ने नारी न्याय गारंटी के नाम पर ऐसी कई घोषणाएं कर भी दी हैं। उन्होंने हर गरीब महिला को सालाना एक लाख रुपये देने का वादा किया है। उन्होंने इस तरह की घोषणाएं पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी की थीं, लेकिन उनसे जनता प्रभावित नहीं हुई। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि मुफ्त बिजली, पानी और दूसरी तमाम चीजें देना कहां तक उचित है और वह भी चुनाव जीतने के लिए?

लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मुफ्त की घोषणाएं करना कोई नया चलन नहीं है। इस चलन पर बहस होती रहती है और इसके विरोध में कई स्वर भी सुनाई देते रहे हैं, पर होता कुछ नहीं है। अपने देश में रेवड़ियां बांटने का वादा और फिर उन पर जैसे-तैसे और अक्सर आधे-अधूरे ढंग से अमल का दौर चलता ही रहता है। लोकलुभावन वादों को पूरा करने की लागत अंततः मतदाताओं को खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है-अक्सर करों अथवा उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जताई थी। नीति आयोग के साथ रिजर्व बैंक भी मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं। कई बार तो वे अपात्र लोगों को भी मुफ्त सुविधाएं देने के वादे कर देते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ समय पहले उन दलों को आड़े हाथों लिया था, जो वोट लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां देने के वादे करते हैं। उनका कहना था कि रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड, रेल नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते। वे अस्पताल, स्कूल और गरीबों के घर भी नहीं बनवा सकते।

तमिलनाडु से निकली मुफ्तखोरी की संस्कृति। फाइल

रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक भी साबित होती है। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना छोड़ देते हैं। दिल्ली में उन महिलाओं को भी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, जिन्हें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं। आधी आबादी को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में डीटीसी को हर साल 15 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव करीब हैं तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि यदि आगामी आम चुनाव में सभी सातों सीटें आप और कांग्रेस के उम्मीदवारों को मिलीं तो वह 15 दिन के अंदर सबका पानी का बिल माफ कर देंगे। आखिर इस तरह की रेवड़ियां बांटने का क्या मतलब? केजरीवाल पानी के बिल माफ करने का वादा करते हुए यह भूल गए कि दिल्ली में लाखों लोगों को अब भी प्राइवेट टैंकरों से पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है। जब मुफ्त पानी, बिजली आदि दी जाने लगती है तो उसका दुरुपयोग भी होने लगता है। अफसोस होता है कि हमारे देश में चुनाव में मुफ्त की सुविधाएं बांटना सामान्य हो गया है। तमिलनाडु से उपजा चलन अब सारे देश में फैल गया है।

यदि कोई नेता या राजनीतिक दल गरीबों को कोई सुविधा मुफ्त देने का वादा कर रहा है तो उसे यह भी बताना चाहिए कि वह उसके लिए धन कहां से लाएगा? अनेक अर्थशास्त्री मुफ्त उपहार बांटकर लोगों के वोट खरीदने की खतरनाक प्रवृत्ति के प्रति आगाह कर चुके हैं, लेकिन उनकी चिंताओं से नेता बेपरवाह हैं। वे यह देखने को तैयार ही नहीं कि अनाप-शनाप चुनावी वादों को पूरा करने की कीमत क्या होती है और उनसे आर्थिक सेहत पर कितना बुरा असर पड़ता है। चुनाव के समय किए गए वादों का राजकोषीय प्रभाव सरकार बनने के लगभग 12-18 महीनों के बाद ही महसूस किया जा सकता है। चूंकि यह पक्का है कि राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में लोकलुभावन वादे करेंगे ही, इसलिए चुनाव आयोग को अपने स्तर पर कुछ करना चाहिए। इसी के साथ मतदाताओं को भी इस प्रवृत्ति से परहेज करना होगा। उन्हें शिक्षा, सेहत और रोजगार जैसे जरूरी सवालों पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए। इससे ही देश में एक स्वस्थ चुनावी संस्कृति का निर्माण होगा।

इस समय देश के सामने एक चुनौती टैक्स देने वाले नागरिकों की संख्या कम होना है। देश का एक बहुत छोटा सा हिस्सा टैक्स देता है। हालांकि पिछले दस साल में करदाताओं की संख्या और टैक्स की वसूली बढ़ी है, लेकिन अभी इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर सभी लोग अपने हिस्से का टैक्स दें तो देश का विकास और तेज हो सकता है। यह ठीक नहीं कि राजनीतिक दल मुफ्त की सुविधाएं देने की होड़ तो लगाएं, लेकिन राजस्व बढ़ाने के लिए जरूरी उपायों पर ध्यान न दें। राजनीतिक दलों की इस आदत पर जनता को सतर्क होना होगा, क्योंकि रेवड़ियां बांटने के वादे पूरे करने से कई राज्यों पर कर्ज का जो बोझ बढ़ा, उसकी कीमत उसे ही चुकानी पड़ रही है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

आनंद के सूत्र

आयु के तीसरे चरण में माता-पिता को अपने अतीत को भूलकर भविष्य की ओर देखना चाहिए, ताकि बच्चों के प्रति उनका प्रेम और बच्चों का उनके प्रति सम्मान बना रहे। संसार में सभी जीव ईश्वरप्रदत्त इस ज्ञान का उपयोग कर सुखी रहते हैं। सुखी, संतुष्ट और गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है कि अपनी योग्यता का उपयोग किया जाए, किंतु दूसरों को वैसा करने के लिए बाध्य न करें। हर पशु यही करता है। वह वही खाता-पीता है, जो उसे प्रिय है। उसे यह समझने के लिए किसी से कुछ सीखना नहीं पड़ता है। वस्तुतः, माता-पिता बच्चों के वर्तमान में उन्हें जो सिखाना चाहते है, समय का तीसरा काल उन्हें वह सब सिखा देता है और वे सीख लेते हैं। हमें सृष्टि का नियामक बनने की मिथ्या चेष्टा से बचना चाहिए।

विभाजन की प्रक्रिया में विभाजित होने से बचना चाहिए। विभाजन सृष्टि का अकाट्य सत्य है। उसे विस्तार के रूप में देखने का स्वभाव बना लेना सुखी जीवन का कारण हो सकता है। उपयोग के पश्चात शेष को छोड़ देना और बीज रोपड़ से पुनः उसी पदार्थ के पुनर्जीवन की प्रक्रिया सृष्टि के साथ जुड़ी हुई हैं। जड़ से सीख लेना ही हमारी चैतन्यता की सिद्धि है। संसार की सहज प्रक्रिया को समझकर उसे स्वीकार करके हम बिना किसी मूल्य के सुख ले सकते हैं। इसके उलट संसार की प्रक्रिया और प्रकृति को परिवर्तित करने की अपनी आधारहीन इच्छा के कारण हम अपने पुरुषार्थ को विनष्ट करके दुख और अवसाद में जा सकते हैं।

आकाश से लेकर जमीन तक जितनी प्रकृति और रंग भेद है वह सब ईश्वर का अनुग्रह है, जो उसने कृपास्वरूप हमें सुख देने के लिए उपलब्ध कराया है। यही श्रेयस्कर है कि हम जीवन से परिवर्तन अभियान की आशा का त्याग करके स्वयं परिवर्तित हो जाएं, ईश्वर में एकनिष्ठ रहें और परमानंद पाकर अपनी भावी पीढ़ियों को मंगलमय पथ पर चलने का राजमार्ग बनाएं।

स्वामी मैथिलीशरण

रील्स के शिकंजे में रियल लाइफ

सोनम लववंशी

रील्स की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि छोटे बच्चे भी इसके मोहजाल में फंस गए हैं

रील्स की अपनी एक अलग दुनिया है। वह एक ऐसी समस्या बन गई है कि चाहकर भी उसके भंवर से निकलना कठिन हो गया है। आज ऐसा कोई विषय शेष नहीं जिस पर रील्स नहीं बन रही हों। आश्चर्य की बात है कि रील्स की लत छुड़ाने तक के लिए भी रील्स बनाई जा रही हैं। एक आंकड़े की मानें तो करीब 253 करोड़ लोग रोजाना रील्स देखते हैं। भारत में सबसे ज्यादा रील्स इंस्टाग्राम के लिए बनाई जाती हैं। 32.7 करोड़ यूजर के साथ भारत में इंस्टाग्राम दुनिया का सबसे बड़ा रील बाजार बन गया है। जबकि अमेरिका दूसरे नंबर पर आता है।

एक रिसर्च के मुताबिक देश की 61 प्रतिशत आबादी इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल करती है। यह आंकड़ा साल 2025 में बढ़कर 67 प्रतिशत पहुंचने का अनुमान है। कलारी कैपिटल की एक स्टडी के मुताबिक भारत में आठ करोड़ प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर हैं। रेडसीर स्टडी की रिपोर्ट बताती है कि देश में स्मार्टफोन यूजर औसतन ढाई घंटे एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें 40 मिनट से भी ज्यादा का समय रील्स देखने में खर्च करता है। इसमें भी सबसे ज्यादा संख्या युवा पीढ़ी की है, जो कभी अपने मनोरंजन के लिए तो कभी पढ़ाई के नाम पर रील्स की दुनिया में खोए रहती है। रील्स की दीवानगी इस हद तक बढ़ गई है कि छोटे बच्चे भी इसके मोहजाल में फंस गए हैं और अपनी भूख प्यास, सुख-चैन सब कुर्बान कर दिए हैं। छोटे बच्चों की आउटडोर एक्टिविटी कम होने से मेंटल हेल्थ पर भी बुरा असर हो रहा है। यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब देश में नशा मुक्ति केंद्र की तरह ही इंटरनेट मीडिया की लत छुड़ाने के लिए भी इंटरनेट मीडिया मुक्ति केंद्र खुलने लगेंगे।

रील्स के कारण अनचाही मौत के मामले भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इनमें ज्यादातर स्कूल-कालेज जाने वाले युवा हैं। अपनी रील्स को आकर्षक दिखाने के चक्कर में कई बार वे चलती ट्रेन की चपेट में आ जाते हैं। इंस्टाग्राम पर अश्लीलता का अंबार लग चुका है। जिसका समाज पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज पर तो आए दिन रील्स बनने के चक्कर में दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये युवा अपने साथ साथ दूसरे व्यक्तियों की भी जान जोखिम में डालने में कोई परहेज नहीं करते हैं। राजस्थान के पाली में बीते दिनों एक युवक को माता-पिता ने रील्स बनाने से रोका तो गुस्से में आकर उसने अपने माता-पिता की हत्या कर दी। यह घटना हर माता-पिता के लिए यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इस समस्या को कैसे रोका जाए? वक्त की नजाकत यही कहती है कि यह डिजिटल बीमारी, महामारी बन जाए इससे पहले सामूहिक रूप से इससे निजात का कोई रास्ता ढूंढ़ना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

सीएए का बेतुका विरोध

'अस्तित्व में आया न्यायसंगत कानून' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में रसाल सिंह का तर्क उचित है कि राजनीतिक कारणों तथा वोट बैंक की राजनीति के चलते नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के अमल का विरोध करना अतार्किक, अमानवीय और असंवैधानिक है। सीएए का विरोध करने वाले भला क्यों नहीं नेहरू-लियाकत समझौते के टूटने की बात करते। आखिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यक अपनी जान बचाकर यदि भारत न आएं तो फिर कहां जाएं। दिसंबर 2014 तक जिन देशों से आने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने वाले सीएए प्रविधानों पर इतनी हायतौबा मची है, उन लोगों के प्रति भारत राष्ट्र की एक अलिखित प्रतिबद्धता है। ये देश अखंड भारत का भाग रहे हैं। अब पड़ोसी देशों की सरकारें और नागरिक आस्था के आधार पर अल्पसंख्यकों पर अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं। सीएए उन असहाय और मजबूर लोगों के लिए मानवीय उपचार की तरह है। इस कानून का स्वागत होना चाहिए। इस कानून का विरोध करना मजबूरी है अपना अस्तित्व बचाने में लगे राजनीतिक दलों की, जिसे भारतीय लोकतंत्र का 'लोक' भलीभांति जानता और समझता है।

योगराज, खरड़ (पंजाब)

मजबूत विपक्ष भी जरूरी

'विपक्ष का मोर्चा कितना मजबूत' शीर्षक से प्रकाशित उमेश चतुर्वेदी का आलेख पढ़ा। उन्होंने सही लिखा है कि यदि कांग्रेस और उसके सहयोगी भाजपा को ठोस चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपनी रणनीति बदलकर सक्रियता दिखानी होगी। अभी उनमें इसका अभाव दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को हराने के लिए विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों का एक गठबंधन तैयार हुआ है, जिसका नाम उन्होंने आइएनडीआइए रखा है, लेकिन इस गठबंधन के बिखराव की खबरें भी सुर्खियां बन रही हैं। पहले नीतीश कुमार इससे अलग हुए। जबकि उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। फिर ममता बनर्जी बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की बात कहने लगीं। आम आदमी पार्टी और वाम दलों की भी यही स्थिति है। ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राजनीति अवसरवादी का शिकार हो गई है। कब कौन-सी पार्टी रंग बदल ले, कोई पता नहीं। गठबंधन की राजनीति विभिन्न विचारधाराओं का गठन होता है, लेकिन विभिन्न विचारधारा आपसी कलह को भी जन्म देती है। इस कलह की चपेट में राष्ट्रीय स्थिरता कभी भी खतरे में आ सकती है। लोकतंत्र में जितनी मुख्य भूमिका आमजन द्वारा चुनी सरकार की होती है, उतनी ही मजबूत विपक्ष की भी होती है। और अगर विपक्ष कमजोर हो तो लोकतंत्र के लिए उचित नहीं होता। इससे सरकार के तानाशाही रास्ते पर चलने की आशंका बढ़ जाती है। सरकार को तानाशाही राह पर चलने से रोकने के लिए मजबूत विपक्ष जरूरी है, लेकिन अफसोस यह है कि आज हमारे देश में न तो मजबूत विपक्ष नजर आ रहा है और न ही विपक्षी एकता। सबकी अपनी-अपनी डफली अपना-अपना राग है। मोदी को हराने के लिए वर्ष 2019 के आम चुनाव में भी विपक्षी की एकजुटता की खबरें सामने आई थीं, लेकिन उस समय भी वे मोदी की जीत को नहीं रोक पाए थे। इसके विपरीत भाजपा ने वर्ष 2014 के मुकाबले 2019 में ओर ज्यादा सीटें हासिल की थीं। मोदी विरोधी पार्टियों का एकजुट होना यह दर्शाता है कि उन्हें इस बात का डर है कि कहीं उनका अस्तित्व खतरे में न पड़ जाए। इन राजनीतिक पार्टियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि आमजन हर चुनाव में सता पक्ष की नीतियों का विश्लेषण करता है, न कि इस पर गौर करता है कि कौन-सी पार्टी किसके साथ गठबंधन कर रही है। भारत में ऐसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का जन्म भी हुआ है जो धर्म पर आधारित हैं। कई बार ये दल सांप्रदायिक तनाव भी पैदा करते हैं। कुल मिलाकर 2024 के आम चुनाव में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए तैयार हो रहा विपक्षी दलों का गठबंधन पहले ही धराशायी होता नजर आ रहा है।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

मेलबाक्स

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
****

विश्व निद्रा दिवस

युवा दुनिया पर भारी पड़ता नींद का संकट

डा. संजय वर्मा
एसोसिएट प्रोफेसर, बेनेट यूनिवर्सिटी

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवाओं में नींद की जरूरत को रेखांकित किया। इंटरनेट मीडिया, कामकाज की शैलियों में बदलाव और बदलती जीवनशैली के कारण खासकर युवाओं में नींद का गंभीर संकट पैदा हो गया है। यह स्थिति स्वास्थ्य और व्यवहार संबंधी कई समस्याओं की वजह बन रही है। हर दिन अच्छी नींद इनसे छुटकारा दिला सकती है। लिहाजा नींद में पड़ते खलल को दुरुस्त करने का संकल्प लेने की जरूरत है

ज्यादा बेहतर होगा कि हर रोज कम से कम सात घंटे की नींद ली जाए। प्रतीकात्मक

हाल में देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार आयोजित 'राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार' वितरण करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर युवाओं में नींद की जरूरत और जागरूकता को रेखांकित किया। इस साल की शुरुआत में अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में मानसिक और शारीरिक सेहत पर बात करते हुए न्यूनतम सात घंटे की नींद लेने की सलाह देने के बाद यह दूसरा मौका था, जब प्रधानमंत्री ने नींद की चर्चा की। इन उल्लेखों का स्पष्ट संकेत है कि इंटरनेट मीडिया, कामकाज की शैलियों में बदलाव और बदलते लाइफ स्टाइल के कारण खासकर युवाओं में नींद का गंभीर संकट पैदा हो गया है। सिर्फ युवा नहीं, बल्कि खुद का उदाहरण देते हुए भी प्रधानमंत्री ने यह बात जोर देकर कई बार कही है कि अच्छा होगा कि नींद के मामले में लोग उनका (प्रधानमंत्री का) अनुसरण नहीं करें- जो कि सिर्फ तीन या चार घंटे ही सो पाते हैं, बल्कि ज्यादा बेहतर होगा कि हर रोज कम से कम सात घंटे की नींद ली जाए।

सदियों की नींद, झटके में गायब : नींद सदियों से रही है। यह प्रत्येक जीवधारी की दिनचर्या से जुड़ी रही है। कुछ जीव-जंतुओं को छोड़कर सूरज ढलने और जमीन पर रात उतरने के बाद लगभग हरेक के जीवन में छह से आठ घंटे की नींद एक नियमित क्रम के रूप में मौजूद रही है। हालांकि उद्योगीकरण के साथ सदियों से कायम रहा यह निद्राचक्र बदल गया। इंटरनेट की खोज और इंटरनेट मीडिया के बढ़ते चलन के साथ बीते कुछ ही दशकों में नींद की कमी एक महामारी की शक्ल में सामने आ गई। नींद की कमी क्या कर सकती है, इसका एक उदाहरण करीब छह दशक पहले वर्ष 1959 का है। तब अमेरिकी डीजे पीटर ट्रिप न्यूयार्क के टाइम स्क्वायर से लाइव प्रसारण के लिए लगातार 201 घंटे तक जागते रहे थे। हालांकि पीटर के रिकार्ड को 1964 में एक किशोर रैंडी गार्डनर ने तोड़ दिया था। वह स्कूल के एक प्रोजेक्ट के लिए लगातार 260 घंटे (करीब 11 दिन) तक जागता रहा। पीटर और रैंडी, दोनों के बारे में ये सूचनाएं आईं कि वे नींद की कमी के शिकार हो गए। एक वक्त ऐसा भी आया, जब उन्होंने लोगों से बातचीत कम कर दी। कभी-कभी वे भ्रमित होने लगे। यहां तक कि वर्णमाला पढ़ने जैसे सरल काम के लिए उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। दोनों मतिभ्रम का शिकार हो गए। उन्हें ऐसा लगता था कि उनके जूतों में मकड़ी के जाले लग गए हैं या फिर उनकी डेस्क की दराज में आग लग गई है। धीरे-धीरे इलाज की मदद से पीटर और रैंडी अनिद्रा के कारण पैदा समस्याओं से निजात पा गए, लेकिन इन उदाहरणों से और अन्य शोध कार्यों से साबित हुआ कि नींद की दीर्घकालिक कमी तंत्रिका तंत्र संबंधी स्थाई समस्याएं पैदा कर सकती है।

खराब नींद, नतीजा दुर्घटनाएं : नींद की कमी से इंसान के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। 1988 में एसोसिएशन आफ प्रोफेशनल स्लीप सोसायटीज ने स्लीप जर्नल में एक रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें बताया गया था कि नींद पूरी नहीं होने से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। खास तौर से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। दिन में सड़क पर होने वाली कहासुनी और मारपीट की घटनाओं यानी रोडरेज को भी नींद की कमी से पैदा होने वाली समस्या के रूप में देखा जाता है। अमेरिकी स्वास्थ्य जर्नल-न्यूरोलाजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक आज हर सात में से एक व्यक्ति स्लीप ड्रंकननेस (नींद से इस कदर बोझिल होना जैसे खूब शराब पी हो) की बीमारी से ग्रस्त है। इस तरह की बीमारी में व्यक्ति भ्रम का शिकार हो जाता है और कुछ का कुछ करने लगता है। जैसे घड़ी का अलार्म बजने पर फोन उठाकर बात करने लगता है। अभी तक यह बीमारी बच्चों तक सीमित मानी जाती थी, लेकिन अब वयस्क भी बड़ी संख्या में इसके शिकार होने लगे हैं। करीब 19 हजार अमेरिकी वयस्कों पर किए एक सैंपल सर्वे के आधार पर तैयार रिपोर्ट में स्टैनफोर्ड स्कूल आफ मेडिसिन में निद्रा मनोचिकित्सक डा. मौरिस ओहयान ने लिखा है कि इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है मानो उसे अचानक नींद से जगा दिया गया हो। कई बार तो ऐसे लोगों को यह पता तक नहीं चलता कि उन्होंने नींद की ऐसी अवस्था में क्या-क्या कर डाला है। स्लीप ड्रंकननेस नामक बीमारी से जूझ रहे 70 प्रतिशत लोगों में निद्रा की कोई न कोई समस्या या मानसिक बीमारी भी अवश्य होती है। भ्रम पैदा करने वाली निद्रा की यह बीमारी कम नींद लेने या अत्यधिक नींद लेने के कारण पैदा होती है। मनोचिकित्सकों ने चेताया है कि यदि सुरक्षा एवं यातायात संचालन जैसे पेशे से जुड़े ऐसे लोगों का वक्त पर इलाज न हो तो ये लोग दूसरों की जिंदगी के लिए भी भारी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।

भारत के युवाओं पर असर : वर्ष 2012 में अमेरिका की यूनिवर्सिटी आफ वारविक के मेडिकल स्कूल के रिसर्चरों ने नींद पर एक व्यापक शोध किया था। उस शोध में पता चला कि भारत जैसे विकासशील देशों के 15 करोड़ लोग नींद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उस शोध ने एक नए ट्रेंड की तरफ इशारा किया था। असल में, पहले माना जाता था कि नींद की कमी और दिमागी चिंता जैसी बीमारियां सिर्फ विकसित समाजों में हैं, लेकिन कई एशियाई और अफ्रीकी देशों में कराए गए इस नए अध्ययन में पता चला कि उनकी 16.6 प्रतिशत आबादी नींद की कमी से होने वाली समस्याओं की चपेट में है। यह आंकड़ा विकसित देशों की नींद संबंधी परेशानियों से पीड़ित 20 प्रतिशत आबादी के काफी करीब है, इसलिए मुमकिन है कि आने वाले वक्त में विकासशील देश इस मामले में विकसित देशों को पीछे छोड़ दें। नींद की कमी से जूझते भारत, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि देशों के निवासियों में भी वे मानसिक समस्याएं देखी जाने लगी हैं, जो अभी तक विकसित देशों का मर्ज मानी जाती थीं। भारत में, जहां पिछले दो-ढाई दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया जगत, काल सेंटरों और बीपीओ सेवाओं ने लाखों-करोड़ों रोजगार पैदा किए हैं, वहां यह तथ्य अक्सर रेखांकित किया जाता है कि इन पेशों ने लाखों युवाओं की स्वाभाविक नींद छीन ली है। इससे न केवल युवाओं की नींद का चक्र बिगड़ रहा है, बल्कि वे इसकी भरपाई भी नहीं कर पा रहे हैं जिससे उनमें कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो रही हैं।

वर्ष 2022 में एक शोध प्रकाश में आया जिसमें कहा गया था कि किसी व्यक्ति की दयालुता या उदारता का संबंध इससे नहीं है कि उसके पास कितना पैसा है, बल्कि इससे है कि वह व्यक्ति कितनी देर अच्छी नींद ले पाता है। यानी नींद आधी-अधूरी और उखड़ी-उखड़ी होगी तो व्यक्ति भी उखड़ा-उखड़ा होगा। यह दिलचस्प शोध बर्कले विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया था। उन्होंने निष्कर्ष में पाया कि जब लोग तीन अलग-अलग तरीकों से थके हुए थे तो उनकी दयालुता में फर्क पाया गया। शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंचे कि नींद की कमी से थके हुए लोगों की परोपकारिता उन लोगों के मुकाबले कम थी, जिन्होंने भरपूर नींद ली थी। यही नहीं, अमेरिका में 38 लाख से अधिक धर्मार्थ दान-पुण्य के कार्यों के विश्लेषण में नींद खोने वाले लोगों की ओर से दान में 10 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई। दान-पुण्य और उदारता में उतार-चढ़ाव से नींद का ज्यादा संबंध सेहत और कामकाज में रुचि से है।

नींद के पैटर्न में आया बदलाव

नींद के रास्ते में सबसे बड़ी मुश्किल यह बताई जा रही है कि इंसान के सोने-जागने का पैटर्न अब वैसा नहीं रहा, जैसा वह औद्योगिकी क्रांति से पहले सदियों तक रहा है। खासतौर से शहरियों के लिए नींद आधुनिक वक्त की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। नींद पर शोध करने वाले अमेरिका के एक प्रख्यात इतिहासकार रोजर इकिर्च कहते हैं कि वैसे तो मनुष्य का शरीर 24 घंटे में एक से अधिक बार नींद लेने के हिसाब से बना है, लेकिन बढ़ती भागदौड़ और आधुनिक शहरी जीवन ने इस क्रम को काफी ज्यादा छिन्न-भिन्न कर दिया है। देर रात तक आफिस में काम करना और घर आकर भी टीवी देखना या मोबाइल-इंटरनेट जैसी गतिविधियों में व्यस्त रहना-इन सबने रात के वक्त ली जाने वाली नींद में व्यवधान उत्पन्न कर दिया है। इकिर्च के मुताबिक इससे लोगों में अनिद्रा का एक खास तरह का रोग पैदा हो जाता है। इसमें लोगों की रात में कई बार नींद खुलती है और फिर दोबारा सोने में दिक्कत आती है। मुश्किल यह है कि नए जमाने के कामकाज के तौर-तरीकों में पुरातन नींद के लिए न तो जगह बची है और न उसकी भरपाई के ठीकठाक विकल्प। ऐसे में सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, बल्कि कई अन्य विज्ञानी और चिकित्सक भी कहते हैं कि नींद का हर हाल में सम्मान किया जाए और दिन में कहीं भी आ जाने वाली नींद के कारण पैदा होने वाली समस्याओं के समाधान के प्रयास किए जाएं।

जैसे-जैसे नींद उचटने लगी है, वैसे-वैसे नींद के जरिये शरीर को मिलने वाले आराम और मानसिक सेहत में भी खलल पड़ी है। विज्ञान के नजरिये से भी नींद की ये समस्याएं मानव सभ्यता के एक बड़े संकट का संकेत हैं। इसलिए इसे नए सिरे से जानने-समझने और इसकी कमी के उपचार के तौर-तरीके खोजे जाने लगे हैं। जैसे-एक तरीका कुछ समय पहले बेंगलुरु की फर्नीचर और गद्दा बनाने वाली कंपनी ने खोजा। वेकफिट नामक इस कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों को बाकायदा ईमेल लिखकर जानकारी दी कि वे हर कामकाजी दिन में दफ्तर में काम करते हुए दोपहर दो से ढाई बजे के बीच खाना खाकर एक झपकी (पावर-नैप) ले सकते हैं। तीस मिनट की यह झपकी उनके शरीर के तंतुओं को रिचार्ज कर सकती है। इससे उनका काम में ज्यादा मन लग सकता है- ऐसा कंपनी ने माना। एक आंकड़ा है कि वर्ष 2008 से अब तक 34 प्रतिशत अमेरिकी कंपनियां अपने कर्मचारियों को पावर-नैप लेने की छूट दे चुकी हैं। कंपनियों ने इसके लिए अपने दफ्तरों में खास कमरों और आंखों को सुकून देने वाले पाड्स तक का निर्माण करवाया है। ऐसे में नींद में पड़ी खलल को दुरुस्त करने और उसकी भरपाई का संकल्प इस विश्व निद्रा दिवस पर लेने की जरूरत है।

खरी-खरी

फिर चुनावी मौसम आया सखी

शरद उपाध्याय

हे सखी, एक बार फिर चुनाव का मौसम आ गया है। चारों ओर हर्ष का माहौल है। बहुत दिनों से उपेक्षा के कारण मतदाता विरह की ज्वाला में जल रहा था, पर अब प्रेम की फुहार की उम्मीद से चैन की बंसी बजा रहा है। चुनाव की घोषणा के अंतिम वर्ष में जल्दी-जल्दी हो रहे निर्माण कार्यों से धरा के बदलते स्वरूप के कारण गूगल मैप भी थका-थका सा महसूस कर रहा था। अब वह भी चैन से है। उसे पता है कि अगले चुनावों तक कोई निर्माण कार्य न होने के कारण धरा का स्वरूप यथावत रहेगा।

हे सखी, मैं यह क्या देख रही हूं। मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। दुर्लभ प्रजाति के श्वेत वस्त्रधारी जीव, जो स्थाई रूप से वातानुकूलित जलवायु में पाया जाता था, इनदिनों उष्ण कटिबंधीय जलवायु में विचरण कर रहा है। गोल-मटोल काया हांफती हुई इधर से उधर लुढ़क रही है। यह श्वेत वस्त्रधारी प्यार से मुझे निहार रहा है। कितने प्यार भरे वादे कर रहा है। आजकल चांद-तारे तोड़ने की बातें करने लगा है। ऐसा प्रेमी तो कभी देखा ही नहीं। हर बात के लिए सिर्फ हां ही कहता है। ना कहना तो जानता ही नहीं। मैं तो उसके वादों से लाज से मरी जा रही हूं।

हे सखी, अब तू अधिक नखरे मत कर। हाईकमान के अलावा कभी किसी के आगे नहीं झुकने वाला सिर आज सिर्फ तेरे मत के आगे झुक रहा है। तू थोड़ी तो दया कर। जरा इसके चेहरे को तो देख। पांच साल लौह धातु की तरह प्रतीत होने वाला चेहरा कैसे रुई से भी नरम लग रहा है। हे सखी, अब अधिक मत इतरा। तू तो जीवन भर उससे मांगती ही रहती है। ठीक है, अभी तक नहीं दे पाया तो क्या हुआ। तुझसे तो सिर्फ वोटिंग मशीन के बटन पर अंगुली का हल्का सा दबाव ही तो चाहता है। फिर न जाने कहां अज्ञातवास में चला जाएगा। तू सोच तो सही। बेचारे ने कभी तुझे डिस्टर्ब नहीं किया। सभी की प्राइवेसी का कितना ख्याल रखता है। तो बस अब अधिक मोलभाव मत कर। निकल और एक वोट देकर लोकतंत्र की रक्षा कर। तेरे हाथ में और है ही क्या।

X पोस्ट

कांग्रेस के चुनावी वादों को देखकर लगता है कि पार्टी उस स्थिति में पहुंच गई है कि वह चुनाव जीतने के लिए हर भारतीय नागरिक को दस करोड़ रुपये और सौ तौले सोना देने का वादा भी कर सकती है।
विकास सारस्वत@VikasSaraswat

अपने आप को दलितों एवं वंचितों के हितैषी बताने वाले मार्क्सवादी कामरेड भी आज प्रताड़ित दलितों-वंचितों को न्याय दिलाने वाले नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ खड़े हुए हैं।
ऋतिका चंदोला@RitikaChandola

भविष्य में यदि कभी कांग्रेस का कायाकल्प हुआ तो वह तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं की वजह से ही हो सकता है, क्योंकि रेड्डी नकारात्मकता को न्यून कर सकारात्मकता को बढ़ावा देने वाले नेताओं में से हैं।
अभिजीत अय्यर मित्रा@Iyervval

हरियाणा में भाजपा और दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी-जजपा का समझौता टूटना दोनों पार्टियों के लिए सुखद है। दोनों पार्टियों का वोट बैंक अलग है। अधिक आसार इसी बात के हैं कि जजपा जाट वोटों में ही सेंध लगाएगी।
आदेश रावल@AadeshRawal

शक्ति संतुलन का दिव्यास्त्र

अभिषेक कुमार सिंह
संस्था टेली परफार्मेंस से संबद्ध

अच्छा तो यह होता कि दुनिया में युद्ध नहीं होते। पड़ोसी देशों में परस्पर शत्रुता का कोई भाव नहीं होता। अमन-चैन के ऐसे दौर में मानव सभ्यता विकास के रोज नए प्रतिमान स्थापित करती, लेकिन इसी सभ्यता का अब तक का इतिहास बताता है कि परस्पर होड़, संसाधनों पर काबिज होने की प्रतिद्वंद्विता और खुद को शक्तिशाली दर्शाने के सोच ने इस धरती से युद्ध कभी खत्म ही नहीं होने दिए। हालात ये हैं कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में रूस-यूक्रेन और इजरायल-हमास के बीच जंग जारी है। अगर भारत ने अपनी सैन्य ताकत में जरूरी इजाफा करना जारी नहीं रखा तो कुछ पड़ोसी देश इसे हमारी कमजोरी मान अपनी मनमानी पर उतर सकते हैं। शक्ति संतुलन साधने की इन्हीं कोशिशों की कड़ी में ताजा कदम भारत की विश्वसनीय मिसाइल अग्नि-5 को एमआइआरवी तकनीक यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री-एंट्री व्हीकल तकनीक से लैस किया जाना है। मिशन दिव्यास्त्र के तहत इसे बनाया गया है। यह एक साथ कई अस्त्र (वारहेड) ले जाने और सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित कई ठिकानों पर एक साथ निशाना लगाने में कितना सक्षम है। इसकी मारक क्षमता पांच हजार किलोमीटर है। इसके दायरे में संपूर्ण एशिया और चीन से लेकर यूरोप के कुछ हिस्से आ सकते हैं।

अग्नि मिसाइलें भारत में 1990 से ही बनाई जा रही हैं, लेकिन जिस एमआइआरवी तकनीक से अब इसे लैस किया गया है वह इसके निर्माण से पहले ही दुनिया में मौजूद थी। अमेरिका इस तकनीक को अपनी मिसाइलों में वर्ष 1970 से ही आजमा रहा है और रूस भी उसके पीछे-पीछे अपनी मिसाइलों में यह क्षमता विकसित करने में कामयाब हो गया था। इनके बाद चीन, फ्रांस और ब्रिटेन भी एमआइआरवी तकनीक वाली मिसाइलें बनाने में सफल रहे हैं। पाकिस्तान भी इस तकनीक वाली मिसाइलों के विकास में जोरशोर से लगा हुआ है। मुमकिन है कि इस काम में चीन उसकी मदद कर रहा हो। चूंकि ऐसी मिसाइलों को जमीन से या फिर समुद्र में तैनात पनडुब्बी से भी दागा जा सकता है, इसके जरिये परमाणु बम वांछित ठिकाने पर गिराए जा सकते हैं और सेंसर की मदद से हजारों किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर अचूक निशाना लगाया जा सकता है, इसलिए ऐसी मिसाइलें वक्त की जरूरत बन गई हैं।

चीन से लगातार मिल रही चुनौतियों के मद्देनजर ऐसे दिव्यास्त्र की कमी को हमारा रक्षातंत्र लंबे समय से महसूस कर रहा था, जिसकी भरपाई यह मिसाइल कर सकती है। भारत के पास चीन के दूरस्थ शहरों पर निशाना लगाने में सक्षम मिसाइलों की संख्या बेहद कम है। चीन ने परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस पनडुब्बियों और बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने के मामले में जो बढ़त बना रखी है, उस शक्ति संतुलन को साधने के लिए भारत को अग्नि-5 जैसे और दिव्यास्त्र के विकास की अविलंब आवश्यकता है। असल में चुनौती अकेले चीन-पाकिस्तान नहीं हैं, बल्कि दुनिया में अत्याधुनिक मिसाइलों के विकास की जो नई होड़ शुरू हुई है, उसमें सेनाओं के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे ऐसी अत्याधुनिक मिसाइलों को अपने बेड़े में शामिल करें, जो किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में हमलावर देश पर पूरी ताकत के साथ प्रहार करने के साथ बचाव या ढाल के रूप में भी काम कर सकें। यह चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा दो साल पहले यूक्रेन के खिलाफ रूस द्वारा एक हाइपरसोनिक मिसाइल के इस्तेमाल से हुआ था। रूस की किंजाल नामक हाइपरसोनिक मिसाइल की खूबी यह है कि दो हजार किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ मैक-10 यानी ध्वनि की गति से 10 गुना तेज यानी 12 हजार से 14 हजार किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय लक्ष्य को भेद सकती है। इसकी गति माहौल के अनुसार बदली जा सकती है और लक्ष्य के स्थान बदलने पर उड़ान मार्ग में भी परिवर्तन किया जा सकता है। आज दुनिया में ऐसा कोई भी मिसाइल सुरक्षा कवच नहीं है, जो किंजाल मिसाइल की रोकथाम कर सके। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेनाओं के लिए अवांगार्ड नामक ऐसा मिसाइल सिस्टम विकसित करने का भी आदेश दिया है, जिसके तहत मिसाइलें ध्वनि की गति से 27 गुना ज्यादा रफ्तार से उड़ सकती हैं।

बात चाहे हाइपरसोनिक क्षमता की हो या फिर एमआइआरवी तकनीक वाली मिसाइलों की, अब यह लगने लगा है कि शत्रु देशों से सीमाओं की सुरक्षा और शक्ति संतुलन कायम करने के लिए अत्याधुनिक मिसाइलों का निर्माण और विकास आज बेहद जरूरी है। जो देश पहले से इस दिशा में काम कर रहे हैं, हाल के वर्षों में वहां ऐसी मिसाइलों के परीक्षण में तेजी देखी गई है। जैसे दो साल पहले अमेरिकी सेना ने रूस और चीन की अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों को टक्कर देने वाली एक मिसाइल के परीक्षण की घोषणा के साथ बताया था कि अमेरिका की डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने हवाई जहाज से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल बनाया है, जो मैक-5 यानी ध्वनि से पांच गुना तेज गति से उड़ान भर सकती है। अमेरिका अगले साल तक समुद्र और हवा से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलें तैनात करने की योजना पर भी काम कर रहा है। इसके अलावा चीन से संभावित खतरे के खिलाफ तैयारी के रूप में अमेरिका, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया मिलकर आकुस नामक एक संगठन बना चुके हैं। इसके तहत ये सभी देश मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएंगे और अपनी युद्धक क्षमताएं बढ़ाएंगे। ऐसे में यदि भारत ने इस संबंध में तेजी नहीं दिखाई तो आधुनिक मिसाइलों के मामले में पिछड़ जाएगा।

एमआइआरवी तकनीक से लैस अग्नि-5। प्रेट्र

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या रोजगार से लेकर गरीब परिवारों को नकद सहायता से जुड़े कांग्रेस के चुनावी वादे प्रभावी साबित होंगे?

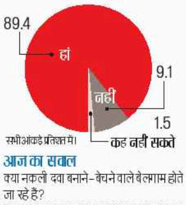

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या नकली दवा बनाने-बेचने वाले बेलगाम होते जा रहे हैं?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

हिंदू पाकिस्तान से आएं तो सिरदर्द,
रोहिंग्या से प्यार है उड़ा रहे जो गर्द।
उड़ा रहे जो गर्द उन्हीं से इन्हें सगापा,
पर हिंदू के नाम शुरू है इनका स्यापा।
है महत्त्व की बात सोचने वाला बिंदु,
क्यों 'सर जी' की आँख खटकते रहते हिंदू।
- ओमप्रकाश तिवारी

वेड इन कश्मीर

आर्थिक-सांस्कृतिक बेहतरी की राह

डा. मोनिका शर्मा
सामाजिक मामलों की जानकार

गत दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीर को डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के लिए चुनने की अपील की। शादी के लिए देश के बाहर समारोह स्थल चुनने की प्रवृत्ति ने सामाजिक जुड़ाव के भाव को ही नहीं बदला, बल्कि भारत के बाजारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है

भारतीय परिवारों में विवाह के आयोजन को विशेष बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती। सदा से ही शादी समारोहों में परंपरागत रीति-रिवाजों के निर्वहन का भाव-चाव और सगे-संबंधियों का मेलजोल मन लुभाने वाले ही रहे हैं। साथ ही हर परिवार यह भी कोशिश करता है कि अपनी हस्ती के अनुसार विवाह आयोजन में खर्चा किया जाए। यही वजह है कि भारतीय समाज में शादियां परिवार और समाज से ही नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था से भी जुड़ी रही हैं। गांवों से लेकर महानगरों तक, कपड़ों-गहनों, खान-पान, यातायात और समारोह स्थल चुनने तक, बहुत कुछ शादियों की धूमधाम से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। पारिवारिक और सामाजिक कहे जाने वाले वैवाहिक आयोजनों से अनगिनत सामानों और सेवाओं का बाजार पोषण पाता है।

तकलीफदेह है कि बीते कुछ वर्षों में चर्चित चेहरों से लेकर आम परिवारों तक में डेस्टिनेशन वेडिंग का चलन बढ़ा है। शादी के लिए देश के बाहर समारोह स्थल चुनने की प्रवृत्ति ने सामाजिक जुड़ाव के भाव को ही नहीं बदला, बल्कि भारत के बाजारों को भी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। विशेषकर स्थानीय बाजारों को बहुत हानि हुई है। ऐसे में चार साल पहले अनुच्छेद 370 हटने के बाद बने सुरक्षित परिवेश के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की देश के लोगों से कश्मीर को डेस्टिनेशन वेडिंग स्थल के लिए चुनने की अपील बहुत मायने रखती है। गत दिनों 'विकसित भारत, विकसित जम्मू-कश्मीर' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो लोग डेस्टिनेशन वेडिंग की योजना बना रहे हैं, वे कश्मीर को भी अपना विकल्प चुन सकते हैं। देश के दूसरे राज्यों में बसे परिवारों से वहां जाकर शादी समारोह आयोजित करने की यह अपील पहले विशेष दर्जा रखने के चलते अलग-थलग रहे कश्मीर में सामाजिक सहजता और मानवीय जुड़ाव के मामले में भी बड़ा परिवर्तन लाने वाली साबित होगी।

धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में जाकर शादियां करना सीधे-सीधे वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला साबित होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हर क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के रास्ते खुलेंगे। ध्यातव्य है कि काफी समय से प्रधानमंत्री मोदी 'वेड इन इंडिया' के तहत भारतीय परिवारों को डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए देश के ही किसी हिस्से को चुनने की बात कहते रहे हैं। वह विदेश में जाकर वैवाहिक समारोह आयोजित करने के चलते भारत के सामाजिक जीवन और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले नकारात्मक असर को लेकर भी चेताते रहे हैं।

वर्षों से आतंकवाद का दंश झेलने वाला कश्मीर हमारे देश के ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे सुंदर पर्यटन स्थलों में से एक है। मनमोहक दृश्यों और अनूठी सांस्कृतिक विरासत इसे एक बेहतरीन वेडिंग डेस्टिनेशन भी बनाती हैं। हालिया समय में वहां बना सुरक्षा और शांति का माहौल ऐसे आयोजनों के लिए कश्मीर के चुनाव को प्राथमिकता देने का परिवेश बनाता है। देखने में आ रहा है कि इस बदलते माहौल में देश के कोने-कोने से जम्मू-कश्मीर में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच भी रहे हैं। होटल, टैक्सी जैसी सेवाओं के अलावा पर्यटकों द्वारा स्थानीय उत्पादों की खरीद में हुआ इजाफा भी लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है, जिसके चलते स्थानीय लोग काफी उत्साहित हैं। आतंकवाद के शिकार एक क्षेत्र विशेष के बाशिंदे कहलाने के बजाय, अब कश्मीरी देश-दुनिया के साथ आगे बढ़ने का सोच रखते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कहा है कि जम्मू-कश्मीर केवल एक क्षेत्र नहीं है, बल्कि भारत का मस्तक है। और ऊंचा उठा मस्तक ही विकास और सम्मान का प्रतीक होता है। इसलिए विकसित जम्मू-कश्मीर, विकसित भारत की प्राथमिकता है। ऐसे में स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और वहां की संस्कृति के सुंदर रंगों से परिचय पाने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग के रूप में कश्मीर का चुनाव करना वाकई एक सुखद कदम साबित होगा। निःसंदेह आर्थिक मोर्चे पर मददगार बनने वाला यह बदलाव सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता के सेतु के माध्यम से भी कश्मीर को हर भारतीय के मन के करीब ले आएगा।

डेस्टिनेशन वेड्गि के रूप में कश्मीर का चुनाव करना देशहित में बड़ा कदम साबित होगा। प्रतीकात्मक

****

एसी मैन्यूफैक्चरिंग की क्षमता विस्तार करेगी ब्लूस्टार

कोलकाता: घरेलू उपकरण बनाने वाली दिग्गज कंपनी ब्लूस्टार अपनी एयरकंडीशनर मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता विस्तार पर अगले वर्ष 250 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक बी थियागराजन ने गुरुवार को कहा कि अभी हमारी मैन्यूफैक्चरिंग क्षमता 10 लाख रूम एसी सालाना है। हम इसको बढ़ाकर 18 लाख सालाना करने की योजना बना रहा हैं। अभी रूम एसी श्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी 13.75 प्रतिशत है। (प्रेट्र)

हम इस वर्ष के अंत तक अपने बिक्री नेटवर्क को तीनगुना बढ़ाकर 200 आउटलेट पर पहुंचाने की योजना बना रहे हैं। नए आउटलेट शहरी, अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण बाजारों में बनाए जाएंगे।
– शिशिर मिश्रा, ब्रांड डायरेक्टर, सिट्रान इंडिया

सेंसेक्स	73,097.28	▲ 335.39
निफ्टी	22,146.65	▲ 148.95
सोना प्रति दस ग्राम	₹ 66,200	▲ ₹250
चांदी प्रति किलोग्राम	₹77,000	▲ ₹1,700
डालर	₹82.84	▲ ₹0.03
क्रूड (ब्रेंट) प्रति बैरल	$ 84.68	

एक नजर में

भारतीय कारोबार की 13% हिस्सेदारी बेचेगी पैरामाउंट

नई दिल्ली: वैश्विक मनोरंजन कंपनी पैरामाउंट ग्लोबल अपने भारतीय टीवी कारोबार का 13 प्रतिशत हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने पर सहमत हो गई है। रिलायंस ने गुरुवार को बताया कि वायकाम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड में पैरामाउंट ग्लोबल की 13.01 प्रतिशत हिस्सेदारी 4,286 करोड़ रुपये में खरीदी जाएगी। इस संबंध में दोनों के बीच समझौता हो गया है। (प्रेट्र)

44 अरब डालर हो सकता है इस वर्ष आइटी पर खर्च

नई दिल्ली: इस वर्ष देश में आइटी खर्च 11 प्रतिशत बढ़कर 44 अरब डालर पर पहुंच सकता है। इंटरनेशनल डाटा कारपोरेशन (आइडीसी) की ओर से गुरुवार को जारी रिपोर्ट में अनुमान जताया गया है कि 2027 तक भारत में आइटी खर्च में 9.9 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में आइटी खर्ज 59 अरब डालर को पार कर सकता है। (आइएएनएस)

एनटीपीसी का उत्पादन 400 अरब यूनिट के पार

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनटीपीसी ने गुरुवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष 2023-24 में 13 मार्च तक 400 अरब यूनिट बिजली उत्पादन का आंकड़ा पार हो गया है। पिछले वित्त वर्ष में इस अवधि में 399.3 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ था। कंपनी ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में एक सितंबर 2023 को सबसे ज्यादा 142.8 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ है। (प्रेट्र)

केंद्र ने शहद का न्यूनतम निर्यात मूल्य किया तय

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शहद के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) दो हजार डालर प्रति टन तय किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) की ओर से गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, नया मूल्य तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दिसंबर 2024 तक प्रभावी होगा। इससे कम मूल्य पर शहद के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी। चालू वित्त वर्ष में जनवरी तक 15.32 करोड़ डालर का शहद निर्यात किया जा चुका है। (प्रेट्र)

वर्ष 2024 के अंत तक ब्याज दरों में कटौती संभव

अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2024-25 में सात प्रतिशत की विकास दर का अनुमान लगाया

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : लगातार दो तिमाहियों के दौरान भारत की आर्थिक विकास दर अप्रत्याशित तौर पर आठ प्रतिशत से ज्यादा रहने के बाद अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों की सोच बदल गई है। मूडीज के बाद अब एक और अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच ने कहा है कि भारत वर्ष 2024-25 में सात प्रतिशत की विकास दर हासिल कर लेगा। ऐसा करने से कोरोना काल के बाद भारत लगातार तेज आर्थिक विकास दर हासिल करने वाला दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में इकलौता देश होगा।

रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2024 की अंतिम छमाही (जुलाई से दिसंबर, 2024) में आरबीआइ की तरफ से ब्याज दरों में 0.50 प्रतिशत की कटौती की भी जा सकती है। कई दूसरे विशेषज्ञों ने हाल ही में इस बात को लेकर उम्मीद जताई है कि अगले वित्त वर्ष के अंत तक ब्याज दरों में कटौती की संभावना बन रही है। केंद्रीय उद्योग व वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी हाल में उम्मीद जताई थी कि कुछ महीनों में ब्याज दरों में कटौती होगी, जिससे कर्ज सस्ते होंगे।

फिच की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत रहेगी। यह केंद्र सरकार की तरफ से 7.6 प्रतिशत की आर्थिक विकास दर के अनुमान से ज्यादा है। तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर, 2024 में भारतीय इकोनमी ने 8.4 प्रतिशत की छलांग लगाई है। इसकी वजह से सरकारी एजेंसियों के साथ ही विदेशी आर्थिक एजेंसियां भी विकास दर के अनुमान में संशोधन कर रही हैं। बता दें कि जब वित्त वर्ष की शुरुआत हुई थी तब विकास दर के 6.5 प्रतिशत के करीब ही रहने का अनुमान लगाया गया था।

- वित्त वर्ष 2023-24 में आर्थिक विकास दर 7.8 प्रतिशत रहेगी
- तीसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत रही अर्थव्यवस्था में वृद्धि

वैश्विक विकास दर में बढ़ोतरी संभव

फिच की इस रिपोर्ट का एक संदेश यह भी है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की स्थिति वर्ष 2024 में अनुमान से बेहतर होगी। क्योंकि इसने वैश्विक ग्रोथ रेट को 0.3 प्रतिशत बढ़ाकर 2.4 प्रतिशत कर दिया है। यह सुधार चीन के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 4.6 फीसद से घटा कर 4.5 प्रतिशत करने के बावजूद हुआ है। दरअसल, अमेरिका की विकास दर उम्मीद से बेहतर रहने वाली है, इससे चीन की इकोनमी में गिरावट का असर नहीं होगा। रूस और ब्राजील की इकोनमी का प्रदर्शन भी उम्मीद से बेहतर रहने की उम्मीद है। ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों में अभी मंदी है लेकिन फिच का कहना है कि इनकी अर्थव्यवस्था में भी अगले वर्ष 2025 में सुधार होगा। भारत के बारे में फिच का कहना है कि घरेलू निवेश और मांग बढ़ने से इकोनमी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा।

क्रिसिल ने जून में ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की तरफ से गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट में जून, 2024 में आरबीआइ की मौद्रिक नीति समीक्षा में ही ब्याज दरों में कटौती की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत के राजकोषीय संतुलन की स्थिति ठीक है लेकिन आरबीआइ संभवत: कुछ दिन और महंगाई की स्थिति पर नजर रखेगा। क्रिसिल ने आर्थिक विकास दर के वर्ष 2024-25 में 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है जबकि चालू वित्त वर्ष में इसके 7.6 प्रतिशत रहने की बात कही है।

पेटीएम की यूपीआइ सेवा जारी रहेगी, थर्ड पार्टी लाइसेंस मिला

मुंबई, प्रेट्र: डिजिटल पेमेंट प्लेटफार्म पेटीएम को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) की ओर से मल्टी-बैंक माडल के तहत थर्ड पार्टी एप का लाइसेंस मिल गया है। एनपीसीआइ ने गुरुवार को बताया कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआइ और यस बैंक पेटीएम के लिए पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर (पीएसपी) के तौर पर काम करेंगे।

इसके अलावा, यस बैंक पेटीएम के मौजूदा और नए यूपीआइ मर्चेंट के लिए मर्चेंट अधिग्रहण बैंक के तौर पर काम करेगा। एनपीसीआइ ने कहा है कि अब पेटीएम मौजूदा यूजर और मर्चेंट बिना किसी बाधा के यूपीआइ लेनदेन और आटो-पे सेवा जारी रख सकेंगे। पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड को सभी मौजूदा यूपीआइ हैंडल (खाते) नए पीएसपी बैंक के पास जल्द हस्तांतरित करने के लिए कहा है। बता दें कि आरबीआइ ने पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च के बाद खातों, पेटीएम वालेट, फास्टैग में किसी भी प्रकार की जमा स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है।

पीपीबीएल से 20 प्रतिशत कर्मचारी हटाएगी पेटीएम

मुंबई, रायटर: डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम अपनी बैंकिंग इकाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) से 20 प्रतिशत कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। माना जा रहा है कि आरबीआइ द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक के कामकाज पर 15 मार्च के बाद रोक लगाने के चलते उसने यह कदम उठाया है। दिसंबर, 2023 तक पेटीएम पेमेंट्स बैंक में 2,275 कर्मचारी थे। पीपीबीएस में पेटीएम की 49 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

चुनावी नतीजों तक बाजार में अस्थिरता संभव

- वैल्यू स्टाक का अध्ययन, इकोनमी के आधारभूत तत्व बेहद मजबूत
- एजेंसी ने कहा- लंबे समय के लिए पूरी तरह सुरक्षित है निवेश

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : पिछले दो दिनों में शेयर बाजार में जिस तरह की अस्थिरता देखी गई है वह मई-जून, 2024 तक बनी रह सकती है। दरअसल आम चुनाव के परिणाम आने तक बाजार में अस्थिरता बनी रही सकती है। यह बात शेयर बाजार पर शोध करने वाली एजेंसी वैल्यू स्टाक ने गुरुवार को जारी अपनी एक अध्ययन रिपोर्ट में कही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय इकोनमी के आधारभूत तत्व बेहद मजबूत हैं लिहाजा मौजूदा अस्थिरता के बावजूद अगर लंबे समय तक यहां निवेश करना है तो वह काफी सुरक्षित है। यह रिपोर्ट पिछले चार आम चुनावी सालों के दौरान शेयर बाजार के प्रदर्शन और आम निवेशकों के रिटर्न की तस्वीर पेश करती है। यह बताता है कि हर चुनावी साल में आम निवेशकों को दूसरे वर्षों के मुकाबले बेहतर रिटर्न हासिल हुआ है। यह बात भी सामने आती है कि वर्ष 2009 के आम चुनाव के बाद निवेशकों के रिटर्न का स्तर कम हुआ है। देखना है कि मौजूदा चुनावी साल (2024) में क्या स्थिति रहती है।

यह रिपोर्ट निफ्टी 50 के मानक पर तैयार की गई है। इसके मुताबिक वर्ष 2004 के चुनाव के पहले के छह महीनों में शेयर बाजार में 10.5 प्रतिशत का रिटर्न मिला था। उस वर्ष चुनाव के बाद छह महीनों में रिटर्न 8.6 प्रतिशत रहा है। इसके बाद के 2014 के आम चुनाव के पहले छह महीनों में रिटर्न 36.9 प्रतिशत जबकि चुनाव के बाद के छह महीनों में 36.1 प्रतिशत रहा। वर्ष 2019 में भी आम चुनाव हुए थे, तब पहले के छह महीनों का रिटर्न 18.9 प्रतिशत रहा था और बाद के छह महीनों का रिटर्न 2.2 प्रतिशत रहा था। इस तरह से पिछले चार आम चुनावी साल में निवेशकों के रिटर्न की बात कहें तो यह क्रमशः 19.9 प्रतिशत, 86.3 प्रतिशत, 38.4 प्रतिशत और 13.2 प्रतिशत रहा है।

आइटी में खरीदारी से 335 अंक उछला सेंसेक्स

मुंबई, प्रेट्र: आइटी और कैपिटल गुड्स शेयरों में खरीदारी की बदौलत घरेलू शेयर बाजार गुरुवार को बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। बीएसई का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 335.39 अंक की वृद्धि के साथ 73,097.28 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह एनएसई का निफ्टी 148.95 अंक बढ़कर 22,146.65 अंक पर बंद हुआ। इस तेजी से बीएसई का कुल पूंजीकरण 7.81 लाख करोड़ रुपये बढ़ा है। अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भी 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी में 43 लाख नए डीमैट खाते खोले गए हैं। अब कुल डीमैट खाते 14.8 करोड़ हो गए हैं।

1,700 रुपये चढ़ी चांदी: गुरुवार को चांदी के मूल्य में 1,700 रुपये की वृद्धि हुई। अब यह 77 हजार रुपये प्रति किलो हो गई है। वहीं, सोना 250 रुपये बढ़कर 66,200 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।

सरकारी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत से कम करेंगे पांच बैंक

नई दिल्ली, प्रेट्र : बैंक आफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूको बैंक सहित पांच सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी हिस्सेदारी को 75 प्रतिशत से कम करेंगे। ये बैंक सेबी के सार्वजनिक शेयरधारिता के मानदंडों का पालन करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में से चार 31 मार्च, 2023 तक इन मानदंडों का अनुपालन कर रहे थे।

फिलहाल दिल्ली स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक में सरकार की हिस्सेदारी 98.25 प्रतिशत है। वहीं चेन्नई स्थित इंडियन ओवरसीज बैंक में 96.38 प्रतिशत, यूको बैंक में 95.39 प्रतिशत, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में 93.08 प्रतिशत, बैंक आफ महाराष्ट्र में सरकारी हिस्सेदारी 86.46 प्रतिशत है। सेबी के नियमों के मुताबिक सभी सूचीबद्ध कंपनियों को 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता को सुनिश्चित करना आवश्यक है। सरकारी बैंकों के पास 25 प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकता को पूरा करने के लिए अगस्त, 2024 तक का समय है।

खाद्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के बावजूद थोक महंगाई घटकर 0.2 प्रतिशत रही

नई दिल्ली, प्रेट्र: खाद्य पदार्थों की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद थोक मुद्रास्फीति की दर फरवरी में मामूली गिरावट के साथ 0.2 प्रतिशत रह गई। जनवरी में यह आंकड़ा 0.27 प्रतिशत था। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) पर आधारित मुद्रास्फीति पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक दायरे में थी लेकिन नवंबर, 2023 में यह 0.26 प्रतिशत पर सकारात्मक हो गई थी। एक साल पहले फरवरी, 2023 में महंगाई दर 3.85 प्रतिशत रही थी।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बुधवार को थोक मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी करते हुए कहा, 'अखिल भारतीय डब्ल्यूपीआइ संख्या पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर फरवरी, 2024 में 0.20 प्रतिशत (अस्थायी) रही है।' आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी के 6.85 प्रतिशत से मामूली रूप से बढ़कर 6.95 प्रतिशत हो गई। सब्जियों की महंगाई दर जनवरी के 19.71 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी में 19.78 प्रतिशत हो गई। दालों की थोक महंगाई दर फरवरी में 18.48 प्रतिशत रही जबकि जनवरी में यह 16.06 प्रतिशत थी। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ईंधन और ऊर्जा खंड में महंगाई दर फरवरी में 1.59 प्रतिशत और घट गई।

जनवरी में इस खंड में 0.51 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज की गई थी। मैन्यूफैक्चरिंग उत्पादों की कीमतों में भी जनवरी के 1.13 प्रतिशत की तुलना में 1.27 प्रतिशत की गिरावट आई। थोक मूल्य सूचकांक से थोक बाजार में उत्पादकों को मिलने वाली कीमतों के बारे में पता चलता है। हालांकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर दर्ज खुदरा मुद्रास्फीति इन उत्पादों की खुदरा कीमतों को दर्शाती है। आरबीआइ अपने मौद्रिक नीति कदमों के लिए खुदरा मुद्रास्फीति को ही आधार बनाता है। कुछ दिन पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 5.09 प्रतिशत थी और लगातार छठे महीने आरबीआइ के छह प्रतिशत के संतोषजनक दायरे के भीतर रही।

- इसी वर्ष जनवरी में 0.27 प्रतिशत थी थोक महंगाई, जो पिछले वर्ष फरवरी में 3.85 प्रतिशत थी
- पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर तक नकारात्मक थी थोक महंगाई, नवंबर में सकारात्मक हुई

राष्ट्रीय फलक

सिंदी ड्राई पोर्ट से बांग्लादेश माल भेजने में समय और लागत की बचत होगी : गडकरी

राज्य ब्यूरो, मुंबई

- केंद्रीय मंत्री ने वर्धा जिले में सिंदी ड्राई पोर्ट पर मल्टी-माडल लाजिस्टिक्स पार्क का किया उद्घाटन
- गडकरी ने कहा, यह बंदरगाह एक लाख नौकरियां, रोजगार और व्यापार के अवसर पैदा करेगा

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को विदर्भ क्षेत्र के वर्धा जिले में सिंदी ड्राई पोर्ट पर मल्टी-माडल लाजिस्टिक्स पार्क का उद्घाटन किया। रेल टर्मिनल सेवाओं के परीक्षण को हरी झंडी भी दिखाई। इस दौरान गडकरी ने कहा, हजारों ट्रक सिंदी ड्राई पोर्ट पर पहुंचेंगे और माल बंगाल के हल्दिया के रास्ते बांग्लादेश को रेक पर भेजा जाएगा। अब यह माल मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा, यह ड्राई पोर्ट करीब एक लाख नौकरियां, रोजगार और व्यापार के कई अवसर पैदा करेगा। गडकरी ने कहा, महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के लिए 1,200 करोड़ रुपये दिए हैं, जबकि जेएनपीटी ने 600 करोड़ रुपये दिए हैं। इससे औद्योगिक क्लस्टर, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम व प्री-कूलिंग प्लांट बनाने में मदद मिलेगी। उम्मीद जताई कि सिंदी ड्राई पोर्ट नागपुर को देश का लाजिस्टिक्स केंद्र बनाने में मददगार साबित होगा।

उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, महिलाओं को सशक्त होना चाहिए और उन्हें समान अधिकार मिलना चाहिए, श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, जबकि किसानों को उनकी उपज के लिए अच्छी कीमत मिलनी चाहिए।

कर्नाटक, तेलंगाना व राजस्थान को सड़कों के लिए 3208.4 करोड़

नई दिल्ली, प्रेट्र: सड़क मंत्रालय ने कर्नाटक, तेलंगाना व राजस्थान में विभिन्न सड़क विकास परियोजनाओं के लिए 3208.4 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। मंत्रालय ने कहा, परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के साथ ही सामाजिक-आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कनेक्टिविटी में सुधार करना भी है। मंत्रालय ने कर्नाटक के विभिन्न जिलों में 2055.62 किलोमीटर लंबाई वाली 295 सड़क परियोजनाओं के विस्तार व मरम्मत के लिए 1385.60 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। वहीं तेलंगाना में 435.29 किलोमीटर की लंबाई वाली 31 सड़क परियोजनाओं के लिए 850 करोड़ और राजस्थान के 31 प्रमुख जिला मार्गों और राज्य राजमार्गों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 972.80 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

युवती ने पसंद के लड़के से की शादी तो पंचों ने लगाया छह लाख का जुर्माना

जासं, जोधपुर : राजस्थान के पाली जिले के चोटिला गांव में युवती का मनपसंद युवक से शादी करना जातिगत पंचों को रास नहीं आया। उन्होंने लड़की के परिवार को समाज से बहिष्कृत करने के साथ ही छह लाख रुपये का जुर्माना भी लगा दिया। युवती ने अपमान और जिल्लत के बाद 18 पंचों के खिलाफ रोहट थाने में मामला दर्ज कराया है।

चोटिला गांव निवासी अर्जुनराम (31 वर्ष) ने बताया कि उनकी भांजी खुशबु की सगाई पहले प्रकाश नामक युवक से हुई थी। बाद में खुशबू ने जालोर जिले के किशनगढ़ निवासी युवक से शादी कर ली। इससे प्रकाश व उसका परिवार नाराज हो गया। इन्हें धमकियां मिलने लगीं। समाज के पंच उनसे मिले और विवाद सुलझाने की बात कही। इसके बाद पंचों ने लड़की के परिवार को दोषी मानते हुए 6 लाख का जुर्माना लगा दिया। पीड़ित परिवार ने पंचों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुटी है।

नकली देसी घी बेचने के दोषियों को उम्रकैद

जागरण संवाददाता, कानपुर

- 2009 में एसटीएफ ने कानपुर में छापा मारकर तीन को पकड़ा था
- एक की हो चुकी मौत, दो पर 1.62-1.62 लाख रुपये का जुर्माना भी

कानपुर स्थित अपर जिला जज की कोर्ट ने नामी कंपनियों के नाम पर नकली देशी घी बेचने में दो लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 1.62-1.62 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। एक अभियुक्त की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी। 15 साल तक मुकदमे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया है। एसटीएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया था। उन पर मानव के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव डालने, फर्जीवाड़ा करने की धाराएं लगाई गई थीं।

एसटीएफ को शिकायत मिली थी कि कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद (अब प्रयागराज) में नकली पराग, अमूल के टेट्रा और पाली पैक छपवाकर उनमें नकली देशी घी बेचा जा रहा है। तीन मार्च, 2009 को एसटीएफ की टीम ने कानपुर के गांधीनगर में छापा मारा तो वहां तीन लोग ड्रम में रखे मिलावटी (अपमिश्रण) अनिक घी, अमूल, पराग, पारस के पैक में तौलकर भरते, गत्तों में पैक करते मिले। एसटीएफ की पूछताछ में उन्होंने बताया था कि वे रिफाइंड आयल के साथ मिलावट कर नकली घी बनाते और उसको नामी कंपनियों के नकली पैकिंग में भरकर बेचते हैं।

22 जुलाई, 2013 को अदालत ने अभियुक्तों पर आरोप तय किए थे। अभियोजन ने आठ लोगों की गवाही कराई। प्रयोगशाला में जांच के बाद नमूनों के मिलावटी होने के साक्ष्य पेश किए। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मनोज गुप्ता की मौत हो गई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बाकी दोनों दोषियों को सजा सुनाई। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर अब भले ही कानून बदल गया हो, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मिलावट पर उम्र कैद की सजा बरकरार है।

> अभियोजन की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि अभियुक्तों ने लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर उनके जीवन को संकट में डालने का काम किया है। यह किसी भी सूरत में क्षमा योग्य नहीं है। इसलिए दोषियों को अधिकतम दंड दिया जाए।
> – अरविंद डिमरी, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता

इससे पहले कोर्ट लगा चुका है एक करोड़ रुपये जुर्माना : अदालत ने इससे पहले ब्रांडेड कंपनी के चिप्स व सेव में मिलावट पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। वहीं मिलावटी दूध बेचने वाली एक कंपनी के प्रबंधक और दूसरी कंपनी के सीनियर केमिस्ट को छह माह की कैद की सजा के साथ दोनों कंपनियों पर 20-20 लाख का जुर्माना लगाया गया था। वहीं, सिंथेटिक सिरके में मिलावट के 1978 में दर्ज मुकदमे में 40 साल बाद फैसला आया था, जिसमें पांच दोषियों को कोर्ट ने छह-छह माह कैद की सजा सुनाई थी।

सिंहस्थ-2028 के पहले बनेगा उज्जैन स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे

राज्य ब्यूरो, भोपाल

- 12 टावर के रोप वे को नेशनल हाईवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लि. बनवाएगी

उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन के लिए देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। श्री महाकाल महालोक परिसर बनने के बाद इसमें काफी वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए उज्जैन में लगातार विकास कार्य किए जा रहे हैं। अब रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक पहुंच आसान करने के लिए रोप वे बनाया जा रहा है। रोप वे पौने दो किलोमीटर लंबा होगा, इससे मात्र पांच मिनट में मंदिर पहुंचा जा सकेगा। 153.72 करोड़ रुपये की लागत वाले 12 टावर के इस रोप वे को नेशनल हाईवे लाजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड बनवाएगी। इसके निर्माण का लक्ष्य सिंहस्थ-2028 के पहले रखा गया है।

सड़क विकास निगम के अधिकारियों का कहना है कि टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, कंपनी को 24 माह में रोप वे बनाना होगा और उसका संचालन, रखरखाव भी वही करेगी। उधर, इसके लिए लोक निर्माण विभाग एवं नेशनल हाईवे लाजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच जो अनुबंध हुआ है, उस पर गुरुवार को मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने भी अनुमति प्रदान कर दी।

श्री महाकाल महालोक परिसर बनने के बाद से उज्जैन में यातायात का दबाव काफी बढ़ गया है। इसी को देखते हुए सरकार ने उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप-वे योजना बनाई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 24 फरवरी 2022 को रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर तक रोप वे बनाने की घोषणा की थी। रोप-वे का बोर्डिंग स्टेशन इंदौर गेट रेलवे स्टेशन के समीप माल गोदाम की तरफ बनेगा।

खनिजों पर वसूली जाने वाले रायल्टी कर है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने खनिजों पर वसूली जाने वाली रायल्टी को खान और खनिज (विकास और विनियमन) एक्ट, 1957 के तहत टैक्स मानने और इसकी वसूली का अधिकार केंद्र के साथ राज्यों को भी होने के विवादास्पद मुद्दे पर अपना फैसला गुरुवार को सुरक्षित रख लिया।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली नौ न्यायाधीशों की पीठ ने विभिन्न राज्य सरकारों, खनन कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दायर 86 याचिकाओं पर आठ दिन तक सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने कहा था कि संविधान खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति न केवल संसद को बल्कि राज्यों को भी देता है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा था कि इस तरह के अधिकारों को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए।

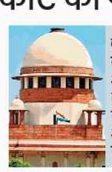

कोर्ट ने राज्यों, खनन कंपनियों और पीएसयू द्वारा दायर 86 याचिकाओं पर आठ दिन तक सुनवाई की

दरअसल, नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ उस जटिल प्रश्न पर विचार कर रही है कि क्या खनन पट्टे पर केंद्र द्वारा एकत्र की गई रायल्टी को कर के रूप में माना जा सकता है, जैसा कि 1989 में सात-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था। छह मार्च को शीर्ष अदालत ने कहा था कि संविधान संसद को खनिज विकास के संबंधों को आधार बनाकर सभी तरह के नियम बनाने का अधिकार नहीं देता है और राज्यों के पास खान और खनिजों को रेगुलेट करने और उन्हें विकसित करने की शक्ति है। 27 फरवरी को शीर्ष अदालत ने इस विवादास्पद मुद्दे पर सुनवाई शुरू की थी कि क्या एमएमआरडीए अधिनियम, 1957 के तहत निकाले गए खनिजों पर देय रायल्टी कर की प्रकृति में आती है या नहीं। यह मुद्दा 1989 में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य के मामले में आए फैसले के बाद उठा, जिसमें शीर्ष अदालत की सात न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि रायल्टी एक कर है। हालांकि शीर्ष अदालत की पांच न्यायाधीशों की पीठ ने 2004 में पश्चिम बंगाल राज्य बनाम केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले में फैसला सुनाते हुए कहा था कि 1989 के फैसले में एक टाइपोग्राफिक त्रुटि थी और रायल्टी एक कर नहीं है। इसके बाद विवाद को नौ न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया।

यूनिकार्न से अर्थव्यवस्था में होगा एक ट्रिलियन डालर का इजाफा

नई दिल्ली, प्रेट्र : उद्योग संगठन सीआइआइ द्वारा गुरुवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक, नए यूनिकार्न से भारतीय अर्थव्यवस्था में एक ट्रिलियन डालर का इजाफा होगा और पांच करोड़ नई नौकरियां पैदा होंगी। साथ ही 2030 तक देश की आर्थिकी सात ट्रिलियन डालर हो जाएगी। एक अरब डालर से अधिक के मूलयांकन वाली स्टार्टअप फर्मों को यूनिकार्न माना जाता है।

मैकिंजे एंड कंपनी के सहयोग से तैयार की गई 'यूनिकार्न 2.0: एडिंग द नेक्स्ट ट्रिलियन' में कहा गया है कि आने वाले सालों में रिटेल और ई-कामर्स, अगली पीढ़ी की वित्तीय सेवाएं, मैन्यूफैक्चरिंग, एसएएएस और डिजिटल क्षेत्र बड़े पैमाने पर विकास को बढ़ावा देंगे। भारत में 2011 में पहला स्टार्टअप यूनिकार्न बना था और एक दशक बाद देश ने 100 यूनिकार्न का आंकड़ा पार कर लिया है। जनवरी, 2024 तक देश में 113 यूनिकार्न थे, जिनका संयुक्त मूल्यांकन 350 अरब डालर है।

विदेशी फंडिंग पर निर्भर नहीं रहे स्टार्टअप : अमिताभ कांत

नई दिल्ली, प्रेट्र: जी20 शेरपा अमिताभ कांत ने गुरुवार को कहा, भारतीय स्टार्टअप को विदेशी फंडिंग पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने यूनिकार्न को देश की राष्ट्रीय संपत्ति बताते हुए कहा, इनको वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए कोष बनाने की जरूरत है। नीति आयोग के पूर्व सीईओ ने कहा कि स्टार्टअप को अगर आगे बढ़ना है तो कारपोरेट गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए अन्यथा वे संकट में पड़ जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं के बिना भारत 2047 तक 35 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था नहीं बन सकता।

****

3 भारतीय समेत चार लोगों को अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश का प्रयास करने के आरोप में न्यूयार्क में गिरफ्तार किया गया है। कनाडा से आ रही मालगाड़ी से कूदने के बाद अमेरिकी सीमा गश्ती एजेंटों ने 12 मार्च को चारों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार भारतीयों में एक महिला है।

संयुक्त राष्ट्र के केंद्र पर इजरायली हमला, हमास कमांडर मारा गया

इजरायल ने कहा, यह राहत सामग्री पर आतंकियों के कब्जे का सुबूत

रमजान के महीने में 5.76 लाख फलस्तीनी खाना-पानी को मोहताज

यरुशलम, रायटर : इजरायल ने कहा है कि उसने दक्षिणी गाजा में स्थित संयुक्त राष्ट्र के एक खाद्य वितरण केंद्र पर हवाई हमला कर वहां मौजूद हमास के कमांडर को मार गिराया है। इस हमले में एक संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सहित चार अन्य लोग भी मारे गए हैं। इजरायल ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र के केंद्र पर हमास कमांडर की मौजूदगी बताती है कि आतंकी संगठन राहत सामग्री पर कब्जा कर उसे केवल आतंकियों में बांट रहा है।

गाजा पट्टी के खान यूनिस में कतर द्वारा वित्त पोषित हमाद सिटी में इजरायली बमबारी में ध्वस्त मल्टीस्टोरी बिल्डिंग के सामने से गुजरती फलस्तीनी महिला। इजरायल लगातार आक्रमण कर रहा है। रायटर

इजरायली सेना ने मारे गए हमास कमांडर का नाम मुहम्मद अबू हसन बताया है। वह हमास को इजरायली सेना के बारे में खुफिया सूचनाएं उपलब्ध कराता था। साथ ही राहत सामग्री को कब्जे में लेकर उसका वितरण हमास के आतंकियों में करता था जिससे वे अपने ठिकानों में सुरक्षित छिपे रहें और मौका मिलने पर इजरायली सेना पर हमला करें। जबकि हमास ने बयान जारी कर कहा है कि हसन उसके पुलिस बल के अधिकारी थे। संगठन ने हसन की हत्या को इजरायल की कायराना हरकत बताया है। हमास ने राहत सामग्री वितरण में गड़बड़ी करने के इजरायल के आरोप को खारिज किया है। फलस्तीनियों के लिए कार्यरत संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि रफाह में स्थित उसके ठिकाने को निशाना बनाया गया है जो 14 लाख शरणार्थियों को राहत सामग्री वितरित करने वाले केंद्रों में से एक था। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने बताया है कि इजरायली हमले में कुल पांच लोग मारे गए और 22 घायल हुए हैं। इन्हें मिलाकर गाजा में पांच महीने के युद्ध में मरने वाले फलस्तीनियों की कुल संख्या 31,341 हो गई है।

एक अनुमान के अनुसार गाजा में 5,76,000 लोगों खाना और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। यह गाजा की एक चौथाई आबादी है। इन लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने को लेकर इजरायल पर दबाव बढ़ता जा रहा है। गाजा में राहत सामग्री की आपूर्ति के लिए अमेरिका और यूरोप से जहाज रवाना हो चुके हैं और वे समुद्री मार्ग में हैं। इससे पहले अमेरिका गाजा में मालवाहक विमानों से राहत सामग्री गिरा चुका है।

वेस्ट बैंक में तीन फलस्तीनी मारे गए

बुधवार को वेस्ट बैंक और यरुशलम के मध्य एक चेक प्वाइंट पर 15 वर्ष के एक फलस्तीनी किशोर ने धारदार हथियार से हमला कर एक इजरायली सैनिक और एक अन्य सुरक्षाकर्मी को बुरी तरह से घायल कर दिया। बाद में सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग कर उक्त किशोर को मार दिया। जेनिन में हुई एक अन्य घटना में इजरायली सुरक्षाकर्मियों की गोली से दो फलस्तीनी मारे गए हैं।

हाउती ने फिर किया हमला, नुकसान नहीं

गाजा पर इजरायली हमले का विरोध कर रहे यमन के हाउती विद्रोहियों ने गुरुवार को लाल सागर से गुजर रहे जहाजों पर कई एंटी शिप मिसाइलों से हमले की कोशिश की। लेकिन उनका यह हमला विफल रहा, किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह जानकारी अमेरिकी नौसेना की मध्य कमान ने दी है।

भूमध्य सागर पार कर रहे 60 प्रवासियों के डूबने की आशंका

रोम, रायटर: लीबिया से प्रवासियों को मध्य भूमध्य सागर के रास्ते इटली अथवा माल्टा ले जा रहे जहाज से 60 लोगों के डूबने की आशंका है। बचाव कर्मियों ने बताया कि बुधवार को इटली तटरक्षक बलों के समन्वय से बेहद कमजोर स्थिति में 25 लोगों को बचा लिया। दो लोगों को बेहोशी की हालत में हेलीकाप्टर से सिसली ले जाया गया।

बचावकर्मियों ने बताया कि ये लोग सात दिन पहले जाविया, लीबिया से चले थे। तीन दिन बाद उनके जहाज का इंजन खराब हो गया और उनका जहाज कई दिन तक भोजन और पानी के बिना समुद्र में भटकता रहा और रास्ते में ही महिलाओं व एक बच्चे समेत कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। उल्लेखीय है कि मध्य भूमध्य सागर दुनिया के सबसे खतरनाक प्रवास मार्गों में से एक है।

संयुक्त राष्ट्र प्रवासन एजेंसी (आइओएम) ने बताया कि गत वर्ष इस मार्ग का उपयोग करने वाले तकरीबन 2500 प्रवासियों की मौत हो गई अथवा लापता हो गए और 2024 की शुरुआत से अब तक 226 की मौत हो चुकी है। आइओएम ने घटना पर दुखद जताते हुए कहा कि समुद्री गश्त को मजबूत और दुखद घटनाओं को रोकने की जरूरत है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी समुद्री यात्रा के दौरान कई प्रवासियों की मौत हो चुकी है।

रूस में राष्ट्रपति चुनाव से पहले यूक्रेन का मिसाइल हमला

- रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी और खार्किव में किया ड्रोन हमला

मास्को, एपी: यूक्रेन ने रूस के सीमावर्ती क्षेत्र बेलगोरोद में आठ मिसाइलें दागीं। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह घायल हो गए। स्थानीय अधिकारियों ने गुरुवार को कहा, सीमांत कुर्स्क क्षेत्र में भी यूक्रेनी बलों ने हमले का प्रयास किया, पर उसे नाकाम कर दिया गया। इधर,रूस ने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया।

रूस में हाल के दिनों में यूक्रेन की ओर से हमले बढ़ गए हैं। ये हमले ऐसे समय हो रहे हैं, जब रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फिर से चुना जाना तय माना जा रहा है। पुतिन ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश में नागरिकों से ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। रूस में 15-17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं।

यूक्रेन के पूर्वोत्तर सुमी व खार्किव क्षेत्रों में रात के समय रूस की ओर से 36 ड्रोन से हमले को अंजाम दिया गया। सुमी में टीवी व रेडियो स्टेशन को निशाना बनाया गया, टावरों व उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्र के कुछ हिस्से टीवी और रेडियो के सिग्नल नहीं मिल सके। वहीं,रूस के नियंत्रण वाले जपोरीजिया परमाणु संयंत्र ने गुरुवार को दावा किया कि यूक्रेनी सेना ने परिसर में बमबारी की।

रूस की ओर से लड़ रहे सात और नेपाली नागरिकों की मौत

काठमांडू, प्रेट्र: रूस-यूक्रेन युद्ध में गत सप्ताह रूस की सेना में सेवारत सात और नेपाली नागरिकों की मौत हो गई। इसके साथ ही रूस-यूक्रेन में मृत नेपाली नागरिकों की संख्या बढ़कर 19 हो गई है। बता दें कि सैकड़ों नेपाली नागरिक यूक्रेन के खिलाफ रूस के लिए लड़ रहे हैं और कुछ नेपाली नागरिक यूक्रेनी सेना में भी सेवारत हैं लेकिन दोनों विरोधी देशों ने नेपाल सरकार के साथ जानकारी साझा नहीं की।

विदेश मंत्रालय ने रूस-यूक्रेन युद्ध में रूस की ओर से लड़ रहे सात और नेपाली नागरिकों की मौत की पुष्टि करते हुए उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। मंत्रालय ने बताया कि उसने एक बार फिर रूसी सरकार से मृत सैनिकों के आश्रितों को मुआवजा देने, युद्ध में घायलों को इलाज मुहैया कराने और सेना में अवैध रूप से भर्ती युवाओं को वापस भेजने का अनुरोध किया है। नेपाल सरकार ने रूसी सेना में भर्ती युवाओं को वापस लाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अभी हाल ही में उप प्रधानमंत्री काजी श्रेष्ठ ने रूस से रूस-यूक्रेन युद्ध में उसकी ओर से लड़ रहे सेवारत नेपाली नागरिकों की सूची साझा करने को कहा था। इस मुद्दे पर उन्होंने नेपाल में रूसी राजदूत अलेक्सी नोविकोव से भी मुलाकात की थी।

अमेरिकी धरती से बढ़ रहीं भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियां

- भारतवंशियों ने एफबीआइ व न्याय विभाग के अधिकारियों संग बैठक में जताई नाराजगी
- कहा, सामान्य भारतवंशियों व हिंदुओं के विरुद्ध घृणा अपराध रोकने में नाकाम रहीं एजेंसियां

वाशिंगटन, प्रेट्र: अमेरिका के सिलिकान वैली में प्रभावशाली भारतवंशियों ने एफबीआइ, न्याय विभाग और पुलिस के साथ विशेष बैठक में रोष जताते हुए कहा कि हाल के वर्षों में अमेरिकी धरती से भारत के विरुद्ध आतंकी गतिविधियां बढ़ गई हैं। कहा, कैलिफोर्निया में हिंदुओं के खिलाफ घृणा अपराध के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारवंशियों ने अमेरिकी अधिकारियों से इस असमानता व भेदभावपूर्ण व्यवहार को लेकर कोई कार्रवाई न करने पर अप्रसन्नता जताई।

भारतवंशियों ने अमेरिकी अधिकारियों से कहा कि यह बहुत ही निराशाजनक है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। सामुदायिक नेता अजय जैन भुतोरिया ने बैठक में कहा कि अमेरिका में हिंदू, जैन व उनके धार्मिक स्थलों के विरुद्ध घृणा अपराध में वृद्धि एक चुनौतीपूर्ण समस्या है। हाल के दिनों में खालिस्तान समर्थकों ने कई मंदिरों में तोड़फोड़ के साथ भारतीय वाणिज्य दूतावास पर भी हमला किया है। लेकिन कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। इस सप्ताह हुई इस बैठक में लगभग दो दर्जन से अधिक प्रभावशाली भारतीय-अमेरिकियों ने हिस्सा लिया। इसमें न्याय विभाग के सामुदायिक संबंध सेवा के विंसेंट प्लेयर और हरप्रीत सिंह मोखा, एफबीआइ (फेडरल ब्यूरो आफ इंवेस्टिगेशन) अधिकारी और स्थानीय पुलिस ने भाग लिया।

भारत-अमेरिका के रक्षा संबंधों में अविश्वसनीय मजबूती : पेंटागन

पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी सिद्धार्थ अय्यर ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों में अविश्वसनीय मजबूती आई है। दक्षिण एशिया के लिए रक्षा नीति के सेक्रेटरी सिद्धार्थ ने एक सम्मेलन में यह टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिका-भारत के बीच रक्षा साझेदारी तकनीकी सहयोग व समुद्री रणनीति पर आधारित है। इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन द यूएस-इंडिया स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप फोरम एंड कट्स इंटरनेशन ने किया था। अय्यर ने कहा कि हाल के दो वर्षों में दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी तेजी से बढ़ी है।

जापान के हाई कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध को बताया असंवैधानिक

टोक्यो, एपी: जापान की साप्पोरो हाई कोर्ट ने कहा है कि देश में समलैंगिक विवाह की इजाजत ना देना असंवैधानिक है। इसके लिए कानून बनाया जाना चाहिए। साप्पोरो कोर्ट से पहले टोक्यो की अदालत भी ऐसा ही आदेश सुना चुकी है, जिसके बाद समलैंगिक विवाह को वैध करने की मांग ने जोर पकड़ लिया है।

अलग-अलग मामलों में टोक्यो और साप्पोरो कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, प्रतिबंध के कारण नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। भले ही कोर्ट ने यह आदेश दिया हो पर फिर भी समलैंगिक समर्थक चाहते हैं कि सरकार इसे मान्यता देने के लिए कानून बनाए। मौजूदा जी 7 देशों में सिर्फ जापान ही ऐसा देश है जो समलैंगिक जोड़ों को मान्यता नहीं देता है और न ही उन्हें कानूनी सुरक्षा प्राप्त है।

हालांकि जापान में कुछ नगर निगम व जिले ऐसे हैं,जो समलैंगिक सर्टिफिकेट जारी करते हैं, जिनसे ऐसे जोड़ों को फायदा मिलता है पर उनके पास कानूनी मान्यता देने का अधिकार नहीं है।

अमेरिका में टिकटाक पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव से खफा चीन

- कहा, यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों व प्रतिस्पर्धा का सरासर उल्लंघन है

वाशिंगटन, रायटर: अमेरिका के निचले सदन (प्रतिनिधि सभा) में बुधवार को शार्ट वीडियो एप टिकटाक पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पारित होने पर चीन ने कड़ा एतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने गुरुवार को कहा, यह निष्पक्ष नहीं है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि टिकटाक अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा है। यह कार्रवाई प्रतिस्पर्धा न कर पाने की खीज है। प्रतिनिधि सभा में चर्चा के दौरान अमेरिकी सांसदों ने भारत का हवाला देते हुए कहा था कि वह 2020 में ही प्रतिबंध लगा चुका है, हम अब विचार कर रहे हैं। ज्ञात हो, भारत, यूरोपीय यूनियन व कनाडा आदि में टिकटाक पहले से प्रतिबंधित है।

वांग वेनबिन ने कहा, अमेरिका का रुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों व प्रतिस्पर्धा का उल्लंघन है। अमेरिका द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे की बात कहना कोरी बकवास है। प्रतिबंध की इस कार्रवाई का अमेरिका पर उल्टा असर हो सकता है।

वांग वेनबिन। फाइल

अमेरिकी सांसद बोले, भारत में 2020 में ही बैन लग चुका, हम अब करने जा रहे

बुधवार को प्रतिनिधि सभा में टिकटाक की वर्तमान स्वामित्व संरचना को देश की सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए 65 के मुकाबले 352 मतों से पारित किया गया। प्रस्ताव में टिकटाक के सामने दो विकल्पों रखे गए हैं, या तो छह माह में उसकी मूल कंपनी बाइटडांस टिकटाक को अमेरिका में बेच दे या प्रतिबंध को तैयार रहे। प्रस्ताव को अब उच्च सदन सीनेट में भेजा जाएगा। 15 करोड़ अमेरिकियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला टिकटाक, चीनी प्रौद्योगिकी फर्म बाइटडांस लिमिटेड की सहायक कंपनी है।

ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के विमान के सिग्नल जाम, रूस पर संदेह

लंदन, रायटर: ब्रिटेन के रक्षा मंत्री के साथ यात्रा करने वाले एक पत्रकार और सरकारी सूत्र ने गुरुवार को कहा कि पौलैंड से ब्रिटेन लौटने के लिए रक्षा मंत्री ग्रांट शाप्स द्वारा प्रयुक्त विमान के उपग्रह सिग्नल रूस ने जाम किए गए थे। विमान के सिग्नल जाम करने का संदेह रूस पर है।

सूत्र और पत्रकार के अनुसार, रूस के कैलिनिनग्राद के बाल्टिक एक्सक्लेव के नजदीक से उड़ान भरते समय विमान के जीपीएस सिग्नल तकरीबन 30 मिनट के लिए बाधित हो गए। इस दौरान मोबाइल फोन इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सके और विमान को अपनी लोकेशन निर्धारित करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का प्रयोग करने पर मजबूर होना पड़ा। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने बुधवार को घटित घटना की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विमान की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था और कैलिनिनग्राद के निकट जीपीएस सिग्नल का जाम होना असामान्य नहीं है।

न्यूज गैलरी

फ्लोरिडा में जेट स्की दुर्घटना में भारतीय छात्र की मौत

वाशिंगटन : अमेरिका के फ्लोरिडा प्रांत में जेट स्की दुर्घटना में 27 वर्षीय भारतीय छात्र वेंकटरमण पिट्टाला की मौत हो गई। छात्र की जेट स्की शनिवार को दूसरी जेट स्की से टकरा गई थी। तेलंगाना निवासी वेंकटरमण इंडियाना यूनिवर्सिटी पुर्दुए यूनिवर्सिटी में स्नातक का छात्र था। मई में वह ग्रेजुएट होने वाला था। उनकी पर्सनल वाटरक्राफ्ट को आमतौर पर जेट स्की कहा जाता है। यह बाइक की तरह पानी पर चलती है। फ्लोरिडा मत्स्य एवं वन्यजीव संरक्षण आयोग ने सोमवार को दुर्घटना पर रिपोर्ट सौंपी। (प्रेट्र)

निज्जर मामले में होने दी जाए जांच : न्यूजीलैंड

नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के उपप्रधानमंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत पर लगाए गए कनाडा के आरोपों पर चल रही जांच होने दी जाए। जांच के बाद ही इस मामले में कोई निष्कर्ष निकाला जाए। निज्जर की पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया में गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भारतीय एजेंट की संलिप्तता को लेकर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को भारत ने बेतुका करार देकर खारिज कर दिया है। (एएनआइ)

अब डेनमार्क की सेना में की जाएगी महिलाओं की भी भर्ती

कोपेनहेगन : यूरोप में बदलते सुरक्षा परिदृश्य के बीच डेनमार्क ने सेना में महिलाओं को भी भर्ती करने का निर्णय लिया है। साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए सेना में सेवाकाल को चार महीने से बढ़ाकर 11 महीने किया जाएगा। डेनमार्क की पीएम मेट फ्रेडरिकसन ने कहा, नई रणनीति का लक्ष्य सेना में युवाओं का अनुपात बढ़ाना है। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं को चुनौती दी जा रही है। ऐसे में हम युद्ध, विनाश को टालने के लिए संगठित हो रहे हैं। वर्तमान में डेनमार्क की सेना में नौ हजार सैनिक हैं। नाटो के संस्थापक सदस्य डेनमार्क का इरादा अगले पांच वर्षों में रक्षा खर्च 40.5 अरब डेनिश क्राउन (5.9 अरब डालर) तक बढ़ाने का है। ज्ञात हो, 1990 की शुरुआत में शीत युद्ध का अंत होने के बाद डेनमार्क ने सैन्य शक्ति कम कर दी थी। (एएनआइ)

चीन के रेस्टोरेंट में विस्फोट, सात की मौत, 27 घायल

- विस्फोट स्थल पर देशी-विदेशी मीडिया को जाने से रोका, अभद्रता
- सरकारी मीडिया ने प्रशासन के रवैया पर जताया कड़ा विरोध
- बड़ी घटना की आशंका, प्रशासन पर तथ्यों को छिपाने का शक

बीजिंग, प्रेट्र: चीन की राजधानी बीजिंग के नजदीक सान्हे शहर के यांजीआओ उपनगर की फ्राइड चिकेन शाप में गुरुवार को हुए विस्फोट में सात लोग मारे गए और 27 घायल हुए हैं। फिलहाल विस्फोट का कारण गैस लीक बताया गया है लेकिन जिस तरह से घटनास्थल पर मीडिया और अन्य प्रमुख लोगों को जाने से रोका जा रहा है उससे मरने वालों की संख्या ज्यादा होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर जैसे-तैसे पहुंचे सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी के कैमरामैन को सुरक्षाकर्मियों ने घेरकर घटनास्थल का फुटेज लेने से रोक दिया और वहां से जाने के लिए विवश कर दिया। इन स्थितियों में विस्फोट के आतंकी वारदात होने से भी इन्कार नहीं किया जा रहा है।

चीन सरकार द्वारा संचालित आल चाइना जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ने प्रशासन के इस रुख पर कड़ा विरोध जताया है। कहा है कि पत्रकारों को कर्तव्य निर्वहन के दौरान अधिकारी इस तरह क्रूरता से नहीं रोक सकते हैं। एसोसिएशन ने प्रशासन से आचरण में बदलाव का अनुरोध किया है। इससे पहले भी कई मौकों पर पुलिस ने मीडियाकर्मियों को घटनाओं की कवरेज के दौरान रोका है और अभद्रता की है। चीन के इंटरनेट मीडिया पर पत्रकारों के विरोध प्रदर्शन का समाचार प्रमुखता पा रहा है और पत्रकारों से माफी मांगने की मांग जोर पकड़ रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने विदेशी पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर में कहा, मीडिया कवरेज को लेकर चीन के नियम तय हैं और वह कोई भी तथ्य छिपाने में विश्वास नहीं रखता है।

उत्तर कोरिया ने दिया युद्ध की तैयारी में जुटने का संकेत

- दक्षिण कोरिया ने भी सीमा के पास टैंक से दागे गोले

सियोल, एपी: उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अत्याधुनिक युद्धक टैंक चलाकर अपनी सेना के प्रशिक्षण में भाग लेकर युद्ध की तैयारी में जुटे होने संकेत दिया है। जवाब में दक्षिण कोरिया ने भी गुरुवार को सीमा के समीप टैंक से गोले दागकर पड़ोसी देश को उत्तर दिया।

दक्षिण कोरिया व अमेरिका के 11 दिनी वार्षिक सैन्य अभ्यास को उत्तर कोरिया अपने ऊपर आक्रमण का पूर्वाभ्यास मानता है। उसने उचित सैन्य गतिविधियों से उत्तर देने की बात कही थी।

उत्तर कोरिया के बुधवार के प्रशिक्षण का उद्देश्य टैंक संचालित करने वाले सैनिकों की युद्ध क्षमता का परीक्षण करना था। आधिकारिक कोरियाई सेंट्रल न्यूज एजेंसी के अनुसार, किम ने नए प्रकार के मुख्य युद्धक टैंक को विश्व का सबसे शक्तिशाली बताया है। किम ने नए टैंक पर संतोष व्यक्त किया। पहले प्रदर्शन में टैंक ने अपनी हमलावर शक्ति प्रदर्शित की।

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास के बीच गुरुवार को उत्तर कोरियाई लीडर किम जोंग उन ने नए प्रकार के युद्धक टैंक को चलाकर अपनी सेना की हौसलाअफजाई की। एपी

दक्षिण कोरिया नहीं मानता उत्तर कोरिया को परमाणु संपन्न देश : दक्षिण कोरिया ने गुरुवार को कहा कि वह उत्तर कोरिया को परमाणु संपन्न देश नहीं मानता है। विदेश मंत्री ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की टिप्पणी के उत्तर में यह टिप्पणी की। पुतिन ने कहा था कि उत्तर कोरिया के पास उसकी अपनी परमाणु छतरी है और उसने रूस से सहायता नहीं मांगी है।

उत्तर कोरिया से तनाव के बीच गुरुवार को सीमावर्ती पोचेन में दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड में हिस्सा लिया। संयुक्त अभ्यास के दौरान कोरियाई के1ए2 टैंक से फायरिंग की गई। एपी

अमेरिका में बढ़ रहे हिंदूफोबिया से लड़ने की जरूरत : भारतवंशी सांसद

वाशिंगटन,प्रेट्र: अमेरिका में भारतवंशी सांसद श्री थानेदार ने कहा कि हाल में अमेरिका में 'हिंदू फोबिया' (हिंदुओं से असुरक्षा की भावना) में वृद्धि हुई है और इससे लड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस देश में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। यह बात उन्होंने समुदाय के प्रति बढ़ रहे घृणा अपराध से लड़ने की मांग करने वाले हिंदू नेताओं व संगठनों की बैठक के दौरान कही।

उन्होंने कहा, हम अमेरिका में बहुत अधिक हिंदू फोबिया देख रहे हैं। हालांकि हमने कैलिफार्निया एसबी403 (जाति भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विधयेक) देखा है और यह महज शुरुआत है। दुनियाभर में हमारे मंदिरों व हिंदुओं पर हमले होते हैं और इसी कारण मैंने हिंदू काकस बनाने का निर्णय लिया। अमेरिकी संसद में पहली बार हमारे पास हिंदू काकस है। हम लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई पहल कर रहे हैं। हमें डर, कट्टरता और नफरत से लड़ने की जरूरत है।

असेंबली की आरक्षित सीटें आवंटित करने की एसआइसी की मांग खारिज

पेशावर, प्रेट्र: जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआइ को पेशावर हाई कोर्ट ने गुरुवार को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने गुरुवार को राष्ट्रीय व प्रांतीय विधायिकाओं में महिलाओं, अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटें आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की याचिका को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।

सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआइसी), इस्लामी राजनीतिक और बरेलवी धार्मिक दलों का सियासी गठबंधन है। इसमें आठ फरवरी को हुए चुनाव में जीते इमरान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार शामिल थे। एसआइसी ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी थी। वहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुरुवार को इमरान को अदियाला जेल में पार्टी के चार वकीलों से मिलने की इजाजत दे दी। कुछ दिनों पहले पंजाब की प्रांतीय सरकार ने पूर्व पीएम को दो हफ्ते के लिए जेल में किसी भी बैठक करने पर प्रतिबंध लगा दिया था।

इमरान खान की पार्टी पीटीआइ को हाई कोर्ट से लगा झटका

पाकिस्तान चुनाव के मुद्दे पर सुनवाई करेगी अमेरिकी कांग्रेस की समिति

वाशिंगटन, प्रेट्र : अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति आगामी 20 मार्च को पाकिस्तान चुनाव के मुद्दे पर सुनवाई करेगी। चुनावों में धांधली के आरोप लगे थे। सुनवाई का शीर्षक 'चुनाव के बाद' पाकिस्तान में लोकतंत्र के भविष्य और अमेरिका-पाकिस्तानों संबंधों की जांच' है।

पीपीपी को उपचुनाव में मिलीं सीनेट की छह सीटें

बिलावल भुट्टो के नेतृत्व वाली पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने सीनेट के उपचुनाव में गुरुवार को छह में से चार सीटें जीत लीं। आठ फरवरी को हुए आम चुनावों में सीनेटरों के राष्ट्रीय या प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद नेशनल असेंबली, सिंध और बलूचिस्तान प्रांतीय विधानसभाओं की खाली छह सीनेट सीटों पर मतदान हुआ था। इस बीच, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने नेशनल और प्रांतीय असेंबलियों की खाली सीटों के लिए उपचुनाव के लिए 21 अप्रैल की तारीख घोषित की है।

स्पेसएक्स के राकेट 'स्टारशिप' ने भरी तीसरी परीक्षण उड़ान

मेक्सिको सिटी, एपी: अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के शक्तिशाली राकेट 'स्टारशिप' ने गुरुवार को दक्षिण टेक्सास से तीसरी परीक्षण उड़ान भरी। पिछले दो प्रयासों की तुलना में राकेट अधिक दूर तक गया, पर पृथ्वी पर लौटते समय इससे संपर्क टूट गया। पिछले साल 'स्टारशिप' की दो परीक्षण उड़ान विफल हो गई थी। 397 फीट ऊंचा 'स्टारशिप' सबसे शक्तिशाली राकेट है।

इस राकेट को कंपनी के स्टारबेस प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित किया गया। राकेट ने किसी अंतरिक्ष यात्री या उपग्रह के बिना उड़ान भरी। स्पेस एक्स ने कहा, उड़ान भरने के लगभग एक घंटे बाद हिंद महासागर में अपने लक्ष्य के करीब पहुंचते ही राकेट से संपर्क टूट गया। स्टारशिप' की लांचिंग पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की नजर थी, क्योंकि नासा को आने वाले वर्षों में एक बार फिर चंद्रमा पर इंसानों को ले जाने के लिए 'स्टारशिप' जैसे राकेट की जरूरत होगी।

पनामा पेपर मिल मामले में नवाज के दोनों बेटों को राहत

- कोर्ट ने हसन और हुसैन का गिरफ्तारी वारंट किया निरस्त
- मामले में नाम आने के बाद 2018 में चले गए थे ब्रिटेन

इस्लामाबाद, प्रेट्र: पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ के परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को ब्रिटेन से लौटे नवाज के दोनों बेटों के विरुद्ध पनामा पेपर मिल से जुड़े भ्रष्टाचार के तीन मामलों में स्थायी गिरफ्तारी वारंट रद कर दिया। नवाज के बेटों हसन व हुसैन ने पनामा पेपर मिल से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में नाम आने के बाद 2018 में देश छोड़ दिया था। ज्ञात हो, कोर्ट ने दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया था। दोनों गुरुवार को ही स्वदेश लौटे हैं।

इस्लामाबाद आतंक-निरोधी कोर्ट ने सात मार्च को दोनों के विरुद्ध गुरुवार तक गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिया था। इसके बाद उनकी सुरक्षित वापसी की आखिरी बाधा दूर हो गई। गुरुवार को हसन व हुसैन दोनों इस्लामाबाद की जवाबदेही अदालत में पेश हुए, जिसने दलीलें सुनने के बाद फ्लैगशिप, अल-अजीजिया व एवेनफील्ड भ्रष्टाचार मामलों में जारी स्थायी गिरफ्तारी वारंट रद कर दिया। कोर्ट ने 50-50 हजार के बांड पर दोनों की जमानत मंजूर कर ली।

हुसैन (बाएं) और हसन। फाइल

दोनों भाइयों ने इसके बाद अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट मांगी। कोर्ट ने शुक्रवार तक सुनवाई स्थगित कर दी। ब्रिटेन की नागरिकता हासिल हासिल कर चुके दोनों भाइयों को 2018 में नवाज शरीफ, बहन मरयम व बहनोई मुहम्मद सफदर के साथ मुकदमा दायर हुआ था।

****

कोचिंग इकाई के रूप में और व्यक्तिगत रूप से रिषभ पंत को बल्लेबाजी करते हुए देखना सुखद था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वह लंबे समय बाद बल्लेबाजी कर रहे हैं।
— प्रवीण आम्रे, सहायक कोच, दिल्ली कैपिटल्स

स्टिमक बोले, हमारा ध्यान क्वालीफाइंग के तीसरे चरण पर

भुवनेश्वर, प्रेट्र : भारतीय फुटबाल टीम के मुख्य कोच इगोर स्टिमक ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ विश्व कप क्वालीफाइंग मैच में स्पष्ट मानसिकता के साथ उतरेगी और उनका ध्यान पहली बार क्वालीफायर्स के तीसरे चरण में जगह बनाने पर है। स्टिमक ने कहा कि हम इन मैचों में जीत हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम अभी बहुत अधिक समीकरणों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।

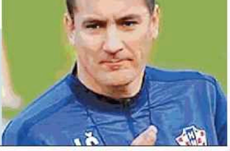

एक नजर में

आइएनए सोलर ने एलएसजी के साथ की साझेदारी

नई दिल्ली : इंसोलेशन एनर्जी लिमिटेड (आइएनए सोलर) ने घोषणा की है कि उनकी कंपनी आइपीएल 2024 में लखनऊ सुपरजायंट्स (एलएसजी) के साथ आधिकारिक सोलर पार्टनर के रूप में जुड़ी है। सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह एक रणनीतिक साझेदारी आगामी वर्ष में बहुत कारगर साबित होगी। आइएनए सोलर और एलएसजी के बीच साझेदारी का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक द्वारा लखनऊ में किया गया। (वि)

भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम की चौथी जीत

नई दिल्ली : मगुंटा साई और देबराज बेहरा के अर्धशतकों की मदद से भारतीय दृष्टिबाधित पुरुष टीम ने गुरुवार को चौथे टी-20 क्रिकेट मैच में श्रीलंका को आठ विकेट से पराजित किया। श्रीलंका की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में सात विकेट पर 142 रन ही बना पाई। भारत ने 40 गेंद शेष रहते हुए लक्ष्य हासिल किया। मगुंटा ने 42 गेंद पर 50 रन जबकि देबराज ने 29 गेंद पर 54 रन बनाए। भारत ने इस जीत से पांच मैच की सीरीज में 4-0 से बढ़त हासिल कर ली है। (प्रेट्र)

शरत सिंगापुर स्मैश के क्वार्टर फाइनल में

सिंगापुर: शरत कमल ने गुरुवार को यहां सिंगापुर स्मैश में मिस्र के दुनिया के 22वें नंबर के खिलाड़ी उमर अस्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। शरत ने स्लोवेनिया के विश्व में 13वें नंबर के खिलाड़ी डार्को जोर्गिक को हराने के एक दिन बाद इस प्रतियोगिता में अस्सर पर 11-4, 11-8, 12-10 से आसान जीत दर्ज की। क्वालीफायर के जरिए मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाले शरत क्वार्टर फाइनल में 10 बार के चैंपियन फेलिक्स लेब्रन से भिड़ेंगे। (प्रेट्र)

कोको गफ क्वार्टर फाइनल में

इंडियन वेल्स: एम्मा नवारो ने इंडियन वेल्स ओपन के चौथे दौर में दूसरी वरीयता प्राप्त आस्ट्रेलियन ओपन चैंपियन अरीना सबालेंका को 6-3, 3-6, 6-2 से हराकर अपने कैरियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वह करियर में चौथी बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं और 1000 श्रेणी के टूर्नामेंट में पहली बार वह अंतिम आठ में खेलेंगी। वहीं कोको गफ ने 20वें जन्मदिन पर एलिसे मर्टेंस को 6-0, 6-2 से हराकर दूसरी बार क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। (एपी)

मुंबई 42वीं बार बना रणजी चैंपियन

फाइनल में विदर्भ को 169 रन से किया पराजित, मुंबई की टीम ने खत्म किया आठ साल का खिताबी सूखा

नई दिल्ली, जेएनएन : रणजी ट्राफी की सबसे सफल टीम मुंबई ने आठ वर्षों का सूखा खत्म करते हुए गुरुवार को विदर्भ को 169 रन से हराकर रिकार्ड 42वीं बार रणजी ट्राफी का खिताब जीता। टूर्नामेंट के इतिहास में 90 में से 48वीं बार मुंबई की टीम फाइनल में पहुंची थी। वानखेड़े स्टेडियम पर खेले गए फाइनल का नतीजा लगभग उसी समय तय हो गया था जब विदर्भ को 538 रन का असंभव सा लक्ष्य मिला था। इससे पहले मुंबई ने अंतिम बार रणजी ट्राफी खिताब 2015-16 सत्र में जीता था।

विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर (102) और हर्ष दुबे (65) ने हालांकि पूरे पहले सत्र में मुंबई के गेंदबाजों को परेशान किया। विदर्भ ने पांच विकेट पर 248 रन से आगे खेलना शुरू किया था और उसे 290 रन और चाहिए थे। विदर्भ की टीम 368 रन पर आउट हो गई। वाडकर ने इस साल पहला शतक जड़ने के साथ ही सत्र में 600 रन का आंकड़ा भी पार किया। वहीं दुबे ने प्रथम श्रेणी करियर में दूसरा अर्धशतक जमाया। दोनों ने 194 मिनट और 255 गेंद तक चली साझेदारी निभाई। दूसरे सत्र का खेल शुरू होने के कुछ देर बाद ही वाडकर को तनुष कोटियान ने आउट किया। कोटियान ने 95 रन देकर चार विकेट लिए। यह साझेदारी टूटने के बाद विदर्भ की हार पर लगभग मुहर लग गई। तुषार देशपांडे ने शार्ट गेंद पर दुबे को आउट किया। देशपांडे ने ही आदित्य सरवटे को भी पवेलियन भेजा। कोटियान ने यश ठाकुर के रूप में चौथा विकेट लिया। वहीं अपने करियर का अंतिम मैच खेल रहे धवन कुलकर्णी ने उमेश यादव का विकेट लेकर विदर्भ की पारी का पटाक्षेप किया। विदर्भ का ये तीसरा फाइनल था। इससे पहले, उसने दो बार फाइनल में जगह बनाई थी और दोनों बार ट्राफी जीती थी।

मुंबई को मिलेंगे पांच करोड़ की अतिरिक्त राशि : मुंबई क्रिकेट संघ ने 42वीं बार रणजी ट्राफी जीतने वाली टीम की पुरस्कार राशि दोगुनी कर दी है जिसका मतलब है की टीम को पांच करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मिलेगी। संघ के सचिव अजिंक्य नाइक ने कहा, एमसीए के अध्यक्ष अमोल काले और शीर्ष परिषद ने रणजी ट्राफी पुरस्कार राशि दोगुनी करने का निर्णय लिया है। मुंबई के लिए यह सत्र शानदार रहा है और उसने सात खिताब जीते। हमारी टीम कई प्रतियोगिताओं के नाकआउट चरण में पहुंची।

किसने कितनी बार जीता खिताब

42	मुंबई
8	कर्नाटक
7	दिल्ली
5	बड़ौदा
4	होल्कर
2	सौराष्ट्र, विदर्भ, बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, हैदराबाद, महाराष्ट्र, रेलवे
1	यूपी, पंजाब,हरियाणा, गुजरात, नवानगर, मप्र, वेस्टर्न इंडिया

संक्षिप्त स्कोर बोर्ड

मुंबई : 224 और 418
विदर्भ : 105 और 348
अक्षय वाडकर : 102, **करुण नायर :** 74, **तनुष** 4/95

ट्राफी जीतने के बाद मुंबई की टीम • प्रेट्र

रणजी ट्राफी जीतने के बाद अब आइपीएल पर ध्यान : रहाणे

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

मुंबई को 42वां रणजी खिताब जिताकर अब कप्तान अजिंक्य रहाणे का पूरा ध्यान आइपीएल पर है, जहां वह चेन्नई सुपरकिंग्स में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार हैं। रणजी ट्राफी फाइनल में विदर्भ को हराने के बाद विशेष बातचीत में उन्होंने अपनी जीत टीम के समर्थकों को समर्पित कर दी। साथ ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों को खेलने के लिए प्रेरित करने के लिए बीसीसीआइ को धन्यवाद किया।

मुंबई की जीत, समर्थकों की जीत है: 42वें खिताब की जीत को लेकर रहाणे ने कहा, 'आज का दिन हमारे लिए विशेष है। आज की जीत हमारे सभी समर्थकों की जीत है। हम विगत कुछ वर्षों से अच्छा खेल रहे थे, परंतु जीत नहीं पा रहे थे। टूर्नामेंट जितना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे ही फर्क पड़ता है। गत वर्ष हम केवल एक रन से क्वालीफाई नहीं कर सके थे, यह हमें सबसे अधिक चुभ रहा था। इस वर्ष हमने यही कोशिश की वातावरण अच्छा बनाएं, क्योंकि खिलाड़ी तो वही थे बस भरोसा बनाए रखना था यह हमारे लिए बहुत आवश्यक था। 42वीं बार इस खिताब को जीतकर हम गौरवान्वित हैं और यह हमारे सभी समर्थकों को समर्पित है।'

आज मैं जो हूं, घरेलू क्रिकेट के कारण ही हूं : मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा कि आज वह जो भी हैं घरेलू क्रिकेट के कारण ही हैं। उन्होंने कहा, 'आज मैं जो भी हूं वह घरेलू क्रिकेट की वजह से ही हूं। भारतीय टीम में मेरा चयन घरेलू क्रिकेट में लगातार पांच-छह वर्षों तक निरंतर प्रदर्शन करने के कारण ही हुआ था। बीसीसीआइ ने भी बहुत अच्छी चीज की है कि उन्होंने घरेलू क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को प्रेरित किया है।

अजिंक्य रहाणे • प्रेट्र

आइपीएल में खुलकर खेलूंगा : रणजी ट्राफी की जीत की खुशी के साथ अब रहाणे आइपीएल में अपनी टीम के साथ जुड़ने को तैयार हैं। आइपीएल को लेकर उन्होंने कहा, 'इस सत्र में मैंने अच्छी बल्लेबाजी की है, परंतु कई बार खिलाड़ियों के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अच्छी शाट खेलकर भी आउट हो जाता है। इससे उसके प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता। ट्राफी जीत की मुझे बहुत खुशी है। अब मेरा पूरा ध्यान आइपीएल पर होगा।

लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में, पीवी सिंधू हारीं

खेल डायरी

बर्मिंघम, प्रेट्र : भारत के लक्ष्य सेन दुनिया के नंबर तीन खिलाड़ी एंडर्स एंटोनसेन पर तीन गेम तक चले मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर गुरुवार को आल इंग्लैंड चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए, लेकिन देश की शीर्ष महिला सिंगल खिलाड़ी पीवी सिंधू को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा।

दुनिया के 18वें नंबर खिलाड़ी सेन दूसरा गेम गंवाने के बाद तीसरे गेम में 2-8 से पिछड़ रहे थे। सेन ने इसके बाद शानदार वापसी करते हुए विश्व चैंपियनशिप में तीन बार के पदक विजेता पर 24-22 11-21 21-14 से जीत दर्ज की। दो बार की ओलिंपिक पदक विजेता सिंधू ने शीर्ष रैंकिंग की खिलाड़ी के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया, लेकिन वह मुकाबले को 19-21, 11-21 से हार गईं।

भारत के मुक्केबाजी कोच डुने ने दिया त्यागपत्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : ओलिंपिक क्वालीफायर में भारतीय मुक्केबाजों के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पेरिस खेलों से चार महीने पहले हाई परफार्मेंस निदेशक (एचपीडी) बर्नार्ड डुने ने त्यागपत्र दे दिया है जबकि विदेशी कोच दिमित्री दिमित्रुक को जल्द ही पद से हटाए जाने की संभावना है। आयरलैंड के पूर्व मुक्केबाज डुने को अक्टूबर 2022 में एचपीडी के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने इटली से अपना त्यागपत्र भेज दिया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) ने स्थिति का आकलन करने के लिए शुक्रवार को कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है। बीएफआइ के महासचिव हेमंत कलिता ने बताया, 'बर्नार्ड अब टीम के साथ नहीं है। हमने कल एक कार्यकारी बैठक बुलाई है, जहां हम हर चीज का आकलन करेंगे।'

पैरा निशानेबाजी विश्व कप में खराब फ्लैश टारगेट से किरकरी

नई दिल्ली, प्रेट्र: भारत पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कुल 16 पदक जीतकर तीसरे स्थान पर रहा, लेकिन अंतिम दिन ट्रैप स्पर्धा में खराब फ्लैश टारगेट के इस्तेमाल से आयोजकों की काफी किरकरी हुई। डा. करणी सिंह रेंज में गुरुवार को संपन्न हुए इस आयोजन में 50 देशों के 250 से अधिक निशानेबाजों ने भाग लिया। फ्लैश टारगेट पर कारतूस टकराने के बाद गुलाबी रंग निकलता है, जिससे जूरी को निर्णय में आसानी होती है। खराब फ्लैश टारगेट से निर्णायक मंडल गुस्से में थे और उन्होंने सभी 'फ्लैश टारगेट' फेंकने वाली मशीनों को तुरंत खाली करने और मिट्टी के टारगेट को इस्तेमाल करने का निर्देश दिया। अंतरराष्ट्रीय जूरी 'गुस्से' में थी लेकिन उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की।

घरेलू टूर्नामेंट खेलने के कारण श्रेयस के फिर आएंगे अच्छे दिन

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

भारतीय मध्यक्रम बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के अच्छे दिन फिर से आने वाले हैं। 2023 के लिए जारी बीसीसीआइ की केंद्रीय अनुबंध की सूची में उनका नाम भले ही शामिल नहीं रहा हो, परंतु बोर्ड उन्हें शीघ्र इस सूची में शामिल कर सकता है। विदर्भ के विरुद्ध रणजी ट्राफी के फाइनल में मुंबई की ओर से खेलने के कारण उन्हें राहत मिल सकती है।

मैच के दौरान पीठ दर्द की समस्या के कारण वह चौथे और अंतिम दिन मैदान में नहीं उतर सके थे। फाइनल मैच की दूसरी पारी में उन्होंने महत्वपूर्ण 95 रन बनाए थे। साथ ही टीम के दूसरे शीर्ष स्कोरर भी रहे थे। पीठ दर्द की समस्या के कारण अभी वह आइपीएल की अपनी फ्रेंचाइज कोलकाता नाइटराइडर्स के साथ नहीं जुड़ सके हैं, परंतु मेडिकल सहायता लेने के बाद वह शीघ्र ही टीम के शिविर में शामिल हो जाएंगे।

श्रेयस अय्यर • फाइल फोटो, प्रेट्र

चेतावनी के बावजूद घरेलू क्रिकेट से दूरी नहीं आई थी बोर्ड को रास: 28 फरवरी को बीसीसीआइ ने केंद्रीय अनुबंध में शामिल 30 खिलाड़ियों की सूची जारी की थी, जिसमें श्रेयस अय्यर को शामिल नहीं किया गया था। इससे पहले मुंबई के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर के पास ग्रेड बी का अनुबंध था। इस संबंध में बीसीसीआइ की ओर से कहा गया था कि वार्षिक अनुबंध के लिए श्रेयस के नाम पर विचार नहीं किया गया। बोर्ड ने सिफारिश की थी कि जब भी कोई खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हो तब वह घरेलू क्रिकेट में खेलने को प्राथमिकता दे। बीसीसीआइ सचिव जय शाह ने भी केंद्रीय अनुबंधित खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में भाग नहीं लेने पर चेतावनी दी थी, परंतु श्रेयस ने इंग्लैंड के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच के बाद बाहर होने पर रणजी ट्राफी में खेलने में कोई रुचि नहीं दिखाई। इतना ही नहीं उन्होंने पीठ में दर्द की बात कहकर क्वार्टर फाइनल में खेलने से इन्कार कर दिया था, जबकि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी ने कहा था कि उसे श्रेयस की चोट को लेकर कोई जानकारी नहीं है।

लाहिरू थिरिमाने सड़क दुर्घटना में घायल

कोलंबो, प्रेट्र : श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर लाहिरू थिरिमाने सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं और उन्हें अनुराधापुरा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस 34 वर्षीय खिलाड़ी को मामूली चोट आई है और उन्हें अनुराधापुरा टीचिंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनुराधापुरा श्रीलंका का एक प्रमुख शहर है जो राष्ट्रीय राजधानी कोलंबो से 205 किलोमीटर दूर है। रिपोर्ट के अनुसार, 'पुलिस ने बताया कि थिरिमाने जिस कार से यात्रा कर रहे थे उसकी दूसरी दिशा से आ रही एक लारी से टक्कर हो गई। यह दुर्घटना सुबह हुई।' थिरिमाने ने 44 टेस्ट, 127 वनडे और 26 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

मुझे डोप टेस्ट में फंसाने की साजिश हो रही : विनेश फोगाट

जागरण संवाददाता, सोनीपत: पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआइ) के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर उन्हें डोप में फंसाने की साजिश का आरोप लगाया है। विनेश पर आरोप था कि वह पटियाला में हुए ओलिंपिक क्वालीफायर के ट्रायल के बाद बिना डोप टेस्ट दिए चली गई थी। वह डोप टेस्ट देने के बाद ही ट्रायल में उतरी थीं। विनेश ने पत्रकारों से बातचीत में ट्रायल के दौरान हंगामे के आरोपों को भी नकार दिया।

विनेश ने कहा कि उन्होंने ट्रायल में हंगामा नहीं किया था, बल्कि कमेटी के सदस्य ही खुद देर से पहुंचे थे। जानबूझकर कमेटी के सदस्य बात को घुमा रहे हैं और यह साजिश बृजभूषण शरण के इशारे पर हो रही है। उन्होंने कहा, जब मैं ट्रायल के लिए पहुंचीं तो चयन समिति ने कहा कि 53 किग्रा भार वर्ग में ट्रायल नहीं होगा। इसके बाद मैंने 50 किग्रा भार वर्ग में अपनी तैयारी शुरू कर दी, लेकिन इंतजार के बाद भी चयन समिति के सदस्य नहीं पहुंचे। देरी की वजह से अन्य पहलवान भी परेशान थीं। जब मैं समिति के सदस्यों के पास ट्रायल में देरी पर नाराजगी जताने गई तो मुझपर हंगामा करने के आरोप लगा दिए। विनेश ने बजरंग पूनिया की ट्रायल में हार पर कहा कि डेढ़ साल से मानसिक रूप से परेशान होने के कारण कुश्ती पर पूरा ध्यान नहीं दे पाए। उन्होंने केंद्र सरकार से भी अपील कि इस मामले में जल्द फैसला हो ताकि पहलवान कुश्ती पर ध्यान दे सकें।

उद्घाटन समारोह में दिखेगा 'बड़े मियां, छोटे मियां' का जलवा

काउंटडाउन 07 दिन शेष

विश्व कप की तरह मैच शुरू होने से पूर्व और पहली पारी के बाद प्रस्तुति देंगे अक्षय, टाइगर श्राफ, सोनू निगम और एआर रहमान

अभिषेक त्रिपाठी • नई दिल्ली

आइपीएल के 17वें सत्र की शुरुआत में अब केवल सात दिन शेष हैं। अगले शुक्रवार को चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में गत चैंपियन चेन्नई सुपरकिंग्स और रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच उद्घाटन मैच खेला जाएगा। इस मैच से पूर्व हर बार की तरह इस बार भी बालीवुड अभिनेता और गायक अपने प्रदर्शन से उद्घाटन समारोह में चार चांद लगाते नजर आएंगे, परंतु विशेष बात यह है कि यह कार्यक्रम दो चरण में आयोजित होगा। मैच की शुरुआत से पूर्व अक्षय कुमार और टाइगर श्राफ अपने आगामी फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' का प्रचार करते दिखेंगे, जबकि पहली पारी के बाद दिग्गज गायक सोनू निगम और आस्कर विजेता एआर रहमान अपनी प्रस्तुति से समां बांधते दिखेंगे। गत वर्ष अहमदाबाद में विश्व कप के दौरान भारत और पाकिस्तान के मैच से पूर्व और लंच काल इसी प्रकार कलाकारों ने प्रस्तुति दी थी।

आइपीएल के प्रचार में भी साथ दिखे टाइगर और अक्षय : आइपीएल के आगामी सत्र के लिए स्टार स्पोर्ट्स की ओर से बनाए गए प्रचार में भी अक्षय कुमार और टाइगर श्राफ साथ दिखे। दोनों अपनी आगामी फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की वेशभूषा में दिखे, जिसमें दोनों जांबाज सैनिक का किरदार निभा रहे हैं। वहीं, इस प्रचार में धौनी और कोहली के प्रशंसकों और दोनों के बीच होने वाली इस भिड़ंत को बड़े मियां, छोटे मियां की भिड़ंत के रूप में दिखाया गया है।

पिछले वर्ष अरिजीत, तमन्ना और रश्मिका ने बांधा था समां : आइपीएल के 16वें सत्र के उद्घाटन समारोह में पिछले वर्ष अरिजीत सिंह, तमन्नना भाटिया और रश्मिका मंधाना ने समां बांध दिया था। पहले पुलवामा हमला और फिर कोविड-19 के कारण चार वर्षों के बाद हुए इस भव्य समारोह से अहमदाबाद का नरेन्द्र मोदी स्टेडियम गूंज उठा था। पिछले वर्ष चेन्नई सुपरकिंग्स ने उद्घाटन मैच में 2022 की चैंपियन गुजरात टाइटंस के विरुद्ध उद्घाटन मैच खेला था।

रिषभ पंत की मानसिक दृढ़ता, इच्छाशक्ति जबरदस्त : पर्डीवाला

बेंगलुरु, प्रेट्र : रिषभ पंत को फिट होने में मदद करने वाले मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के खेल मेडिसिन सेंटर के निदेशक डा. दिनशा पर्डीवाला ने कहा, पंत की चोट बहुत गंभीर थी। रिकवरी प्रक्रिया के दौरान पंत का आत्मविश्वास देखकर हैरान रह गए। मैंने उनसे कहा कि 18 महीने लगेंगे तो उन्होंने कहा कि वह 12 महीने में कर दिखाएंगे।' और ऐसा ही हुआ भी।

अभ्यास करते रिषभ पंत • एक्स

डार्टमंड, एटलेटिको अंतिम आठ में

चैंपियंस लीग

डार्टमंड, एपी : जादोन सैंचो के शुरुआती गोल और मार्को रियूस के अंतिम क्षणों में आए गोल की मदद से डार्टमंड ने बुधवार को चैंपियंस लीग के अंतिम-16 के मैच में पीएसवी इंडोवेन को 2-0 से हराया। वहीं, एक अन्य मैच में एटलेटिको मैड्रिड ने इंटर मिलान को पेनाल्टी शूटआउट में हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। सैंचो ने मैच की शुरुआत के तीसरे मिनट में और रियूस ने स्टापेज टाइम के पांचवें मिनट में गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसके साथ ही डार्टमंड ने 3-1 के कुल स्कोर के साथ अंतिम-16 का मैच अपने नाम किया। इससे पहले लीग के पहले चरण में डार्टमंड और इंडोवेन ने 1-1 से ड्रा खेला था। 2013 में चैंपियंस लीग का फाइनल खेलने वाले डार्टमंड ने तीन वर्षों में पहली बार अंतिम आठ में जगह बनाई।

पेनाल्टी शूटआउट में जीता एटलेटिको मैड्रिड

मैड्रिड, एपी : एटलेटिको मैड्रिड ने पेनाल्टी शूटआउट में इंटर मिलान को 3-2 से हराकर चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पहले चरण में 1-2 से पिछड़ने वाला एटलेटिको मैड्रिड दूसरे चरण में इंटर मिलान के डिमार्को के एक गोल से पिछड़ गया था, परंतु ग्रीजमैन और डिपे के गोल के दम पर टीम ने बराबरी कर ली। इसके बाद पेनाल्टी शूटआउट में 3-2 से जीत दर्ज कर एटलेटिको ने जैन ओबलाक की शानदार गोलकीपिंग से मैच अपने नाम कर लिया।

राष्ट्रीय फलक

आइएस से जुड़े हथियार जब्ती मामले में पूरक आरोप पत्र दायर

नई दिल्ली, एएनआइ : राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) ने आतंकी संगठन आइएस से संबंधित पुणे हथियार और विस्फोटक जब्ती मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें चार और लोगों (मोहम्मद शाहनवाज आलम, रिजवान अली, अब्दुल्ला शेख और तल्हा लियाकत खान को)को आरोपित किया गया है। एक अन्य आरोपित शमील नचान के खिलाफ अतिरिक्त आरोप लगाए हैं, जो पहले दायर आरोपपत्र के सात आरोपितों में से एक है।

हथियारों, विस्फोटकों की जब्ती से संबंधित जुलाई 2023 के मामले में 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है। सभी आरोपित आइएस के सदस्य थे। सभी पुणे और उसके आसपास आतंक फैलाने के षड्यंत्र में शामिल रहे।

पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वाली देश की 100 जेलों को 'ईट राइट कैंपस' टैग

- इनमें तिहाड़ जेल, सेंट्रल जेल गया, माडर्न सेंट्रल जेल पंजाब शामिल
- 'ईट राइट कैंपस से प्रमाणित सबसे अधिक जेलों की संख्या उत्तर प्रदेश में

नई दिल्ली, प्रेट्र: देश की 100 जेलों को 'ईट राइट कैंपस' टैग दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआइ) ने कैदियों और जेल कर्मचारियों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने की पहल के तहत देश भर की लगभग 100 जेलों को ईट राइट कैंपस के रूप में प्रमाणित किया है। प्रमाणित जेलों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश से रही। उसके बाद पंजाब, बिहार और मध्य प्रदेश का स्थान रहा।

गुरुवार को जारी बयान के अनुसार इस पहल के तहत भारत की जिन प्रमुख जेलों को ईट राइट कैंपस टैग दिया गया है, जिनमें तिहाड़ जेल (दिल्ली), सेंट्रल जेल गया (बिहार), माडर्न सेंट्रल जेल (पंजाब), सेंट्रल जेल रीवा (मध्य प्रदेश) और कई अन्य जिले के मंडल कारागार शामिल हैं। इन जेलों ने एफएसएसएआइ के निर्धारित मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करके कैदियों की खाद्य सुरक्षा और भलाई को बढ़ावा देने के लिए अपने समर्पण का प्रदर्शन किया है।

ईट राइट कैंपस प्रमाणन के माध्यम से एफएसएसएआइ कैदियों और जेल कर्मचारियों सहित सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक पहुंच सुनिश्चित करना चाहता है। प्रतिभागी जेल परिसरों को चार प्रमुख मापदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक आडिट से गुजरना पड़ता है, जिसमें बुनियादी स्वच्छता मानदंड, स्वस्थ भोजन के प्रविधान सुनिश्चित करने के लिए कदम और स्थानीय और मौसमी भोजन के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयास शामिल हैं। जेलों के अलावा देशभर में 2,900 से अधिक कार्यस्थलों को भी ईट राइट कैंपस के रूप में मान्यता दी गई है।

बेंगलुरु में साइनबोर्डों पर कन्नड़ को मिल रही प्रमुखता

बेंगलुरु, प्रेट्र: बेंगलुरु में व्यवसायों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों के साइनबोर्डों में अब कन्नड़ भाषा को प्रमुखता मिल रही है। व्यवसायों व प्रतिष्ठानों के साइनबोर्डों में कन्नड़ के 60 प्रतिशत उपयोग को अनिवार्य करने वाला विधेयक फरवरी में कर्नाटक विधानसभा ने पारित किया गया था। सरकार ने कहा था कि इसका अनुपालन न करने पर व्यवसायों के लाइसेंस रद कर दिए जाएंगे। दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए शहर में कई स्थानों पर नियमों का पालन न करने वाले बोर्डों के स्थान पर अस्थायी बोर्ड या बैनर और पुराने बोर्डों को ढंकने वाले कपड़े या स्टिकर देखे जा सकते हैं। बृहत बेंगलुरु महानगरपालिका ने शहर में व्यवसायों व प्रतिष्ठानों के साइनबोर्ड में 60 प्रतिशत कन्नड़ के उपयोग के अनुपालन के लिए 28 फरवरी की समय सीमा तय की थी।

मेघालय पुलिस ने एचएनएलसी के हथियार व गोला-बारूद जब्त किए

- शिलांग के पंजाबी लेन इलाके में विस्फोट के मामले चार लोग गिरफ्तार

शिलांग, प्रेट्र: मेघालय पुलिस ने री भोई जिले में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) के हथियार और गोला-बारूद जब्त किए गए हैं। एचएनएलसी से जुड़े चार लोगों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पुलिस ने हथियार और गोला-बारूद बरामद किए हैं। इन चारों को पुलिस ने शिलांग के पंजाबी लेन इलाके में आइईडी विस्फोट के सिलसिले में गिरफ्तार किया था।

एसपी जगपाल धनोआ सिंह ने बताया कि बुधवार को री भोई जिले में एचएनएलसी के झंडे के साथ हथियार, जिलेटिन की छड़ें, विस्फोटक आदि बरामद किए गए। शनिवार रात पंजाबी लेन इलाके में हुए विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हुआ है। एसपी ने बताया कि सोमवार को गिरफ्तार किए गए चारों आरोपितों ने बांग्लादेश में बैठे आकाओं के निर्देश पर हमले को अंजाम दिया था। विस्फोट में शामिल होने के आरोप में रविवार रात हाइनीवट्रेप नेशनल यूथ फ्रंट के नेता सहित दो अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था। मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा ने पंजाबी लेन इलाके में हुए विस्फोट में शामिल आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था। उन्होंने कहा था कि इस हमले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

****

दैनिक जागरण
सप्तरंग
मनोरंजन की दुनिया का
शुक्रवार, 15 मार्च, 2024

राजनीति का रण सिनेमा में

चर्चा में

मैं अटल हूं में केंद्रीय भूमिका में पंकज त्रिपाठी
स्वातंत्र्य वीर सावरकर का पोस्टर
एक्सीडेंट आर कांस्पिरेसी- गोधरा का पोस्टर

एक हिंदुस्तानी को कश्मीर जाने के लिए परमिट चाहिए। वहां तिरंगा लहराना पाप है...ये पूरा देश अनुच्छेद 370 का विरोध करता है..., फिल्म मैं अटल हूं में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पात्र ने उपरोक्त कथन के जरिए भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। इसी पर आधारित फिल्म आर्टिकल 370 ने भी बाक्स आफिस पर अच्छा कारोबार किया। आज प्रदर्शित हो रही फिल्म बस्तर- द नक्सल स्टोरी में छत्तीसगढ़ में माओवादी उग्रवाद का मुद्दा उठाया गया है। यही नहीं, लोकसभा चुनावों की सरगर्मियों के मध्य प्रदर्शित होने वाली आगामी फिल्मों रजाकार, स्वातंत्र्य वीर सावरकर, एक्सीडेंट आर कांस्पिरेसी: गोधरा, द साबरमती रिपोर्ट व इमरजेंसी के केंद्र में हैं भारतीय राजनीति के अहम मुद्दे। चुनावी माहौल में इन फिल्मों को लेकर प्रियंका सिंह की पड़ताल...

आज प्रदर्शित हो रही बस्तर-द नक्सल स्टोरी फिल्म में छत्तीसगढ़ में सक्रिय माओवादी उग्रवाद का सच टटोलने का प्रयास किया गया है, जबकि वर्ष 1948 के हैदराबाद की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म रजाकार में भारत के तत्कालीन निजाम के शासन में हिंदुओं की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए भारतीय रियासतों के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल को नायक के तौर पर दर्शाए जाने की बात कही जा रही है। वहीं 22 मार्च को प्रदर्शित होने वाली फिल्म स्वातंत्र्य वीर सावरकर में भारतीय राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले वीर सावरकर की कहानी के माध्यम से राष्ट्रवाद को हवा देने का प्रयास है। इन फिल्मों को कुछ लोग खास एजेंडे को सामने रखने की कवायद बता रहे हैं। हालांकि फिल्मकार ऐसी किसी मंशा को खारिज करते हैं। सावरकर का पात्र निभा रहे रणदीप हुडा कहते हैं कि ऐसे नायकों की कहानियां राजनीतिक विरोध को नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प से लक्ष्य की ओर बढ़ने का उत्साह जगाती हैं। आगामी दिनों में सिख विरोधी दंगों पर आधारित फिल्में द डेल्ही फाइल्स और जेएनयू प्रदर्शित होंगी। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग में अयोध्या से लौटते कारसेवकों के जल जाने की घटना पर आधारित फिल्में रणवीर शौरी अभिनीत एक्सीडेंट और कांस्पिरेसी: गोधरा व विक्रांत मेसी अभिनीत द साबरमती रिपोर्ट भी प्रदर्शन की कतार में हैं। गौरतलब है कि इस वर्ष जनवरी में अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसके कुछ माह के भीतर ही राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कथित कारसेवकों की साबरमती ट्रेन में दर्दनाक मृत्यु की पड़ताल करती फिल्मों का आना मात्र संयोग नहीं। वास्तव में राजनीतिक मुद्दों की कहानी जब सही समय पर प्रदर्शित की जाती है तो दर्शक भी जुड़ते हैं।

चुनाव से जुड़ी पटकथा: चुनाव पूर्व राजनीतिक मुद्दों पर बनी फिल्मों का प्रदर्शन पहले भी होता रहा है। 2019 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले प्रदर्शित फिल्म उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय जवानों के बलिदान का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में घुसकर किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर थी। फिल्म का संवाद हाउ इज द जोश राजनीतिक रैलियों में जोश जगाने का माध्यम बन गया था। इस वर्ष की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक मैं अटल हूं से हुई। उसके बाद आर्टिकल 370 और बालाकोट एयरस्ट्राइक पर बनी फिल्म फाइटर, आपरेशन वैलेंटाइन प्रदर्शित हुईं। देश से जुड़े ये मुद्दे अहम हैं, पर अक्सर प्रोपेगेंडा फिल्में बताकर इनका विरोध किया जाता है।

सच दिखाने का कोई वक्त नहीं होता: बस्तर-द नक्सल स्टोरी फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह अपनी फिल्म को लेकर प्रोपेगेंडा का टैग झेल चुके हैं। बकौल विपुल, अगर लोग सोच रहे हैं कि चुनाव से पहले बस्तर फिल्म से किसी पार्टी को लाभ होगा तो यह अतार्किक है। क्या बस्तर में 76 जवान बलिदान नहीं हुए थे? नक्सली इलाकों में विकास कार्य बाधित किए जा रहे हैं। सच को दिखाने का कोई समय नहीं होता है। विषय इतना अहम है कि यह प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। पांच अगस्त, 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी करते हुए इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। इसकी कहानी निर्माता आदित्य धर ने फिल्म आर्टिकल 370 में दिखाई। उरी : द सर्जिकल स्ट्राइक का निर्देशन भी उन्होंने ही किया था। आदित्य कहते हैं कि भारतीय दर्शक बहुत स्मार्ट हैं। उन्हें पता होता है कि कौन-सी प्रोपेगेंडा फिल्म है और कौन नहीं। कश्मीर में जो दिक्कतें रही हैं, उसके मुख्य कारणों में से एक आर्टिकल 370 भी था। उसकी आड़ में अलगाववादी गलत चीजें करके भी बच जाते थे। मैं स्वयं कश्मीर से हूं। वहां के लोग शांति चाहते हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकी गतिविधियां कम हुई हैं। स्कूल बंद नहीं होते हैं, होटल खुल गए हैं, लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, इस दृष्टि से यह कहानी भारत के लिए अहम है। ऐसी कहानियां सामने आनी चाहिए।

फिल्म बस्तर-द नक्सल स्टोरी का दृश्य ● फोटो: जागरण आर्काइव

विवादों का साया भी रहा

इमरजेंसी में कंगना

आने वाले दिनों में कंगना रनोट भारतीय राजनीति में काले अध्याय आपातकाल पर फिल्म **इमरजेंसी** लेकर आ रही हैं। उनका लुक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मिलता-जुलता है। इससे पूर्व भी कुछ ऐसी फिल्में आईं जिनकी कथावस्तु के साथ ही राजनीतिज्ञों से साम्य के कारण विवाद खड़े हुए। कुछ प्रमुख फिल्मों की बात करें तो गुलजार निर्देशित आंधी पर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह कहकर प्रतिबंध लगा दिया था कि इससे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की छवि धूमिल होगी। यही हाल फिल्म किस्सा कुर्सी का भी रहा। इसके प्रिंट जला दिए गए थे। इंदु सरकार और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर विपक्ष ने विवाद खड़े किए थे।

दिल से

एक्शन में रंग जमाना है

फिल्म कट्टी बट्टी से हिंदी सिनेमा में कदम रखने वाली अभिनेत्री **मिथिला पालकर** भाषाओं की सीमा में नहीं बंधना चाहतीं। आगामी दिनों में वह तमिल फिल्म ओहो एंथन बेबी में नजर आएंगी। पहली तमिल फिल्म को लेकर उत्साहित मिथिला कहती हैं, 'दक्षिण भारतीय सिनेमा से मेरा रिश्ता तेलुगु फिल्म ओरि देवुड़ा करने के साथ ही जुड़ गया था, पर तमिल में यह पहला प्रोजेक्ट है। एक-दो महीने में हम शूटिंग शुरू कर देंगे। मेरी एक करीबी तमिल मित्र थी। उसके परिवार के साथ समय बिताने से मुझे थोड़ी-बहुत तमिल की समझ हो गई थी, पर फिल्म के संवादों में उच्चारण सही होना चाहिए। इसके लिए उच्चारण सीख रही हूं। संवादों को सुनकर मैं देवनागरी लिपि में लिख लेती हूं, ताकि सही उच्चारण कर सकूं।'

मिथिला अब नकारात्मक और स्याह भूमिका में अपने अभिनय के रंग दिखाना चाहती हैं। उनका कहना है, 'अधिकांश प्रोजेक्ट में मैंने आस-पड़ोस में दिखने वाली सामान्य लड़की की भूमिका निभाई है, पर अब ऐसी भूमिकाओं में स्वयं को आजमाना चाहती हूं, जिनका कलेवर मेरे वास्तविक जीवन से बिल्कुल अलग हो। नकारात्मक व स्याह भूमिकाओं में अपने अभिनय को परखना चाहती हूं। मुझे कोई साइकोलाजिकल थ्रिलर फिल्म करनी है। इसके अलावा मुझे एक्शन भी करना है।'

दीपेश पांडेय

मेरी बात

कुछ लोग नहीं तय कर सकते देश का मिजाज

किसी कलाकार, निर्देशक, निर्माता का एक बयान बालीवुड बायकाट (बहिष्कार) ट्रेंड को हवा दे सकता है। बीच में एक दौर ऐसा आया था, जब इंटरनेट मीडिया पर फिल्मों के बहिष्कार का ट्रेंड चल निकला था, पर अभिनेता **राजीव खंडेलवाल** ऐसे ट्रेंड हैशटैग को महत्व नहीं देते हैं। बालीवुड की झलक दिखाती डिज्नीप्लस हाटस्टार की वेब सीरीज शोटाइम में इन दिनों नजर आ रहे राजीव कहते हैं कि इंटरनेट मीडिया पर जो ट्रेंड चलते हैं, वे मेरे लिए मायने नहीं रखते हैं। जैसे ही आप उसे अहमियत देना आरंभ करते हैं, वह बड़ा ट्रेंड बन जाता है। मुझे आज तक वो लोग नहीं मिले, जो बायकाट बालीवुड या फिल्मों पर प्रतिबंध की बात सामने से करते हों। मुझे लगता है कि वास्तव में ये लोग होते ही नहीं हैं। हजार लोग जब किसी विषय पर बात करना शुरू करते हैं तो वो ट्रेंड होना शुरू होता है, लेकिन क्या वह आधे देश का मिजाज व सोच हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम जब बाहर निकलते हैं, देश-विदेश में लोगों से मिलते हैं तो हमेशा प्यार ही मिलता है। आज तक मुझे कोई नहीं मिला, जिसने कहा हो बायकाट बालीवुड।

स्मिता श्रीवास्तव

वर्ग पहेली-2574

बाएं से दाएं
1. गति देनेवाला, परिचालक (4)। 3. हल्का काला (3)। 7. राग का अभाव (3)। 9. प्रत्येक, विष्णु (2)। 11. दैत्य, जालिम इंसान (3)। 12. जो बोलने में अटकता हो (3)। 13. कन्नी काटना, बच कर निकलना (4)। 15. किसी को अपना बना लेना (4)। 17. पृथक, भिन्न (3)। 18. विपत्ति, दुर्भाग्य (3)। 19. लक्ष्मी, विष्णु की पत्नी (2)। 21. नीले रंग का रत्न (3)। 23. प्रभाव (3)। 24. पदार्थ का तत्वगत ज्ञान (4)।

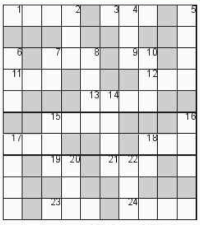
© Bird Features & Writing Agency

ऊपर से नीचे
2. कूड़ा करकट। (3)। 4. कारण, हेतु (3)। 5. बराबरी करना (4)। 6. पराजित करना (3)। 7. विधानसभा को संक्षेप में कहेंगे (2)। 8. सुगंध देना (4)। 10. स्थिर होना (3)। 14. खींचातानी (4)। 15. यदि (3)। 16. प्रभुता एवं महत्ता का नष्ट होने की स्थिति में आना (3)। 17. राजस्थान का एक ऐतिहासिक शहर (4)। 18. सांझ, संध्या (2)। 20. मन से संबद्ध (3)। 22. तरंग, कंप (3)।

कल का हल

	आ	क्ष	र			आ	न	न	
म			क्ष			य			रा
न			क	मा	सु	त			व
न	म	न		न			शा	म	त
		र्क		चि	त	व	न		
		स्व	तं	त्र	ता		दा		
वि	स	र्ग			र		र	सो	ई
प			स	र्व	ना	म			शा
त्ति			वां			द			न
	आ	ल	ग			द	र्प	ण	

जागरण सुडोकू-2574

	8	7		2				5
2			8		1	3	4	
		4		3		2		8
5			1	8		7		4
	6	1			3		8	
8				4				6
				1		9		
	1	8					6	
9			4		2			1

कल का हल

4	2	7	1	6	8	9	3	5
3	8	1	4	5	9	2	7	6
6	5	9	3	2	7	4	1	8
1	9	2	8	3	6	5	4	7
7	4	3	5	9	2	8	6	1
8	6	5	7	4	1	3	9	2
9	7	4	6	8	5	1	2	3
2	1	8	9	7	3	6	5	4
5	3	6	2	1	4	7	8	9

आज का भविष्यफल- 15 मार्च, 2024 शुक्रवार

के. ए. दुबे पद्मेश

आज की ग्रह स्थिति : फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष षष्ठी।
आज का राहुकाल : प्रात : 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजे तक।
आज का दिशाशूल : पश्चिम। पर्व एवं त्योहार : गोरूपणी षष्ठी। विशेष : मंगल कुंभ राशि में।

कल 16 मार्च, 2024 का पंचांग
कल का दिशाशूल : पूर्व
कल की भद्रा : रात्रि के 09 :39 बजे से 17 मार्च को प्रात : 09 :47 बजे तक।
विक्रम संवत 2080 शके 1945 उत्तरायण, दक्षिणगोल, शिशिर ऋतु फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तत्पश्चात अष्टमी रोहिणी नक्षत्र तत्पश्चात मृगसिरा नक्षत्र प्रीति योग तत्पश्चात आयुष्मान योग वृष में चंद्रमा तत्पश्चात मिथुन में।

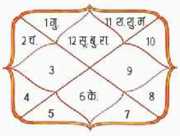

- **मेष :** मांगलिक या सांस्कृतिक उत्सव में हिस्सेदारी रहेगी।
- **वृष :** विरोधी परास्त होगा। संबंधित अधिकारी के कृपा पात्र होंगे।
- **मिथुन :** शासनसत्ता का सहयोग मिलेगा। धन व्यय होगा।
- **कर्क :** आर्थिक मामलों में सुधार होगा। शिक्षा के कारण चिंतित रहेंगे।
- **सिंह :** व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाणी पर संयम रखें।
- **कन्या :** कुछ पारिवारिक समस्या रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
- **तुला :** राजनैतिक महात्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। निजी सुख में वृद्धि होगी।
- **वृश्चिक :** ससुराल पक्ष का सहयोग मिलेगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
- **धनु :** अधीनस्थ कर्मचारी, मित्र या भाई से तनाव मिल सकता है।
- **मकर :** जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। वाणी पर संयम रखें।
- **कुंभ :** रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा। विरोधी परास्त होंगे।
- **मीन :** संतान के कारण चिंतित रहेंगे। मादक वस्तुएं घातक हो सकती हैं।

राष्ट्रीय फलक

न्यूज गैलरी

आरएसएस की प्रतिनिधि सभा की बैठक आज से नागपुर में

रांची: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीन दिनी प्रतिनिधि सभा की बैठक शुक्रवार से नागपुर में शुरू होगी। बैठक का शुभारंभ संघ के सरसंघचालक डा. मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले सुबह नौ बजे करेंगे। बैठक में सरकार्यवाह गत एक वर्ष का प्रतिवेदन रखेंगे। उसके बाद प्रांतों के कार्यवाह अपने-अपने यहां के कार्यों का वृत्त प्रस्तुत करेंगे। दोपहर में सह सरकार्यवाह मनमोहन वैद्य पत्रकारों से बात करेंगे। बैठक में सीएए के तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश व अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता दिलाने में संघ एवं समवैचारिक संगठनों के कार्यकर्ता कैसे मदद कर सकते हैं इस पर भी चर्चा होगी। (जासं)

पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर

पुणे : पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को महाराष्ट्र के पुणे शहर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह बुखार और सीने में संक्रमण से पीड़ित हैं। उनकी स्थिति स्थिर है। 89 वर्षीया प्रतिभा को बुधवार को भारती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के सर्वोच्च पद पर प्रतिभा 2007 से 2012 तक रहीं। देश की राष्ट्रपति बनने वाली वह पहली महिला हैं। (प्रेट्र)

मेक इन इंडिया पहल के तहत नौसेना को मिला 'बजरंग'

नई दिल्ली: केंद्र सरकार की "मेक इन इंडिया" पहल के तहत भारतीय नौसेना को गुरुवार को 25टी बोलार्ड पुल (बीपी) टग 'बजरंग' मिला। इससे नौसेना के जहाजों को अग्निशमन सहायता के साथ ही खोज व बचाव अभियान में भी मदद मिलेगी। बीपी टग, बजरंग को गुरुवार को कमोडोर वी. प्रवीण ने लांच किया। आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, तीन 25टी बीपी टग नौकाओं का निर्माण एवं वितरण के लिए शाफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड (एसएसपीएल) के साथ अनुबंध किया गया है। (आइएएनएस)

बिहार में खनन विभाग की टीम पर हमला, तीन सिपाही घायल

लखीसराय : बिहार के लखीसराय जिले में गुरुवार को बालू माफिया और उसके समर्थकों ने खनन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। इसमें जिला खनन सब इंस्पेक्टर सुनील कुमार भी चोटिल हुए। घायल सिपाही महेश कुमार, सलीन प्रसाद एवं शिवाजी यादव को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। (जासं)

गुरदासपुर जेल में सुरक्षा कर्मियों व कैदियों में भिड़ंत, गोलियां चलीं

जागरण संवाददाता, गुरदासपुर

- कैदियों ने की तोड़फोड़, थाना प्रभारी सहित छह पुलिस कर्मचारी जख्मी
- एडीजीपी ने कहा, एसडीएम करेंगे जांच, दोषी पर होगी कार्रवाई

गुरदासपुर केंद्रीय जेल में गुरुवार को सुरक्षा कर्मियों व कैदियों के बीच हुए टकराव में थाना प्रभारी समेत छह पुलिसकर्मी घायल हो गए। चार कैदी भी चोटिल हुए हैं। करीब आठ घंटे बाद स्थिति नियंत्रण में आ पाई। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं।

एडीजीपी (ला एंड आर्डर) गुरिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि तीन दिन पहले जेल कर्मचारियों व कैदियों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी। गुरुवार सुबह करीब 11 बजे फिर तकरार हुई, जिसने गंभीर रूप ले लिया। कैदियों की कुछ मांगें थीं, जिन्हें बैठकर सुलझा लिया गया है। तीन विशेषज्ञ डाक्टर बुलाकर उनका चेकअप कराया जाएगा। एसडीएम के नेतृत्व में मामले की जांच होगी, जो भी दोषी मिलेगा, उस पर कार्रवाई करेंगे।

एडीजीपी (जेल) अरुणपाल सिंह ने बताया कि जेल कर्मचारियों से कहासुनी के बाद कैदी पथराव करने लगे। कई कैदी और हवालाती जेल के पिछले हिस्से की छत पर चढ़ गए और वहां आग लगा दी। पुलिस लगातार लाउड स्पीकर पर कैदियों से नीचे आने की अपील करती रही। जेल परिसर से गोलियां चलने की आवाज आती रही। आंसू गैस के गोले भी दागे गए। स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने वज्र वाहन भी बुला लिए। स्थिति बिगड़ती देख गुरदासपुर, बटाला, पठानकोट, होशियारपुर व तरनतारन से भारी संख्या में पुलिसकर्मी जेल में तैनात किए गए। सीआरपीएफ की टुकड़ी भी बुलाई गई। पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियां, फायर ब्रिगेड व एंबुलेंस भी जेल के बाहर तैनात की गई है। घायलों में थाना धारीवाल के एसएचओ (थाना प्रभारी) मंदीप मंगोत्रा, जेल गार्द कर्मचारी जोधा सिंह, थाना काहनूवान में तैनात हवलदार बलजिंदर सिंह, पुलिस फोटोग्राफर जगदीप सिंह, एएसआइ नरेश कुमार और कांस्टेबल मनोज कुमार शामिल हैं। एसएसपी गुरदासपुर दयामा हरीश कुमार, डीसी डा. हिमांशु अग्रवाल, डीआइजी नरिंदर भार्गव, अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, एसएसपी बटाला अश्विनी गोटियाल, एसएसपी पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों के अलावा कई उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे।

लिव इन रिलेशनशिप पर भी लागू होगा धर्मांतरण निषेध कानून : हाई कोर्ट

जागरण संवाददाता, प्रयागराज

- अंतरधार्मिक जोड़े की सुरक्षा की मांग वाली याचिका खारिज

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उप्र धर्मांतरण निषेध कानून न केवल अलग-अलग धर्म के लोगों की शादी, बल्कि लिव-इन रिलेशनशिप पर भी लागू होता है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया अपनाकर धर्म परिवर्तन किए बिना अलग-अलग धर्मों का जोड़ा लिव-इन रिलेशनशिप में भी नहीं रह सकता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति रेनू अग्रवाल ने अंतरधार्मिक जोड़े की उस याचिका को खारिज करते हुए की है, जिसमें पुलिस सुरक्षा की मांग की गई थी।

अदालत ने कहा कि धर्म परिवर्तन न केवल विवाह के उद्देश्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह विवाह की प्रकृति के सभी रिश्तों में भी जरूरी है। प्रकरण में किसी भी याचिकाकर्ता ने अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं दिया है और आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराकर लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अधिनियम की धारा 3 (1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलतबयानी, बल का प्रयोग या गुमराह करके किसी अन्य व्यक्ति को सीधे या अन्यथा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित या परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करेगा। अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से कोई भी व्यक्ति इस तरह के रूपांतरण के लिए उकसाएगा, मनाएगा या साजिश नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि कानून में स्पष्ट है कि न केवल अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में बल्कि विवाह की प्रकृति के रिश्तों में भी धर्म परिवर्तन की आवश्यकता है। हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की से आर्य समाज मंदिर में शादी का पंजीकरण कराया और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। संबंधों में हस्तक्षेप पर रोक लगाने व पुलिस सुरक्षा की मांग में याचिका दायर की थी।

अपने आपको अनुशासन में रखने का रूहानी प्रशिक्षण है रोजा

मौलाना अरशद मदनी, अध्यक्ष, जमीयत उलमा-ए-हिंद

रमजान रहमतों व बरकतों का महीना है और सभी महीनों का सरदार कहलाता है। यह महीना हमें गरीबों की मदद करने का संदेश देता है। इस पाक महीने में अल्लाह अपने बंदों को हर नेकी का सवाब 70 गुना अधिक देता है। रोजा मन की गंदगी, तन के प्रदूषण और विचारों की दुर्गंध को इंसान से दूर करता है। केवल खाने-पीने पर अनुशासन का नाम ही रोजा नहीं, बल्कि अपने आपको अनुशासन में रखने का रूहानी प्रशिक्षण भी है। रोजा इंद्रियों को वश में करता है। रमजान और कुरान करीम का खास रिश्ता है। रमजान के पाक महीने में नाजिल हुआ कुरान हमें मानव उत्थान, आपसी सौहार्द, भाईचारे और अमन की शिक्षा देता है। रमजान में अल्लाह तआला की इबादत के साथ ही देश और देशवासियों के उत्थान की चिंता करें। साथ ही प्रेम, भाईचारा व सौहार्द का पैगाम आम करें। इंसानियत, हमदर्दी, गरीबों की सेवा, प्रेम, भाईचारा, सौहार्द को अपने आचार-विचार, व्यवहार में आत्मसात कर इस पाक महीने को सही मायनों को यथार्थ करें। रमजान में ज्यादा से ज्यादा इबादत कर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांगें और गरीबों की खूब मदद करें।

अश्लील सामग्री दिखाने पर 18 ओटीटी प्लेटफार्मों समेत 19 वेबसाइट ब्लाक

- चेतावनी के बाद भी न मानने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की कार्रवाई
- 10 एप और ओटीटी प्लेटफार्मों से जुड़े 57 इंटरनेट मीडिया खाते भी ब्लाक

नई दिल्ली, प्रेट्र: अश्लील सामग्री दिखाने पर ओवर द टाप (ओटीटी) प्लेटफार्म, वेबसाइटों और एप पर सरकार सख्त हो गई है। बार-बार चेतावनी के बावजूद अश्लील सामग्री दिखाने और प्रकाशित करने पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 18 ओटीटी प्लेटफार्म और उनसे जुड़े इंटरनेट मीडिया खातों को ब्लाक कर दिया है। इनमें से एक एप को गूगल प्ले स्टोर से एक करोड़ से अधिक बार और दो अन्य को 50 लाख से ज्यादा डाउनलोड किया गया था।

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि देश में 18 ओटीटी प्लेटफार्म, 19 वेबसाइट, 10 एप और उनसे जुड़े 57 इंटरनेट मीडिया खातों को ब्लाक किया गया है। ब्लाक किए गए प्लेटफार्मों में ड्रीम फिल्म्स, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, ट्रि फ्लिक्स, एक्स प्राइम, निओन एक्स वीआइपी, बेशर्म, हंटर्स, रैबिट, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, चिकूफ्लिक्स, हाट शाट्स वीआइपी, फुगी और प्राइम प्ले शामिल हैं। इन प्लेटफार्मों पर दिखाए जाने वाली अधिकांश सामग्री अश्लील व महिलाओं को अपमानजनक रूप से चित्रित करने वाली पाई गई। साथ ही ये प्लेटफार्म दर्शकों को आकर्षित करने के लिए इंटरनेट मीडिया खातों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे में अन्य मंत्रालयों, सरकारी विभागों, मीडिया व मनोरंजन, बाल-महिला अधिकारों के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श कर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के प्रविधान के तहत इन्हें ब्लाक करने का निर्णय लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्लेटफार्मों को रचनात्मक अभिव्यक्ति की आड़ में अश्लीलता और दुर्व्यवहार का प्रचार नहीं करना चाहिए।

बिहार में प्रोफेसर पर भड़के मंत्री, वीडियो प्रसारित

जागरण संवाददाता, बिहारशरीफ : बिहार में नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित किसान कालेज में बुधवार को सांसद निधि मद से पानी के टैंकरों को हरी झंडी दिखाने पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार कालेज के एक प्रोफेसर द्वारा गले लगाने की कोशिश पर भड़क गए। मंत्री श्रवण कुमार ने प्रोफेसर से कहा, क्या आप समधी मिलन करने आए हैं? प्रोफेसर ने माफी मांगी, पर मंत्री जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। मंत्री ने कहा, तुम प्रोफेसर के लायक नहीं हो। अब पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। हालांकि, दैनिक जागरण प्रसारित वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मंत्री का यह व्यवहार देखकर प्रोफेसर वहां से चले गए। दरअसल, किसान कालेज के वनस्पति विज्ञान के एचओडी प्रो. सुधीर रंजन गुलाब का फूल भेंटकर अतिथियों का स्वागत कर रहे थे। इसी क्रम में उन्होंने मंत्री श्रवण कुमार को गुलाब भेंट किया और उन्हें गले लगाने की कोशिश की।

अदालतों पर बोझ बढ़ा रहे नकारा और लापरवाह अधिकारी : कोर्ट

विधि संवाददाता, शिमला

- लंबित मामलों पर की टिप्पणी, कहा- ऐसे अधिकारी कोर्ट के आदेश की राह देखते हैं

हिमाचल प्रदेश में हाई कोर्ट ने अदालतों में मामलों के लंबित पड़े रहने के लिए सरकारी अफसरों की लापरवाही व अयोग्यता को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने कहा, ऐसे अधिकारी अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेने के बजाय कोर्ट के आदेश की राह देखते रहते हैं, जिस कारण जनता को कोर्ट का रुख करने पर मजबूर होना पड़ता है। नकारा व लापरवाह अधिकारी अदालती आदेशों का पालन समय पर न कर अदालतों का बोझ बढ़ा रहे हैं।

न्यायाधीश संदीप शर्मा ने तहसीलदार आनी को एडीएम मंडी की ओर से दिए आदेश पर एक वर्ष तक अमल न करने को गंभीरता से लेते हुए उक्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, आए दिन अदालतों में लंबित मामलों को लेकर टीका टिप्पणियां होती रहती हैं, परंतु आज तक किसी ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि लापरवाह और अयोग्य अधिकारियों की वजह से कोर्ट में मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोर्ट ने इन आदेशों की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भेजने का आदेश भी दिया।

ये है मामला: एडीएम कोर्ट ने 22 दिसंबर, 2022 को तहसीलदार आनी को आदेश दिया था कि वह एक महिला को जारी आय प्रमाणपत्र को दोबारा सत्यापित करें। सत्यापन सात मई, 2022 तक किया जाना था, पर आज तक तहसीलदार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस कारण प्रार्थी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। कोर्ट ने तहसीलदार को आदेश दिया कि वह दो दिन में एडीएम मंडी के आदेश का पालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश करें।

उत्तराखंड में करोड़ों की धोखाधड़ी में सीएम का पूर्व निजी सचिव गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, देहरादून : पंजाब और हरिद्वार के दवा कारोबारियों को उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में दवा आपूर्ति का ई-टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव प्रकाश चंद्र उपाध्याय उर्फ पीसी उपाध्याय को पुलिस ने बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। उपाध्याय और उनके सहयोगियों के विरुद्ध दून की नगर कोतवाली में करोड़ों की धोखाधड़ी के चार मुकदमे दर्ज हैं। यही नहीं, आरोपितों पर उत्तर प्रदेश व राजस्थान में भी करोड़ों की धोखाधड़ी के मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे ही दूसरे मामले में पीसी उपाध्याय के मुख्य सहयोगी सौरभ वत्स को 1.15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राजस्थान पुलिस ने बुधवार देर रात भीलवाड़ा से गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपित सौरभ वत्स को बी-वारंट पर देहरादून लाने की तैयारी कर रही है।

****

जलवायु परिवर्तन के खतरों पर लाखों छात्रों ने किया प्रदर्शन

2019 में आज ही के दिन दुनिया में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्कूल हड़ताल का आयोजन किया गया था। इसमें 125 देशों के लगभग 14 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया। हड़ताल का आह्वान पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने किया था। इस प्रदर्शन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा।

अमेरिका में पहले इंटरनेट डोमेन का नाम पंजीकृत किया गया

1985 में आज ही के दिन अमेरिका में दुनिया का पहला इंटरनेट डोमेन सिमबालिक डाटकाम पंजीकृत किया गया था। इसे अमेरिकी साफ्टवेयर कंपनी सिमबालिक आइएनसी ने विकसित किया था। वर्तमान में दुनिया में इंटरनेट पर एक अरब से अधिक डोमेन कार्यरत हैं। सिमबालिक डाटकाम आज भी सक्रिय है।

भटावड़ेकर को देश की पहली मोशन पिक्चर बनाने का श्रेय

हरिश्चंद्र सखाराम भटावड़ेकर (सावे दादा) का जन्म 1868 में आज ही बंबई (अब मुंबई) में हुआ था। पेशे से फोटोग्राफर सावे दादा 1896 में बंबई में प्रदर्शित ल्यूमियर ब्रदर्स की फिल्म देखने पहुंचे और इससे प्रभावित होकर सिनेमा बनाने की ठानी। इसके बाद इंग्लैंड से कैमरा मंगवाकर भारत की पहली मोशन पिक्चर (चलचित्र) द रेसलर्स बनाई। एक कुश्ती मैच की रिकार्डिंग होने की वजह से इसे फिल्म नहीं माना जाता। इसके बाद कई अन्य घटनाओं को भी चलचित्र का रूप दिया। 20 फरवरी, 1958 को उनका निधन हो गया।

हवा, पानी, धरती पर चलेगा मानव रहित हाइब्रिड वाहन

आइआइटी जोधपुर ने किया विकसित, पक्षी एहिंगास की एक प्रजाति से ली गई प्रेरणा

रोबोटिक्स पर हुए छठे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया गया

नेशनल डेस्क, जोधपुर

आइआइटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान) जोधपुर के शोधकर्ताओं ने एक हाइब्रिड मानव रहित वाहन का प्रोटोटाइप तैयार किया है, जो धरती, हवा, पानी के नीचे एक साथ चल सकेगा। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह एक मजबूत नियंत्रण प्रणाली होगी। यह समुद्र तटों, नदियों या पानी के नीचे होने वाले कटाव और तेल रिसाव का मैप तैयार किया जा सकता है।

इन वाहनों को चलाने वाली एक सुदृढ़ गणितीय प्रणाली विकसित करके यह शोध उन्हें सक्षम व कुशल बनाने में मदद करेगा। लाइफगार्ड बचाव प्रयासों और यहां तक कि पानी के नीचे और हवाई फोटोग्राफी जैसे उनके कार्यों पर बेहतर ढंग से लागू होगा। रोबोटिक्स को लेकर हुए छठे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इसे प्रस्तुत किया गया है। शोध में शामिल आइआइटी जोधपुर के डा. जयंत कुमार मोहंता और उनके शोध विद्वान जय खत्री, आइआइटी कानपुर के प्रोफेसर संदीप गुप्ता व आइआइटी पलक्कड़ के प्रोफेसर संतकुमार मोहन के अनुसार टीम ने इस प्रणाली को पक्षी एहिंगास की एक प्रजाति से प्रेरणा लेकर विकसित किया है, जो जमीन और पानी के नीचे दोनों पर चलने में सक्षम है। अनुसंधान टीम ने विभिन्न घटकों और वाटरप्रूफिंग से बना एक 3डी-मुद्रित प्रोटोटाइप बनाया है। रिमोट कंट्रोल (आरसी) ट्रांसमिशन का उपयोग कर हवाई, पानी की सतह और पानी के नीचे पैंतरेबाजी के लिए प्रोटोटाइप का परीक्षण किया गया है। आइआइटी, जोधपुर के सहायक प्रोफेसर डा. जयंत कुमार मोहंता बताते हैं, यह प्रोटोटाइप सतह पर एक जहाज की तरह चल सकता है, हवा में उड़ सकता है और यदि कोई वस्तु पानी में डूबी हुई है तो उसका भी पता लगा सकता है।

इन वाहनों को चलाने वाली सुदृढ़ गणितीय प्रणाली को किया गया विकसित

प्रोटोटाइप। फाइल

15 मिनट उड़ सकता है और आठ घंटे पानी के भीतर रह सकता है

डिजाइन किया हुआ प्रोटोटाइप लगभग 15 मिनट तक उड़ सकता है। इसके अलावा लगभग 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है। यह तकनीक फिलहाल अमेरिका और चीन जैसे बहुत कम देशों के पास है। भारत में पहली बार स्वदेशी उत्पाद विकसित किया जा रहा है।

युद्धाभ्यास में भी उपयोगी

- हाइब्रिड वाहन छह युद्धाभ्यास करने में सक्षम है।
- हवा से पानी के अंदर गोता लगाना
- पानी के अंदर से हवा में उड़ान भरना
- हवा से पानी की सतह पर उतरना
- पानी की सतह से पानी के अंदर गोता लगाना
- पानी के अंदर से सतह पर आना
- पानी की सतह से उतारना

प्रोटोटाइप से माडल तैयार करते वक्त यह तय करना पड़ेगा कि हाइब्रिड वाहन लड़खड़ाए नहीं। हमने एक मजबूत बैकस्टेपिंग नियंत्रण का प्रस्ताव रखा ताकि रोबोट बाधाओं व गड़बड़ी के बावजूद स्वतंत्र रूप से आगे बढ़े। परीक्षणों से पता चलता है कि यह बैकस्टेपिंग नियंत्रण अनिश्चितता के समय में बेहतर प्रदर्शन करता है, जिससे यह एक शक्तिशाली रूप से निर्मित संरचना बन जाती है।

- डा. जयंत मोहंता, आइआइटी जोधपुर

जर्मनी ने तैयार की रोबोट कार

जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में कैंपस फ्रीसिटी परियोजना के अंतर्गत चालक रहित रोबोट कार 'सिटी बोट' पेश की गई है। शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को ध्यान में रखकर यह रोबोट कार डिजाइन की गई है। यात्री परिवहन के साथ इसे मालवाहक कार के रूप में भी डिजाइन किया जा रहा है। यह पूरी तरह से इको फ्रैंडली है। एपी

इधर-उधर की

फीस के बदले बिल्ली का चित्र मांग रहा पुस्तकालय

वाशिंगटन, एजेंसी: पुस्तकालय से किताबें लेकर उसे खो देने या क्षतिग्रस्त करने वालों से जुर्माने के तौर पर अक्सर नकद राशि वसूली जाती है, लेकिन अमेरिका का एक पुस्तकालय वार्सेस्टर लाइब्रेरी पैसों के बदले बिल्ली का चित्र मांग रहा है। दरअसल, पुस्तकालय ने कार्यक्रम की घोषणा की है। पुस्तकालय से किताब लेकर उसे खो देने का जुर्माना नकदी के स्थान पर बिल्ली का चित्र जमा करने से माफ होगा। पुस्तकालय प्रबंधन ने कहा कि इसका उद्देश्य उन लोगों की मदद करना है, जो जुर्माने का भुगतान नहीं कर सकते। महीने के पहले पांच दिनों में 400 खातों को जुर्माने से मुक्त कर दिया गया।

भुगतान न कर पाने वालों की मदद के लिए उठाया कदम ● इंटरनेट मीडिया

दो से तीन सप्ताह में पूरी तरह से ठीक होगी सोरायसिस

सुमेश ठाकुर, चंडीगढ़

- सोरायसिस ठीक होने के साथ नहीं बचेगा चमड़ी पर दाग
- पेटेंट मंजूरी के बाद अब क्लीनिकल ट्रायल का इंतजार, जल्द उपलब्ध होगी मार्केट में

शरीर के किसी भी हिस्से पर सोरायसिस की परेशानी है, तो वह दो से तीन सप्ताह में ठीक हो जाएगा। दो से तीन सप्ताह में सोरायसिस से होने वाली खुजली और जख्म का अंत होगा और उसके बाद चमड़ी पर कोई निशान नहीं बचेगा। पंजाब यूनिवर्सिटी के फार्मास्यूटिकल विभाग में तैनात असिस्टेंट प्रोफेसर डा. वंदिता कक्कड़ ने इसकी दवा तैयार की है। डा. वंदिता ने आठ वर्ष के शोध के बाद सफेद हल्दी और एलोवीरा के मिश्रण से सोरायसिस के इलाज में सफलता पाई है। पीयू में डा. वंदिता ने दवा पर शोध किया, जिसकी सफलता के बाद भारत सरकार से भी पेटेंट को मंजूरी मिल चुकी है। अब यह दवा क्लीनिकल ट्रायल के लिए तैयार है। ट्रायल सफल होने के बाद इसे मार्केट में उतारा जा सकेगा।

डा. वंदिता ने बताया कि सोरायसिस के लिए कोई उपयुक्त इलाज नहीं था, जो भी दवा मार्केट में उपलब्ध है उनसे कई बार चमड़ी पर साइड इफेक्ट होते हैं।

सोरायसिस। फाइल

इससे चमड़ी पीली हो जाती है या फिर सोरायसिस के स्थान पर सफेद या काले रंग का दाग रह जाता था। शोध में सफेद हल्दी का इस्तेमाल किया है। सफेद हल्दी का इस्तेमाल सोरायसिस का जख्म ठीक होने के बाद कोई दाग नहीं छोड़ेगा और इससे चमड़ी भी पीली नहीं होगी।

क्लीनिकल ट्रायल के लिए इंतजार में पंजाब यूनिवर्सिटी

केंद्र सरकार से पेटेंट को मंजूरी मिलने के बाद अब क्लीनिकल ट्रायल के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी प्रयास कर रही है। ट्रायल पीयू की लैब में संभव नहीं है। पीजीआइ जैसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान में जाकर ही इसका ट्रायल हो सकता है। दवा के तौर पर इस्तेमाल से पहले इसे कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया गया है, जिसका परिणाम सफल रहा है।

क्रीम के उपयोग से चेहरे की झाइयों के लिए भी उपयोगी

डा. वंदिता ने बताया कि शोध से तैयार प्रोडक्ट को ब्यूटी प्रोडक्ट तैयार करने वाली कंपनियों ने इस्तेमाल किया है। ब्यूटी प्रोडक्ट ने इससे चेहरे पर इस्तेमाल होने वाली क्रीम को तैयार किया है जिससे झाइयां से निजात मिली है। ब्यूटी प्रोडक्ट में शोध से तैयार पदार्थ का थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है।

हर रोज सात-आठ घंटे से कम सोने से डायबिटीज का खतरा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली: महानगरीय जीवन में बहुत लोग अक्सर देर रात तक कामकाज में व्यस्त रहते हैं। इस बीच विदेश में हुए एक शोध में यह बात सामने आई है कि प्रतिदिन दो घंटे कम सोने से 16 प्रतिशत व चार-पांच घंटे कम सोने पर डायबिटीज होने का 41 प्रतिशत जोखिम रहता है। इसलिए प्रतिदिन सात, आठ घंटे से कम नींद लेने से डायबिटीज की बीमारी हो सकती है। दिल्ली के डाक्टर इस शोध को देश के लोगों को भी सचेत करने वाला बता रहे हैं।

पीएसआरआइ अस्पताल के पल्मोनरी व स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डा. जीसी खिलनानी ने कहा कि भारत में बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं।। डायबिटीज हृदय, मस्तिष्क व किडनी की बीमारी का एक बड़ा कारण होता। सामान्य तौर पर डायबिटीज का कारण खराब खानपान, मोटापा, व्यायाम नहीं करना माना जाता है।

हल्दी में पाए जाने करक्यूमिन से आंत में बढ़ जाते हैं लाभकारी बैक्टीरिया

अनुसंधान

हल्दी में करक्यूमिन की अच्छी मात्रा मिलती है, जो एंटी इंफ्लामेट्री कंपाउंड है। ये खास कंपाउंड शरीर में संक्रमण या क्रोनिक इंफ्लामेशन को कम कर सकता है। शोधकर्ताओं ने हल्दी में पाए जाने वाले करक्यूमिन को आंत में लाभकारी बैक्टीरिया को बढ़ाने वाला पाया है। शोधकर्ताओं ने कहा चूहों पर किए गए प्रयोग में पाया गया कि इससे आंत की सूजन व पाचन से जुड़ी समस्याओं में सुधार हुआ। वेस्टर्न साओ पाउलो और साओ पाउलो स्टेट यूनिवर्सिटी (यूएनओईएसटीई) के शोधकर्ताओं का निष्कर्ष इंटरनेशनल जर्नल आफ फार्मास्यूटिक्स में हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

शोधकर्ताओं ने पाया कि दही जैसे आहार में आमतौर पर पाए जाने वाले प्रोबायोटिक लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया ने सामान्य चूहों की अपेक्षा बीमार चूहों में 25 प्रतिशत तक करक्यूमिन बढ़ा दिया। करक्यूमिन के इमल्सन वाले नैनोमैट्रिक अणु या नैनोइमल्शन को सूजनरोधी और एंटीआक्सीडेंट के रूप में जाना जाता है। शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्होंने नैनोइमल्शन के जरिये करक्यूमिन की क्षमता बढ़ाकर सूजन व पाचन संबंधी समस्याओं का उपचार करने में सफलता पाई। यूएनओईएसटीई में प्रोफेसर व शोध के लेखक लिजिएन क्रेटली विंकेल्सट्रोटर इलर ने कहा कि शोध में दो चरण शामिल थे। पहले में करक्यूमिन प्रदान करने के लिए नैनोइमल्शन का उत्पादन शामिल था। दूसरे चरण में इसकी स्थिरता, आकृति व भौतिक रासायनिक गुणों का मूल्यांकन किया गया। शोधकर्ताओं ने पहले चूहों को आंत में सूजन बढ़ाने वाली दवा इंडोमेथासिन दी। इसके बाद करक्यूमिन नैनोइमल्शन को मुंह द्वारा दिया। 14 दिन तक निगरानी के बाद विश्लेषण में पाया कि दवा के कारण हुआ आंतों की सूजन खत्म हो गई।

स्क्रीन शाट

परफार्मेंस से पहले तैयारी करना पसंद करती हैं मौनी

हालिया प्रदर्शित वेब सीरीज शो टाइम में अभिनेत्री की भूमिका में नजर आईं मौनी। Instagram (@imouniroy)

अपनी फिल्मों और अन्य प्रोजेक्ट्स के लिए कैमरे के सामने परफार्म करने के अलावा भी कलाकारों को कभी किसी अवार्ड शो के लिए तो कभी किसी अन्य समारोह के लिए परफार्म करना पड़ता है। कैमरे के सामने तो कट और रीटेक के विकल्प भी होते हैं, लेकिन लोगों के सामने परफार्म करते हुए गलती करने के मौके बहुत कम होते हैं। इसलिए ऐसे किसी भी परफार्मेंस से पहले अभिनेत्री मौनी राय पूरी तैयारी करना पसंद करती हैं। मौनी 16 मार्च को जी टीवी पर प्रसारित होने जा रहे जी सिने अवार्ड्स में परफार्म करती नजर आएंगी। ऐसे में मौनी का कहना है, 'मेरी कोशिश होती है कि मैं परफार्मेंस की तैयारी में जितना समय दे सकती हूं, दूं। मैं स्टेज पर पूरी तैयारी के साथ जाना पसंद करती हूं। मैं ऐसी नहीं कि मैं एक दिन रिहर्सल के लिए जाऊं और बोल दूं कि मुझे सब आ गया है। हां, कभी-कभी आपके पास समय बिल्कुल नहीं होता तो जल्दी-जल्दी में स्टेज पर जाना पड़ता है। अन्यथा मैं परफार्मेंस से पहले चार-पांच दिन की तैयारी करती हूं।' वहीं अवार्ड्स के महत्व पर मौनी कहती हैं कि मेरे लिए दर्शकों का प्यार और सपोर्ट सबसे ज्यादा मायने रखता है। अवार्ड उसी चीज का एक भौतिक रूप होता है। अवार्ड मिलने या किसी अवार्ड के लिए नामित होने पर हम कलाकारों से ज्यादा प्रशंसक खुश होते हैं कि उनकी पसंदीदा अभिनेता या अभिनेत्री को अवार्ड मिल रहा है।

लाहौर 1947 के लिए प्रिटी जिंटा नहीं, मोना थी पहली पसंद

सिनेमा जगत में कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले फिल्म में किसी और कलाकार को कास्ट किया गया होता है और बाद में निर्माता उसकी जगह किसी दूसरे कलाकार के साथ शूटिंग शुरू कर देते हैं। थ्री इडियट्स व लाल सिंह चड्ढा फिल्मों की अभिनेत्री मोना सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बन रही फिल्म लाहौर 1947 में पहले सनी देओल के साथ मोना को कास्ट किया गया था। फिर बाद में निर्माताओं की तरफ से घोषणा की गई कि फिल्म में सनी के साथ अभिनेत्री प्रिटी जिंटा मुख्य भूमिका में होंगी। मोना के नाम को लेकर कोई घोषणा नहीं हुई। यह फिल्म अब प्रिटी के साथ बन रही है। मोना ने स्वयं इस फिल्म से हाथ पीछे खींचा या उन्हें फिल्म से हटाया गया, इसकी सही जानकारी तो फिलहाल निर्माताओं और मोना के बीच ही गुप्त है। इस बीच, अब खबरें आ रही हैं कि मोना ने राजकुमार हिरानी के साथ एक दूसरा प्रोजेक्ट साइन किया है। हिरानी अभिनेता विक्रांत मेस्सी के साथ डिजिटल प्लेटफार्म के लिए अपना पहला प्रोजेक्ट बना रहे हैं।

राजकुमार हिरानी के साथ एक और प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है मोना। Instagram (@monajsingh)

सगाई की अफवाहों के बीच मुनमुन ने लिखा, बेहतरीन जिंदगी जी रही हूं

इंटरनेट और डिजिटल मीडिया में सिनेमा और टीवी सितारों की व्यक्तिगत जिंदगी से जुड़ी कई अफवाहें सामने आती रहती हैं। धारावाहिक तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बबिता जी की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री मुनमुन दत्ता और टप्पू की भूमिका निभाने वाले अभिनेता राज अनादकट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ महीनों पहले दोनों के बीच रिलेशनशिप की खबरें आई थी। हाल में यह भी खबरें आई कि दोनों ने वड़ोदरा में सगाई कर ली है। जब बात ज्यादा बढ़ी तो मुनमुन को स्वयं इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ा। उन्होंने इस मामले में एक इंटरव्यू में कहा, 'यह खबर झूठी और हास्यास्पद है। इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं अपनी ऊर्जा ऐसी झूठी चीजों में नहीं बर्बाद करना चाहती हूं, जो बार-बार आती रहती हैं।' इसके अलावा उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में चाय की तस्वीर के साथ लिखा, 'फेक न्यूज तो चलती रहती है। लेकिन अपनी लड़कियों की गैंग के साथ शाम की चाय पीने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है।' इस कड़ी में उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें भी साझा की। इनके साथ उन्होंने लिखा, 'अपनी सबसे बेहतरीन जिंदगी जी रही हूं।'

मुनमुन ने साझा की अपनी न्यूयार्क की तस्वीर। Instagram (@mmoonstar)

कंटेंट निर्माण को फुर्सत के पलों का ही काम मानते हैं कार्तिकेय

शनि देव की भूमिका में फिर नजर आएंगे कार्तिकेय। Team Kartikey

इन दिनों इंस्टाग्राम पर कई फिल्म और टीवी कलाकार भी इंस्टाग्राम पर अपना कुछ न कुछ कंटेंट बनाकर साझा करते रहते हैं। हालांकि कलर्स चैनल के शो शिव शक्ति – तप त्याग तांडव में शनि देव की भूमिका निभा रहे अभिनेता कार्तिकेय मालवीय कंटेंट निर्माण को फुर्सत के पलों का काम मानते हैं। कार्तिकेय भले ही इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट करते हों, लेकिन वह बतौर अभिनेता ही पहचान बनाना चाहते हैं। वह कहते हैं कि मैं मम्मी के कहने पर कंटेंट बना लेता हूं, क्योंकि उनका कहना है कि प्रशंसकों के बीच सक्रिय रहने के लिए दिखते रहो। जब कंटेंट क्रिएटर्स खुद को एक्टर कहते हैं, तो वह मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं अभिनय के करियर में खुश और संतुष्ट हूं। शिव शक्ति शो से जब से जुड़ा हूं, मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया है। इस शो में कार्तिकेय एक बार फिर शनि देव की भूमिका में होंगे।

इससे पहले वह कर्मफल दाता शनि धारावाहिक में युवा शनि देव की भूमिका निभा चुके हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि यह रोल उस शो से अलग है। कर्मफल दाता बनने से पहले शनि कैसे थे, इसमें वह दिखाया जाएगा। इस किरदार के लिए तैयार होने में डेढ़ घंटे लग जाते हैं। जो टीका मैं शो में लगाता हूं, वह रोज बनाया जाता है। इस बार आंखों में लेंस भी पहना है, जो चुभने लग जाता है। लेकिन जैसे ही मैं सेट पर पहुंचता हूं, तो केवल किरदार में डूब जाता हूं।

जब बात में दम हो, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती : सारा

सात सवाल

अभिनेत्री सारा अली खान के लिए यह साल काफी खास है। आज (15 मार्च) उनकी फिल्म मर्डर मुबारक डिजिटल प्लेटफार्म नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित हो रही है। वहीं अगले सप्ताह 21 मार्च को फिल्म ए वतन मेरे वतन अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित होगी। ए वतन मेरे वतन फिल्म स्वतंत्रता सेनानी ऊषा मेहता की जिंदगी से प्रेरित है, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से कांग्रेस रेडियो चलाया था। पेश है सारा अली खान से फिल्म को लेकर बातचीत के अंश...

फिल्म ए वतन मेरे वतन में स्वतंत्रता सेनानी ऊषा मेहता की भूमिका में हैं सारा ● @saraalikhan95 (इंस्टाग्राम)

● आपकी दो फिल्में एक ही सप्ताह के अंतराल पर प्रदर्शित हो रही हैं। क्या दोनों की शूटिंग भी आपने आस-पास की थी?

-हां, ऐसा इसलिए कर पाई, क्योंकि मुझे अपने निर्देशकों पर भरोसा है। हालांकि यह आसान नहीं था। दोनों किरदार एकदूसरे से बेहद अलग हैं, लेकिन यह हम कलाकारों का काम है। हमारी कोशिश भी अलग-अलग काम करने की होती है। पिछले निभाए किरदारों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाई एनर्जी और चंचल स्वभाव वाले किरदार मैं निभा चुकी हूं। ऐसे में इन दोनों फिल्मों (मर्डर मुबारक और ए वतन मेरे वतन) के किरदारों के लिए निर्देशकों के दृष्टिकोण पर यकीन करना बहुत जरूरी था।

● आजादी की लड़ाई के दौर को जीने का अनुभव कैसा रहा?

-सच बताऊं तो मैं आभारी हूं कि मैं इस आजाद देश की नागरिक हूं और खुद को भारतवासी बुला सकती हूं। यह गर्व की बात है लेकिन इस गर्व के पीछे बहुत सारी कुर्बानियां छुपी हैं। उनके बारे में हमने बहुत पढ़ा और समझा है। कई कुर्बानियां गुमनामी के पन्नों में छुपकर रह गईं, जैसे ऊषा मेहता। मुझे लगता है कि बतौर कलाकार ऐसी कहानी दर्शकों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि वह भी देखें और समझें कि त्याग और बलिदान के कितने अलग-अलग रंग-रूप थे। यह सिर्फ महिला या पुरुष की कहानी नहीं है, यह रूहानी शक्ति की कहानी है। यह उस त्याग की कहानी है, जो हर चीज को भूलकर देशप्रेम को आगे रखकर चलने का आत्मविश्वास देती है। यह प्रेरणादायक कहानी आज भी प्रासंगिक है।

आपके भाई इब्राहिम अली खान भी फिल्मों में पदार्पण की तैयारी में हैं। इंडस्ट्री में आने की उनकी तैयारी आपसे कितनी अलग हैं?

तैयारी तो सबकी थोड़ी ऊपर-नीचे होती है, लेकिन सबका सफर अलग होता है। जरूरी बात यह है कि वो काम पर ध्यान दे। काम से परे भी अपनी जिंदगी को तवज्जो दे। एक अच्छा नियंत्रण और संतुलन अपने काम और जिंदगी में बनाकर रखे। अच्छा काम करते रहेंगे, तो उनके साथ भी अच्छा ही होगा।

● इस फिल्म ने आपकी देशप्रेम की भावना को कितना मजबूत किया?

-देशप्रेम की भावना तो मेरे अंदर है ही लेकिन इस किरदार को निभाते हुए मुझे समझ आया कि अपनी बातों को कहने के लिए मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं है, जब मुझे पता है कि जो मैं बोल रही हूं, वह सच है। जब आपकी बातों में दम होता है, तो चिल्लाने की जरूरत ही नहीं होती है। अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, मेहनत का फल मीठा होता है, यह सब मुहावरे हैं, लेकिन कैसे इन्हें अपनाकर जीवन जीना है, यह मैं सीख रही हूं।

● ऊषा मेहता बनने के लिए कैसी तैयारियां की?

-हर वक्त जो मैं जोक्स बोला करती हूं, वह भूलना पड़ा। हंसी-मजाक में चीजों को हल्के में नहीं लेना था। आपके अंदर जो स्पिरिट (भावना) है, उसे सम्मान देना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में अपने आप को यह याद दिलाते रहना बहुत जरूरी होता है कि आप सब कर सकते हैं।

● ऊषा मेहता की जिंदगी का सबसे कठिन पहलू आपको क्या लगा?

-हर चीज। सुबह साढ़े आठ बजे जब वह रेडियो का प्रसारण करती थीं, किसी भी समय कोई अंग्रेज उन्हें पकड़ सकता था। उन्हें इसके लिए फांसी की सजा दी जा सकती थी, क्योंकि वह जो काम कर रही थीं, वह अंग्रेजी शासन की नजर में गैरकानूनी था। उन्होंने कई तरह का बलिदान दिया। कभी शादी नहीं की। पिताजी का घर छोड़ दिया, क्योंकि उनकी जान को जोखिम में नहीं डालना चाहती थीं। वह बहुत बहादुर थीं।

● फिल्म में नारा है करो या मरो। असल जिंदगी में यह स्थिति आपके साथ कब आई?

-मुझे लगता है फिल्म अतरंगी रे के पहले आई थी। मुझे जल्दी मीडिया ने ज्यादा प्यार दे दिया था। फिर आई फिल्म लव आज कल, तो वो प्यार थोड़ा डावांडोल होने लगा। फिर लगा कि अब खुद को साबित करना है, तो उस वक्त करो या मरो जैसी ही स्थिति थी। फिल्म जरा हटके जरा बचके में यही नारा अपनाया।

(स्मिता श्रीवास्तव)

टिकट खरीद कर दें तोहफा : आमिर खान

गुरुवार को आमिर खान ने मनाई अपनी 59वीं जन्मतिथि ● मिडडे आकाइव

अभिनेता आमिर खान पिछले कई वर्षों से अपनी जन्मतिथि मुंबई में मीडिया के साथ भी मनाते आए हैं। इस वर्ष भी इस परंपरा को जारी रखते हुए उन्होंने अपनी 59वीं जन्मतिथि पर अपनी पूर्व पत्नी किरण राव, लापता लेडीज फिल्म की स्टारकास्ट स्पर्श श्रीवास्तव, प्रतिभा रांटा और नीताशी गोयल की उपस्थिति में मीडिया के साथ केक काटा और उनके साथ बातचीत की। आमिर फिल्म लापता लेडीज के निर्माता है। इस मौके पर आमिर ने बताया कि वह अपनी फिल्म सितारे जमीं पर की शूटिंग कर रहे हैं और वहां से कुछ घंटों की छुट्टी लेकर आए हैं। वहीं केक पर उनका नाम नहीं लिखा था, जिस पर मजाक में आमिर चुटकी लेना नहीं भूले कि आप लोगों ने कुछ लिखा ही नहीं, जैसे हैप्पी बर्थ डे आमिर वगैरह। आमिर ने आगे कहा, 'किरण की फिल्म लापता लेडीज को लेकर हमारे प्रोडक्शन हाउस को गर्व है। फिल्म अब भी थिएटर में चल रही है। अगर मुझे जन्मतिथि का तोहफा देना है, तो एक टिकट इस फिल्म की ले लीजिए। वही मेरा सबसे बड़ा तोहफा होगा।' आमिर फिलहाल तीन फिल्मों को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनमें सितारे जमीं पर, सनी देओल के साथ लाहौर 1947 और अपने बेटे जुनैद के साथ एक फिल्म शामिल है।

****